राष्ट्रीय संस्करण

शुभमन बोले, टीम में जगह को लेकर पृथ्वी से कोई मुकाबला नहीं

>>14

वर्ष 3 अंक 248

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शुक्रवार, 14 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

मरीजों की जिंदगी में खुशियों का उदय हैं डॉ. रवि कानन

नई दिल्ली: असम में कछार कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र चला रहे डॉ. रवि कानन को हाल ही में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। उनके अस्पताल में गरीबों के इलाज की बेहतर व्यवस्था है। अन्य राज्यों से भी लोग यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं।

(पेज-10)

जागरण विशेष

अनूठा है आइआइटी का मानवरहित सोलर यान

कानपुर : आइआइटी कानपुर के शोधार्थियों ने दुनिया का पहला एक्सीरॉन तकनीक वाला यूएवी बनाया है। 20 किग्रा पेलोड भारवर्ग में अब तक का सबसे अधिक उड़ान बैकअप इसकी खूबी है। नौसेना में हो सकता है इस्तेमाल।

(पेज-10)

दलों को बताना होगा दागियों को क्यों दिया टिकट

सुप्रीम निर्देश ▸ आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट देने पर पार्टियों को उसका ब्योरा देना होगा

कोर्ट ने कहा, उम्मीदवारों के चयन का पैमाना सिर्फ जीत नहीं हो सकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। दागियों के लिए संसद-विधानसभा के दरवाजे बंद करने के लिए राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजनीतिक दल जिस उम्मीदवार को टिकट देंगे, उसके आपराधिक रिकार्ड समेत सारा ब्योरा पार्टी की वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पर डालेंगे।

इतना ही नहीं शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि राजनीतिक दल यह भी बताएंगे कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों चुना? जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उन्हें क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया गया? अदालत ने कहा कि उम्मीदवार चयन का पैमाना सिर्फ जीतने की संभावना नहीं हो सकती। यह अहम फैसला है, क्योंकि राजनीतिक दल विशुद्ध रूप से जीतने की योग्यता पर ही उम्मीदवारों का चयन करते हैं।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और एस रवींद्र भट की पीठ ने यह आदेश 25 सितंबर, 2018 के पांच जजों की संविधान पीठ के फैसले का पूरी तरह अनुपालन नहीं किए जाने की शिकायत करने वाली अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए सुनाया है। पांच न्यायाधीशों की पीठ में जस्टिस नरीमन भी शामिल थे। भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने फैसले का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए एक अवमानना याचिका केंद्र सरकार के खिलाफ और एक चुनाव आयोग के खिलाफ दाखिल की थी।

अवमानना याचिका में कहा गया था कि केंद्र ने उस आदेश के मुताबिक अभी तक राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कानून नहीं बनाया। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के आपराधिक ब्योरे को पार्टी की वेबसाइट और अखबार व टीवी पर प्रकाशित प्रचारित करने के आदेश का पालन नहीं किया। चुनाव आयोग ने कहा था कि वह आदेश का पालन कर रहा है, लेकिन इससे राजनीति का अपराधीकरण पूरी तरह नहीं रुक रहा। कोर्ट ही राजनीतिक दलों को आदेश दे कि वे आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट न दें। कोर्ट ने इस बारे में चुनाव आयोग और याचिकाकर्ता से इस पर लगाम लगाने के लिए प्रस्ताव भी मांगा था।

राजनीति के शुद्धिकरण के लिए है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : कांग्रेस पेज>>4

फैसला

- राजनीति का अपराधीकरण रोकने को कोर्ट ने जारी किए दिशा-निर्देश
- चुनाव आयोग ने कहा था कि हम कर रहे आदेश का पालन फिर भी नहीं रुक रहा अपराधीकरण

“हमने पाया है कि राजनीतिक दल इस बात का कोई स्पष्टीकरण या जवाबदेही नहीं रखते कि उन्होंने पहले स्तर पर ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार का चयन क्यों किया? इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 129 और 142 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पार्टियों को दिशा-निर्देश जारी कर रहे हैं।

–सुप्रीम कोर्ट

चार आम चुनावों में दागियों की संख्या में हुई भारी बढ़ोतरी

वर्ष 2004	वर्ष 2009	वर्ष 2014	वर्ष 2019
24%	30%	34%	43%

उम्मीदवार का ब्योरा अपलोड करें

- कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अनिवार्य रूप से पार्टी की वेबसाइट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का ब्योरा अपलोड करें।
- दल बताएं कि उम्मीदवार के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला लंबित है? किस कोर्ट में लंबित है? क्या केस नंबर है और अदालत ने आरोप तय किए हैं कि नहीं?

पार्टियां चयन का कारण बताएंगी

- आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रत्याशी उतारते समय राजनीतिक दल उसके चयन का कारण भी बताएंगे।
- कारण बताते समय राजनीतिक दल उस उम्मीदवार की योग्यता, उपलब्धियां और मेरिट भी बताएंगे।
- उम्मीदवार के बारे में जानकारी क्षेत्रीय भाषा के एक स्थानीय अखबार और एक राष्ट्रीय अखबार में भी प्रकाशित की जाएगी।
- इसके अलावा पाटी के आफीशियल सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक और ट्वीटर पर भी डाली जाएगी।

साफ-सुथरी राजनीति और दैनिक जागरण की मुहिम

अपने धारदार समाचारीय अभियानों के साथ दैनिक जागरण देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने का सजग प्रहरी रहा है। बात चाहे न्यायिक सुधार की हो, राजनीतिक सुधार की हो या फिर लोगों के सरोकार से जुड़ी हो। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण से जब लोग आकुल होने लगे थे, तब दैनिक जागरण ने समाज में जागरूकता और तंत्र की तंद्रा तोड़ने के लिए अपनी कलम को हथियार बनाया। 'हम जागे जनतंत्र आगे' जनजागरण अभियान मार्च 2014 में शुरू हुआ। एक माह तक देश में चले इस अभियान में समाज की हर सोच-हर विचार को समाहित किया गया। एकमत से राय निकली कि न्यायपालिका की निगरानी के साथ आम लोगों की जागरूकता ही दलों को चुनावी मैदान में साफ-सुथरी छवि के प्रत्याशियों को उतारने के लिए विवश करेगी।

आदेश का पालन नहीं करना सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संबंधित दल उम्मीदवार के चयन के 72 घंटे के अंदर इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देंगे। अगर दल रिपोर्ट आयोग को देने में नाकाम रहते हैं, तो आयोग इसे कोर्ट के संज्ञान में लाएगा। इसका पालन नहीं करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट का गुरुवार को दिया गया आदेश 25 सितंबर 2018 के आदेश के अलावा है। उस आदेश में कोर्ट ने कहा था कि उम्मीदवार नामांकन भरते समय उसके साथ लगे फॉर्म में शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक रिकार्ड का पूरा ब्योरा देगा।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 4

नए जम्मू-कश्मीर में बजा पंचायत चुनाव का बिगुल

श्रीनगर : अनुच्छेद-370 हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली बार बड़ी चुनावी कवायद शुरू हो गई है। सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार को प्रदेश में रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंचों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। पांच मार्च से 20 मार्च तक आठ चरणों में मतदान होगा।

नेशनल न्यूज ▸ पृष्ठ 5

बैंकाक से कोलकाता आए दो लोगों में कोरोना के वायरस

कोलकाता : बैंकॉक से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे दो यात्री कोरोना वायरस के लिए की गई थर्मल स्क्रीनिंग में 'पॉजिटिव' पाए गए हैं। वहीं, बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसका खंडन किया है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 12

निर्यात बढ़ाने के लिए दर्जनभर क्षेत्रों पर ध्यान दे रही सरकार

नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिहाज से बेहतर स्थिति वाले दर्जन भर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनमें निर्यात के मजबूत स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

स्पोर्ट्स ▸ पृष्ठ 14

मनप्रीत सिंह बने एफआइएच के साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

लुसाने : राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) का साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इस तरह उनके लिए 2019 का साल यादगार रहा, जहां उनकी अगुआई में भारतीय टीम ने ओलंपिक में भी जगह बनाई।

शाह ने माना, भाजपा नेताओं को नहीं बोलनी चाहिए थी नफरत की भाषा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के कारणों पर रोशनी डालते हुए पहली बार माना कि कुछ पार्टी नेताओं की नफरत भरी भाषा की पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। भाजपा के रणनीतिकार शाह ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं को 'गोली मारो' और 'भारत-पाकिस्तान मैच' जैसे नफरत भरे भाषण नहीं देने चाहिए थे। बहरहाल, शाह ने कहा, भाजपा सिर्फ जीत या हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती है बल्कि चुनावों के मार्फत अपनी विचारधारा के प्रसार में भरोसा करती है।

अमित शाह ने गुरुवार को एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा, 'गोली मारो' और 'भारत- पाक मैच' जैसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे। हमारी पार्टी ने इस तरह के बयानों से खुद को अलग कर लिया है। फिर भी संभव है कि इस तरह की टिप्पणियों से पार्टी की हार हुई है। इसी के चलते पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी।

एक सवाल के जवाब में शाह ने स्वीकारा कि दिल्ली चुनावों पर उनका आकलन गलत साबित हुआ। उनका यह मानना कि विस चुनाव में भाजपा को 45 सीटें मिलेंगी एकदम गलत था। उन्होंने ईवीएम से करंट निकलने वाले अपने बयान का भी बचाव किया। शाह ने कहा कि भाजपा अब दिल्ली विधानसभा में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएगी।

आत्म मंथन

- गृह मंत्री ने स्वीकार किया-'देश के गद्दारों', और 'भारत-पाकिस्तान मैच' जैसे बयानों से हुआ नुकसान
- कहा, जीत-हार के लिए चुनाव नहीं लड़ती भाजपा, विचारधारा के विस्तार के लिए मैदान में उतरती है पार्टी

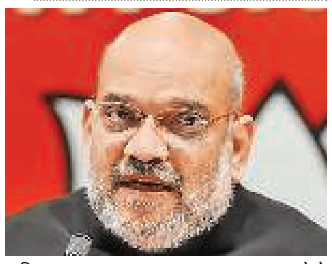

अमित शाह फाइल फोटो

ज्ञात हो, पिछले विधानसभा में सिर्फ तीन सीटें पाने वाली भाजपा को इस बार भी सिर्फ आठ सीटों से संतोष करना पड़ा है।

हिंसा को जायज नहीं ठहरा सकते : शाह ने जोर दिया कि चुनाव परिणाम संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर जनादेश नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों (गैर मुस्लिमों) को नागरिकता देने वाले कानून सीएए का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हमने धर्म के आधार पर कभी किसी से भेदभाव नहीं किया है। सीएए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएए की सिर्फ आलोचना न करें, बल्कि इस पर मेरिट पर चर्चा करें। सीएए ना तो मुसलमान विरोधी है और ना ही यह गैर-अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। सीएए पर जारी विरोध-प्रदर्शन पर कहा, हर किसी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

चर्चा के लिए तीन दिन में देंगे समय पेज>>3

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राज्यों के बीच होगी प्रतिस्पर्धा

नई दिल्ली : स्वच्छ शहरों की तर्ज पर अब साफ हवा को लेकर भी शहरों व राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इनमें देश के वो 102 शहर भी शामिल होंगे जिन्हें डब्ल्यूएचओ के सर्वे में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। बेहतर काम करने वाले राज्यों को ज्यादा पैसा मिलेगा। (पेज-3)

धर्मनिरपेक्ष सरकारें समय की जरूरत : प्रकाश सिंह बादल

अमृतसर : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि देश की मजबूती और विकास के लिए धर्मनिरपेक्ष सरकारें समय की जरूरत हैं क्योंकि कोई भी राष्ट्र सिर्फ धर्मनिरपेक्ष सरकारों से ही सुरक्षित रह सकता है। (पेज-4)

ग्रामीणों की हत्या के लिए प्रशासन जिम्मेदार : एनएचआरसी

बिलासपुर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अहम फैसले में कहा है कि सुकमा जिले के ग्राम कोंडासावली, कर्रेपारा और कामरागुडा गांवों में 2007 में सलवा जुडूम ने 95 घरों को जलाया। इस दौरान सात ग्रामीणों की जान चली गई। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। (पेज-7)

19 साल बाद लंदन से भारत लाया गया संजीव चावला

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पटियाला हाउस कोर्ट ने 12 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा
- क्रिकेट मैच फिक्सिंग में आरोपित है सटोरिया चावला

सन् 2000 में क्रिकेट मैच फिक्सिंग करने वाले दिल्ली के व्यवसायी और क्रिकेट जगत के दिल्ली के बड़े सटोरियों में शुमार संजीव चावला को आखिरकार 19 साल बाद दिल्ली पुलिस लंदन से दिल्ली ले आई। गुरुवार को चावला को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर 12 दिनों की रिमांड ली गई है। डीसीपी क्राइम ब्रांच डॉ. राम गोपाल नाइक के मुताबिक चावला को पूछताछ के लिए मुंबई समेत कई अन्य जगहों पर ले जाया जाएगा।

भारत-दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टेस्ट सीरीज में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए संजीव चावला ने दक्षिण अफ्रीकी टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोनिए को मैच फिक्स करने की एवज में 30 हजार डॉलर देने का ऑफर दिया था। चावला ने हैंसी क्रोनिए को खेल के तीसरे दिन मैच हार जाने को कहा था। दोनों की बात लीक हो जाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस कुछ कर पाती इससे पहले ही चावला लंदन भाग गया था। भारतीय पासपोर्ट रद हो जाने पर उसने 2005 में लंदन की नागरिकता ले ली थी। बीते जनवरी में लंदन हाई कोर्ट से चावला की अंतिम अपील खारिज हो जाने पर 20 जनवरी को उसे दिल्ली लाने की बात की गई थी, लेकिन कानूनी मामलों में देर हो गई। राम गोपाल नाइक व जांच अधिकारी केशव माथुर की टीम चावला को लाने लंदन गई थी।

लंदन से प्रत्यर्पित कराके भारत लाया गया मैच फिक्सिंग का आरोपी संजीव चावला गुरुवार को मीडिया के सामने मुंह छिपाते हुए। एएनआइ

1996 में पहली बार यूके गया था चावला पेज>>6

मुंबई हमले के अपराधियों को मिले सजा : भारत

नई दिल्ली : मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तानी अदालत ने टेरर फंडिंग के दो मामलों में भले ही 11 साल की सजा सुना दी है, लेकिन इससे भारत बहुत संतुष्ट नहीं है। भारत मानता है कि जमात उद दावा के मुखिया हाफिज के खिलाफ अदालत का फैसला सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ इमरान खान की सरकार की तरफ से इस बात के संकेत नहीं दिए गए हैं कि वह आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए वाकई गंभीर है। पाकिस्तान जब तक अपने यहां आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता है और मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कदम नहीं उठाता है, तब तक उसे गंभीर नहीं माना जा सकता। हाफिज सईद को सजा भी वित्तीय कार्यवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की बैठक को ध्यान में रख कर दी गई है। (पेज-13)

हाफिज सईद फाइल

भारतीय सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री

लंदन : ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक (39) को नया वित्त मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मतभेदों के चलते पाकिस्तानी मूल के साजिद जावीद के वित्त मंत्री पद से इस्तीफे के बाद सुनक की नियुक्ति हुई है। यूरोपीय यूनियन से हटे ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आने वाले महीनों में ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ ही दुनिया के देशों से अपने व्यापार संबंधों का नया ढांचा खड़ा करना है। सुनक को लेकर एक खास बात और...वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए भारत में जन्मे आलोक शर्मा (52) को वाणिज्य मंत्री बनाया गया है, वह मूल रूप से आगरा के हैं और उनका मूल पेशा बैंकर का है। (पेज-13)

ऋषि सुनक रायटर

पुस्तक पर संग्राम

नेहरू के मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर भिड़े विदेश मंत्री व इतिहासकार रामचंद्र गुहा, वीपी मेनन पर लिखी पुस्तक का हवाला देकर जयशंकर ने की टिप्पणी, गुहा को नागवार गुजरी

पटेल को कैबिनेट में नहीं चाहते थे नेहरू : जयशंकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्ष 1947 में आजादी मिलने के बाद पंडित जवाहर लाल नेहरू अपनी पहली कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रखना चाहते थे या नहीं, इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और इतिहासकार रामचंद्र गुहा आमने-सामने आ गए। इस मुद्दे पर इनके बीच ट्विटर वार छिड़ गया।

बता दें कि विदेश मंत्री ने एक दिन पहले ही एक पुस्तक का विमोचन किया। पटेल के सहायक रहे वरिष्ठ नौकरशाह वीपी मेनन के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर लिखी गई इस पुस्तक के आधार पर दावा किया कि नेहरू वर्ष 1947 की अपनी कैबिनेट में पटेल को शामिल नहीं करना चाहते थे। गुहा ने इसे एक गलत करार देते हुए नेहरू और पटेल के बीच हुए पत्राचार के उदाहरण से कहा कि पटेल को प्रथम प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखते थे।

गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत बुधवार को हुई थी। लेखिका नारायणी बसु की प्रथम गृह मंत्री पटेल के सहयोगी व आइएएस अधिकारी वीपी मेनन की जीवनी पर आधारित किताब का विमोचन विदेश मंत्री जयशंकर ने किया। जयशंकर ने इस विमोचन के बाद एक ट्वीट किया, 'इस पुस्तक से यह जानकारी मिली कि नेहरू पटेल को अपनी कैबिनेट में नहीं लेना चाहते थे। वर्ष 1947 की कैबिनेट की शुरुआती सूची में उनका नाम शामिल नहीं था। साफ तौर पर यह काफी चर्चा का विषय है। मुझे इस बात की खुशी है कि लेखिका ने इस बात को काफी ठोस तरीके से रखा है।' उनके इस ट्वीट का संदर्भ लेते हुए गुहा ने प्रोफेसर श्रीनाथ राघवन के आलेख को उद्धृत किया और लिखा, 'आधुनिक भारत के निर्माताओं के बारे में झूठी खबर (फेक न्यूज) फैलाने का काम विदेश मंत्री का नहीं है। यह काम भाजपा आइटी सेल पर छोड़ देना चाहिए।'

जयशंकर

रामचंद्र गुहा (फाइल)

आपने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं : अब बारी विदेश मंत्री जयशंकर की थी। उन्होंने पलटवार करते हुए ट्वीट किया, 'कुछ विदेश मंत्री किताबें पढ़ते हैं। कुछ प्रोफेसरों को भी इस अच्छी आदत को अपनाना चाहिए। मैंने कल जो पुस्तक रिलीज की है, उसकी अनुशंसा करता हूं।' बात यहीं खत्म नहीं हुई। गुहा ने पंडित नेहरू की तरफ से पटेल को लिखे पत्र का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पटेल उनकी सरकार के एक मजबूत स्तंभ हैं। गुहा ने लिखा, 'कोई इस पत्र को विदेश मंत्री को दिखा दो।' उन्होंने लिखा, 'विदेश मंत्री जी आपने जेएनयू से पीएचडी की है और निश्चित तौर पर आपने मुझसे ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। आप उन पुस्तकों को फिर पढ़ें।'

ट्वीट वार में जयराम भी कूदे : इसके बाद इन दोनों के ट्वीट वार में कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी कूद गए। उन्होंने नेहरू की तरफ से लार्ड माउंटबेटन को 19 जुलाई,1947 को लिखे पत्र का जिक्र किया जिसमें कैबिनेट की सूची में सबसे ऊपर सरदार पटेल का नाम था।

6449 हेक्टेयर भूमि का पंजीकरण हो चुका है दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग नीति के तहत। इस नीति के तहत 15 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है।

तैयारी ▶ अरविंद केजरीवाल रविवार को रामलीला मैदान में तीसरी बार लेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ

शपथ ग्रहण समारोह में नहीं दिखेंगे दूसरे राज्यों के नेता

दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं को निमंत्रण नहीं, जनता ही होगी वीआइपी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में रविवार को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली की जनता ही वीआइपी होगी। केजरीवाल के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, नेताओं व किसी भी वीआइपी को निमंत्रण नहीं देगी। यह जानकारी गुरुवार को पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने दी।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। केजरीवाल 16 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह दिल्ली केंद्रित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह उन लोगों के बीच शपथ लेंगे जिन्होंने उनके नेतृत्व में एक बार फिर से विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी ने 53 फीसद से ज्यादा वोट लेकर 62 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह दिल्ली की जनता की जीत है।

मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान में तैयारी चल रही है। प्रेट्र

पूरी दिल्ली के लोगों को शपथ ग्रहण समारोह में किया गया आमंत्रित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दिल्ली के लोगों को न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए 16 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में जरूर आना। उन्होंने यह न्योता ट्वीट करके दिया है। गुरुवार को उन्होंने ट्वीट किया कि दिल्लीवासियों, आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहा है। अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आना है।

जूनियर मफलरमैन होंगे केजरीवाल के मेहमान : मंगलवार को आम आदमी पार्टी अपनी जीत पर जश्न मना रही थी। वहीं, उसकी जीत में जूनियर मफलरमैन देशभर में टीवी स्क्रीन की सुर्खियां बटोर रहा था। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वेशभूषा में आया था। चंद मिनटों में ही इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह बच्चा माता-पिता के साथ पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलना चाहता था। अब केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में इस एक साल के बच्चे अव्यान तोमर को पार्टी ने आने का निमंत्रण दिया है। वह मयूर विहार के रहने वाले हैं। उनके पिता का नाम राहुल तोमर है। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर इस बात का एलान भी किया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि अनाउंसमेंटः बेबी मफलरमैन को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। तैयार हो जाओ जूनियर।

जिन सीटों पर पार्टी हारी, वहां जनता से संपर्क में रहें कार्यकर्ता : केजरीवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर हार की आम आदमी पार्टी ने की समीक्षा

▶ केजरीवाल के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक संपन्न

जनता के इस सकारात्मक रुख के बाद भी आम आदमी पार्टी आठ सीटें क्यों हार गई, इस पर पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर हुई हार की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को केजरीवाल ने निर्देश दिया कि जिन सीटों पर पार्टी हारी है, वहां लगातार जनता के संपर्क में रहा जाए। उनके काम और समस्याओं का भी तत्परता से समाधान हो। जनता से और करीबी संबंध स्थापित किए जाएं।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में केजरीवाल के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी मौजूद थे। इस दौरान प्रत्याशियों से हार के कारणों को विस्तार से जाना गया। इस दौरान सभी नेताओं ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि इतना काम करने के बाद भी आप 8 सीटों पर कैसे हार गई। जिन सीटों पर बहुत कम अंतर से हार हुई, उन पर विशेष बात हुई जिसमें लक्ष्मी नगर सबसे महत्वपूर्ण है। जहां पार्टी आठ सौ वोट से हार गई।

आम आदमी पार्टी बदरपुर, रोहिणी के अलावा यमुनापार की भी छह सीटें हार गई हैं। लक्ष्मीनगर, गांधी नगर, विश्वास नगर, रोहतास नगर करावल नगर व घोंडा शामिल हैं। इनमें से तीन सीटों पर आप के विधायक थे जो फिर से चुनाव लड़े और हार गए। इसमें घोंडा से श्रीदत्त शर्मा, लक्ष्मी नगर से नितिन त्यागी व रोहतास नगर से सरिता सिंह शामिल हैं।

कैबिनेट की शपथ के लिए राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल सहित पूरी कैबिनेट के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अनुमति के लिए भेजी गई फाइल मंजूरी के साथ सरकार के पास वापस आ गई है। इसके तहत रामलीला मैदान में रविवार को शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा।

उपराज्यपाल अनिल बैजल मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री पद की शपथ अरविंद केजरीवाल लेंगे। इनके अलावा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और राजेंद्र पाल गौतम मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये सभी पिछले कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों को लाए जाने की अटकलें चल रही थीं, मगर पार्टी ने इसे खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि जब पुराने मंत्री हमें अपने काम के दम पर चुनाव जिताकर लाए हैं, ऐसे में इन मंत्रियों को बदलने का सवाल ही नहीं उठता है।

विधानसभा का सत्र अगले सप्ताह : नवगठित दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र विधायकों को शपथ दिलाने के लिए अगले सप्ताह आयोजित होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार यह विशेष सत्र 18 और 19 फरवरी को आयोजित हो सकता है।

दिल्ली की सर्दी में गर्मी ने तोड़ा आठ साल का रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हवा के रुख में आए बदलाव के बाद दिल्ली की सर्दी में ही गर्मी का रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। गुरुवार को दिल्ली के अधिकतम तापमान ने आठ वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिन में लोगों को न केवल गर्म कपड़े उतारने पड़ गए, बल्कि धूप में तो उन्हें पसीना तक आ गया। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण अभी सुबह और शाम के समय तो ठंडक बरकरार रहेगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ठिठुरन वाली सर्दी पड़ने के आसार नहीं ही हैं।

गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का ही नहीं, बल्कि बीते आठ वर्षों के दौरान 13 फरवरी का सबसे अधिक तापमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा में नमी का स्तर 50 से 85 फीसद रहा। रिज क्षेत्र में तो अधिकतम 28.2 एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। तेज गर्म हवा चलेगी। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 और 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

फिर जोर पकड़ सकते हैं दिल्ली-हरियाणा के मुद्दे

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के साथ ही हरियाणा से जुड़े मुद्दे भी जोर पकड़ सकते हैं। केजरीवाल के शपथ लेते ही दिल्ली सरकार के लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा गर्मियों में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। इसके लिए केजरीवाल सरकार हरियाणा से ज्यादा पानी देने की मांग करेगी। यह मुद्दा लेकर दिल्ली सरकार अपने पिछले कार्यकाल में एनजीटी और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। फिलहाल हरियाणा, दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी प्रतिदिन दे रहा है, मगर गर्मियों में इतने पानी से दिल्ली की प्यास नहीं बुझती। दिल्ली सरकार 1169 क्यूसेक पानी प्रतिदिन दिए जाने की मांग कर रही है, जबकि हरियाणा सरकार दिल्ली से पानी की बकाया राशि 100 करोड़ रुपये की मांग कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार दिल्ली में प्रदूषित हो रही यमुना की सफाई पर भी जोर देगी।

राज्यों के बीच जल बंटवारे के दौरान यह तय हुआ था कि हरियाणा, दिल्ली को प्रतिदिन 719 क्यूसेक पानी देगा। इसके लिए दिल्ली को 120 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार को देने थे। 1995 में दिल्ली ने महज 20 करोड़ रुपये देकर पानी की आपूर्ति शुरू करवा ली। हरियाणा जब भी बकाया 100 करोड़ रुपये की मांग करता, तभी दिल्ली में कम पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठा दिया जाता। इसके अलावा 2017 से दिल्ली सरकार गर्मियों के दिनों में लगातार हरियाणा पर यह आरोप लगा रही है कि दिल्ली को तय मापदंड के अनुसार पानी नहीं मिल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो हरियाणा सरकार दिल्ली को 330 क्यूसेक बढ़ाकर 1049 क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने लगी, मगर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1169 क्यूसेक पानी की मांग करती रही।

फिलहाल दिल्ली सरकार की जलापूर्ति के मामले में दो शिकायतें हैं। एक-हरियाणा से आने वाला पानी 120 क्यूसेक कम आ रहा है। दो-जलापूर्ति प्रदूषित हो रही है। गत वर्ष गर्मियों में दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर दूषित जलापूर्ति का आरोप लगाया तो राज्य के सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गई, जिसमें लिखा था कि दिल्ली जल बोर्ड के जल शोधन संयंत्र 40 साल पुराने हैं। इनसे हरियाणा से आने वाले पानी को शोधित नहीं किया जाता। पुराने जल शोधन संयंत्रों से 200 क्यूसेक पानी प्रतिदिन बेकार होता है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार पर मंथन करेगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ प्रदेश भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को होगी बैठक, राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

▶ पार्टी मानती है आप के साथ अब सीधा है मुकाबला, मिशन 51 फीसद पर होगा जोर

विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली करारी हार की समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद अब दिल्ली के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके प्रत्येक सीट की समीक्षा करेंगे। शुक्रवार को इसे लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। उसके बाद चुनाव में जुड़े दूसरे राज्यों के सांसदों व अन्य नेताओं से भी चर्चा की जाएगी। समीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में अब कांग्रेस का जनाधार लगभग समाप्त हो गया है और आम आदमी पार्टी (आप) के साथ सीधा मुकाबला है। इसे ध्यान में रखकर 51 फीसद मत हासिल करने की रणनीति तैयार की जाएगी।

शुक्रवार को होने वाली बैठक में विधानसभा चुनाव के सभी प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी मंडलों व जिलों के अध्यक्ष और चुनाव से जुड़े अन्य नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रत्येक सीट को लेकर विस्तार से मंथन करके हार के कारणों की पड़ताल की जाएगी। नेताओं व कार्यकर्ताओं से यह जानने की कोशिश की जाएगी कि चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए मुद्दों को लेकर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया थी, स्थानीय स्तर पर क्या समीकरण थे, चुनाव प्रचार में क्या कमी थी और आखिर किन कारणों से मतदाता पार्टी से दूर हुए।

मीडिया से बात करते हुए दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि हार से निराशा जरूर हुई है, लेकिन हताश नहीं हैं। हार की समीक्षा करने के बाद अगले चुनावों की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि सीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं करने का फैसला सामूहिक था। दिल्ली में पहली बार यह प्रयोग किया था। इसकी भी समीक्षा होगी। उन्हें लगता है कि चेहरा घोषित करने से फायदा होता। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा कि दिल्ली में अब मुकाबला भाजपा व आप के बीच है। पिछले विस चुनाव में कांग्रेस को लगभग दस फीसद वोट मिले थे। इस बार वह पांच फीसद भी वोट नहीं ले सकी। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का भी भाजपा को नुकसान हुआ है। इसे ध्यान में रखकर 51 फीसद से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए पार्टी काम करेगी।

प्रदेश स्तर पर फेरबदल की सुगबुगाहट हुई तेज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद प्रदेश भाजपा में फेरबदल की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। संभव है कि समीक्षा बैठक के बाद संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब सबकी नजर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है। मनोज तिवारी को फिर से यह कुर्सी मिलेगी या फिर किसी अन्य नेता को दिल्ली की कमान सौंपी जाएगी।

पिछले वर्ष अगस्त में सदस्यता अभियान संपन्न हो गया था। दिल्ली में 17 लाख नए सदस्य बनाए गए हैं और दस लाख पुराने सदस्य हैं। सदस्यता अभियान समाप्त होने के बाद विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर संगठनात्मक चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

अब चुनाव संपन्न हो गया है और संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। भाजपा नेताओं का कहना है कि तय नियम के अनुसार बूथ समितियां गठित होने के बाद मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों का चुनाव होता है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है। संगठनात्मक चुनाव में काफी विलंब हो चुका है इसलिए संभव है कि सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई फैसला हो और उसके बाद जिला व मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए जाएं।

प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि उनकी जगह किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाए। नगर निगमों के चुनाव व लोकसभा में पार्टी उनके नेतृत्व में जीत हासिल की थी। ऐसे में संभव है कि दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को ध्यान में रखकर इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया जाए। इनके साथ ही सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व सांसद व राष्ट्रीय मंत्री महेश गिरी, मिजोरम के प्रभारी व पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री पवन शर्मा के नाम की भी चर्चा है।

सर्वोच्च न्यायालय का इन्कार, हाई कोर्ट पहुंचा गार्गी कॉलेज विवाद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गार्गी कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस संबंध में दायर याचिका में कोर्ट की निगरानी में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) से घटना की जांच कराने की मांग की गई है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी।

अधिवक्ता एमएल शर्मा की तरफ से दायर याचिका में मांग की गई कि घटना से जुड़े सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को संरक्षित रखा जाए और इस सुनियोजित आपराधिक साजिश में शामिल आरोपितों को गिरफ्तार किया जाए। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली चुनाव के दौरान राजनीतिक और आपराधिक साजिश रची गई और इस घटना के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप लगाया गया कि 6 फरवरी को पुलिस ने और प्रधानाचार्य ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की और न ही आरोपितों को गिरफ्तार किया।

मालूम हो कि छह फरवरी को गार्गी कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव के दौरान बाहर से आए लोगों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। छात्राओं का आरोप था कि पुलिस और कॉलेज प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। बाद में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी और बुधवार को 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया था।

दो और आरोपितों की पहचान हुई : गार्गी कॉलेज में तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव में अंतिम दिन बाहरी लोगों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने दो और आरोपितों की शिनाख्त कर ली है। इससे पहले बुधवार को पुलिस ने 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। आशंका है कि गिरफ्तार आरोपित दिल्ली-एनसीआर के किसी कॉलेज के छात्र हो सकते हैं।

रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने पर विरोध प्रदर्शन

रसोई गैस सिलेंडर का दाम बढ़ने पर महिलाओं ने शास्त्री भवन के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया। शास्त्री भवन स्थित पेट्रोलियम भवन में महिलाओं ने घुसने की कोशिश भी की, लेकिन बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ महिलाएं पोस्टर लेकर पहुंची थीं। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार को गरीब विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाला बताया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। दिल्ली में बुधवार को सिलेंडर के दाम में 144 .5 रुपये की वृद्धि हुई है। जागरण

दिल्ली में कांग्रेस फिर राम भरोसे

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद दिल्ली में कांग्रेस एक बार फिर से राम भरोसे हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों का इस्तीफा तो हार के अगले ही दिन स्वीकार कर लिया गया, लेकिन नए अध्यक्ष और प्रभारी को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। विडंबना यह भी कि जिन्हें अंतरिम प्रभारी बनाया गया है, वह दिल्ली की राजनीति का अनुभव ही नहीं रखते। इस बीच पार्टी के भीतर केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ भी आवाज उठने लगी है।

जनवरी 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को प्रदेश की कमान सौंपी गई तो पार्टी का ग्राफ बढ़ने लगा। यही वजह रही कि फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का जो मत फीसद घटकर नौ रह गया था, वो मई 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 22.5 फीसद पहुंच गया। पिछले साल 20 जुलाई को शीला दीक्षित की मौत के बाद तीन माह प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व विहीन रही तो पार्टी का ग्राफ फिर से नीचे आ गया। गत वर्ष 23 अक्टूबर को सुभाष चोपड़ा के हाथों में प्रदेश की कमान दी गई। तीन माह की अल्पावधि में उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन सियासी समीकरणों के चलते पार्टी का ग्राफ इस चुनाव में और नीचे गिरकर महज 4.1 फीसद पर पहुंच गया।

पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव परिणाम आने के 24 घंटों के अंदर प्रभारी और अध्यक्ष दोनों को हटा दिया हो। विचारणीय पहलू यह है कि आलाकमान ने हटाने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन नई नियुक्तियों पर विचार ही नहीं किया। दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो केंद्रीय नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिसके बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। जिन शक्ति सिंह गोहिल को अंतरिम प्रभारी के तौर पर दिल्ली का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, वह गुजरात के नेता हैं। वह दिल्ली की राजनीति से अनभिज्ञ रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक दिल्ली कांग्रेस में नए अध्यक्ष के तौर पर कोई उपयुक्त चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। अजय माकन, जयप्रकाश अग्रवाल एवं अरविंदर सिंह लवली को पार्टी पहले अवसर दे चुकी है। राजेश लिलोठिया, हारून यूसुफ, देवेंद्र यादव का कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा। महाबल मिश्रा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है।

मुझे दिल्ली के अतिरिक्त प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने की जानकारी बुधवार देर रात ही मिली। कई दिनों से स्वास्थ्य भी खराब चल रहा है। 18 या 20 को प्रभार संभालूंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाने की स्थिति में आ पाऊंगा।

-शक्ति सिंह गोहिल, अंतरिम प्रभारी, दिल्ली कांग्रेस

सलाह

सीबीएसई की चेयरपर्सन अनीता करवाल ने परीक्षार्थियों को चिट्ठी लिखकर दी सलाह, कहा- परीक्षा के दौरान विद्यार्थी अपने ऊपर हावी न होने दें तनाव

परीक्षार्थी चिंता से रहें दूर, करें कड़ी मेहनत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सीबीएसई की चेयरपर्सन अनीता करवाल ने कहा है कि बोर्ड के परीक्षार्थी ज्ञान और क्षमता के साथ आगे बढ़ें। वे चिंताओं को खत्म करें और कड़ी मेहनत कर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। परीक्षा के दौरान विद्यार्थी अपने ऊपर तनाव हावी न होने दें। इसलिए अंकों की दौड़ के बजाय अपने व्यक्तित्व को निखारने पर अधिक ध्यान दें। ये बातें उन्होंने चिट्ठी लिखकर बोर्ड परीक्षार्थियों से कहीं।

अनीता करवाल फाइल फोटो

गौरतलब है कि 15 फरवरी से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता में तनाव देखने को मिलता है। इस तनाव को दूर करने और बोर्ड परीक्षा के सही मायने समझाने के लिए करवाल ने छात्रों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं भी दी हैं। वह तीन साल से परीक्षा से पहले छात्र-छात्राओं के नाम चिट्ठी लिखती आ रही हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से छात्रों को परीक्षा को तनाव में न लेने की सलाह दी है। करवाल ने चिट्ठी में कई दिलचस्प और हौसला बढ़ाने वाली बातें लिखी हैं। अनीता ने बच्चों से कहा कि जीवन में कुछ भी करो, पर इतिहास बनाने से दूर रहना। उन्होंने छात्रों को पत्र के माध्यम से कहा कि परीक्षा में मिले अंक करियर नहीं तय करते हैं। कोई भी नियोक्ता स्कूल में मिले अंकों के बजाय यह जानना चाहेगा कि आप कठिन परिश्रम करते हैं या नहीं, रचनात्मक व्यक्ति हैं कि नहीं। वे आप में गहन सोच, समस्या सुलझाने की काबिलियत, अच्छा कम्युनिकेशन और सहयोग के कौशल को देखना चाहेंगे।

अपने पत्र में उन्होंने छात्रों को सुझाव दिया है कि विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए निश्चित तौर पर स्कूलिंग जरूरी होती है। जीवनपर्यंत सीखने और नैतिकता व कुशलता हासिल करने के लिए व्यक्तित्व का विकास कहीं अधिक जरूरी है। उन्होंने बताया कि वह अपने स्कूली दिनों में हमेशा अमेरिका को कोसती थीं, क्योंकि उनके फ्लोरा और फॉना अफ्रीका से बिल्कुल अलग थे। आखिर क्यों दुनिया एक जैसी और आसान नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वह अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों में पढ़ाई-लिखाई से बेहतर थीं। हालांकि बॉयोलॉजी उनका पसंदीदा विषय था, जिसे वह खूब पढ़ती थीं।

अनिता ने कहा कि स्कूल जाने और वहां पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ बोर्ड परीक्षा नहीं होता है। आज जब अपने स्कूल के दिनों को याद करती हूं तो पिकनिक में जाना, वार्षिकोत्सव व खेल समारोह, दोस्तों के साथ मस्ती याद आती है। वहीं पढ़ाई की धुंधली सी यादें हैं, जिनमें इतिहास की बहुत सारी तिथियां हैं जो अब बिलकुल याद नहीं हैं।

परीक्षा जीवन के सफर में मात्र एक पड़ाव : उन्होंने छात्रों को कहा कि आपने जीवन में कई पड़ाव पार किए हैं। जैसे घुटनों के बल चलते-चलते पैरों पर चलना सीखा, तुतला कर बोलने से लेकर साफ बोलना सीखा, दोस्त बनाने से लेकर टीम वर्क करना, पढ़ना, लिखना, खेलना, पेंट करना, गाना, इंटरनेट पर सर्च करना, खाना बनाना, बागवानी करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपनी संस्कृति को जानना और भी बहुत कुछ। यह सभी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। परीक्षा इन हजारों चीजों की सूची में से महज एक चीज है। यह उतना बड़ा हौवा नहीं है, जितना इसे बनाया जाता है। ये सिर्फ अपनी वास्तविक क्षमता ढूंढने के आपके सफर में एक मील का पत्थर है। आप यदि यह मान लें कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो यह मुश्किल नहीं है।

दिल्ली प्रभारी के बयान को एक एआइसीसी नेता ने बना लिया था नाक का सवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और प्रभारी पीसी चाको का इस्तीफा एक साथ स्वीकार होने के पीछे भी नाटकीय घटनाक्रम रहा है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी की पसंद रहे चाको को मंगलवार दोपहर चुनाव परिणाम स्पष्ट हो जाने के बाद ऊपर से इस्तीफा नहीं देने का निर्देश मिला था। चोपड़ा ने भी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भर की थी। लेकिन चाको के एक बयान से मामला पलट गया। दरअसल, मंगलवार शाम चाको ने दक्षिण भारत की मीडिया में पार्टी की हार के लिए चोपड़ा और एआइसीसी के एक वरिष्ठ नेता को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनका बयान बुधवार सुबह वहां के अखबारों में प्रमुखता से छपा। एआइसीसी के वरिष्ठ नेता ने इसे अपनी नाक का सवाल बना लिया। उन्होंने सोनिया से बात की और उनकी अनुमति मिलने पर चाको को इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया। चोपड़ा अपने इस्तीफे की पेशकश पहले ही कर चुके थे, लिहाजा, उसे भी स्वीकार कर लिया गया।

31 जनवरी से 11 फरवरी तक चले बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा में 38 घंटे 30 मिनट काम हुआ। इस दौरान 96 फीसद कामकाज हुआ। सदन की कार्यवाही में व्यवधान के कारण पांच घंटे 32 मिनट कामकाज नहीं हो सका, जबकि सदन में करीब चार घंटे तक अतिरिक्त कामकाज हुआ।

न्यूज गैलरी

डीजीसीए ने स्पाइस जेट के दो पायलटों को किया निलंबित

नई दिल्ली : घटना के करीब साढ़े तीन महीने बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार को स्पाइस जेट के दो पायलटों को साढ़े चार महीने के लिए निलंबित कर दिया। दोनों गत वर्ष 31 अक्टूबर को मेंगलुरु हवाईअड्डे पर बी-737 विमान की लैंडिंग के दौरान लापरवाही और एजलाइट क्षतिग्रस्त करने के दोषी पाए गए हैं। घटना के वक्त विमान दुबई से आ रहा था। डीजीसीए के दस्तावेज के अनुसार, 'जांच में पाया गया कि विमान ने सेंटरलाइन की बाईं तरफ स्पर्श किया और फिसलता चला गया। स्थिति को संभालने में क्रू ने देरी की। इसके कारण रनवे की तीन एजलाइट क्षतिग्रस्त हो गईं।' पायलटों की निलंबन अवधि की गणना घटना के दिन से ही की जाएगी। (प्रेट्र)

मद्रास हाई कोर्ट के नौ जजों को किया गया स्थायी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने नौ एडिशनल जजों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के मद्रास हाई कोर्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कोलेजियम ने बुधवार को जस्टिस पीटी आशा, एम. निर्मल कुमार, सुब्रमणियम प्रसाद, एन. आनंद वेंकटेश, जीके इलांतीरैयन, कृष्णन रामासामी, सी. सरवनन, बी. पुगलेंडी व संतिलकुमार राममूर्ति को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कोलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जज राहुल चतुर्वेदी को भी स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। न्यायिक अधिकारी आइ जसवंतराय वोरा, गीता गोपी, डॉ अशोक कुमार सी. जोशी और राजेंद्र एम. सरीन को पदोन्नति देकर गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। (प्रेट्र)

चारा घोटाले में सीबीआइ की अर्जी पर सुनवाई आज

नई दिल्ली : चारा घोटाले में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआइ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। देवघर ट्रेजरी घोटाले से जुड़े मामले में सजा की आधी अवधि खत्म होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में लालू की जमानत के आदेश दिए हैं। सीबीआइ ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो को वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत सात वर्ष और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत सात वर्ष की सजा हुई थी। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। यह मामला दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा है। वर्ष 1991-96 के दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने ट्रेजरी से गलत तरीके से 3.5 करोड़ निकाले थे। उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे। (एएनआइ)

पीएम पर टिप्पणी पर राज्यसभा सुरक्षा अधिकारी पदावनत

नई दिल्ली: राज्यसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के आरोप में एक सुरक्षा अधिकारी को पदावनत कर दिया है। उन पर नियम के उल्लंघन और राजनीतिक तटस्थता बरकरार रखने में विफल रहने का आरोप है। अधिकारी ने कई पोस्ट साझा किए हैं, जिनसे उनकी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रियता का पता चलता है। राज्यसभा सचिवालय ने 12 फरवरी को जारी आदेश में कहा है कि सभापति वेंकैया नायडू ने नियमों के तहत सुरक्षा उपनिदेशक उरजुल हसन को पदावनत करते हुए पांच साल के लिए लोअर ग्रेड अधिकारी बनाने का आदेश दिया है। सचिवालय ने कहा है कि हसन पर नियमों के उल्लंघन और राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में विफल रहने का आरोप है। पदावनत किए जाने के साथ ही हसन को पांच वर्षों के लिए वेतनवृद्धि भी नहीं मिलेगी। सजा की अवधि खत्म होने के बाद ही वह अपने पद पर लौट सकेंगे।

अर्जुन विजेताओं, निशानेबाजों को बंदूक रखने के नियमों में छूट

- अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को शस्त्रों की संख्या में छूट मिलेगी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने कहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को शस्त्र कानून में संशोधन के बाद बंदूक रखने के लिए बनाए गए नियमों से छूट दी गई है।

अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को यदि पुरस्कार निशानेबाजी में मिला है, तो शस्त्रों की संख्या में छूट मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता और जाने-माने निशानेबाज .22 कैलीबर की 12 तक राइफल, आठ एमएम तक के कैलीबर की सेंटर फायर राइफल, नौ एमएम सहित इससे कम के कैलीबर की पिस्टल और रिवाल्वर और 12 बोर तक के कैलीबर की शॉटगन रख सकते हैं। हालांकि निजी इस्तेमाल, ट्रेनिंग या प्रतियोगिताओं में उपयोग लिए बंदूक रखने के नियम से जिस भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज को छूट मिलेगी, उसे खेल मंत्रालय या राष्ट्रीय या राज्य राइफल संघ से प्रमाणित होना चाहिए।

खिलाड़ियों को छूट से संबंधित इस अधिसूचना को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने जारी किया है। अधिसूचना के अनुसार अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में एशियाई खेल, एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप, एशियाई महिला या एशियाई जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप, ओलिंपिक खेल, विश्व जूनियर या सीनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप और जूनियर तथा सीनियर विश्व कप शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता का अर्थ वह खिलाड़ी है, जिसने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में व्यक्तिगत या टीम पदक जीता हो। प्रख्यात निशानेबाज का अर्थ वह व्यक्ति है, जिसने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो और न्यूनतम क्वालीफाइंग स्कोर बनाया हो।

सांसदों, विधायकों के साथ संवाद में नियमों का पालन करें अधिकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों से सांसदों तथा विधायकों के साथ संवाद के दौरान नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं होने पर अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार की ओर से इस संबंध में जारी किए गए आदेश के मुताबिक, सभी राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से सांसदों की सामान्य और विशेष रूप से संसद सत्र के दौरान आवाजाही को लेकर अधिकारियों से जिम्मेदारियां निभाते समय संवेदनशीलता बरतने को कहा गया है कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सदस्यों और विधायकों का अहम स्थान है। जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों के सिलसिले में उन्हें अकसर भारत सरकार (केंद्र)या राज्य सरकारों के मंत्रालयों अथवा विभागों से जानकारी लेना, सुझाव देना अथवा अधिकारियों के साथ साक्षात्कार के लिए कहना जरूरी लगता है।

असम का नागरिकता डाटा गायब होने के बाद पूर्व अधिकारी पर एफआइआर

- नौकरी छोड़ने से पहले संवेदनशील दस्तावेजों का नहीं दिया पासवर्ड
- शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत पूर्व परियोजना अधिकारी पर कार्रवाई

प्रतीकात्मक फोटो

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में वेबसाइट ठ्ठह्म्ष्ठ्ठह्यह्यड्डद्द.ठ्ठद्ब.द्बठ्ठ से राज्य का अपडेट नागरिकता डाटा गायब होने के कुछ घंटे बाद पूर्व एनआरसी अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी नौकरी छोड़ने से पहले उनके द्वारा संवेदनशील दस्तावेजों का पासवर्ड नहीं देने के लिए दर्ज की गई है।

एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने गुरुवार को प्रेट्र को बताया कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत एनआरसी की पूर्व परियोजना अधिकारी के खिलाफ पलटन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कई बार लिखित में स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद दस्तावेजों का पासवर्ड नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि पिछले साल 11 नवंबर को इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया। वह अनुबंध पर थीं और नौकरी छोड़ने के बाद उनको पासवर्ड अपने पास रखने का अधिकार नहीं था।

शर्मा ने यह भी कहा कि एनआरसी कार्यालय ने कई बार उन्हें पासवर्ड देने के लिए लिखा। लेकिन, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमें पता था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए पासवर्ड के लिए उन्हें कई बार पत्र लिखा। लेकिन, इतने महीने में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए बुधवार को हमने उनके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का एक मामला दर्ज कराया। हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इन संवेदनशील जानकारियों से छेड़छाड़ तो नहीं की है। हालांकि, उन्होंने इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना के आरोप को खारिज किया।

ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति : अमित शाह

खरी बात ▸ गृहमंत्री ने ड्रग्स तस्करी को बताया आतंकी फंडिंग का अहम जरिया

कहा, हम इस समस्या पर लगाम लगाने को प्रतिबद्ध और दुनिया की अगुआई को तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

ड्रग्स तस्करी को आतंकी फंडिंग का बड़ा स्रोत बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की है। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार दुनिया के किसी भी देश से भारत में न तो ड्रग्स आने देगी और न ही यहां से बाहर जाने देगी।

अमित शाह बिम्सटेक देशों (बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन) के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान और थाईलैंड बिम्सटेक के सदस्य हैं। दो दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत बिम्सटेक समेत दुनिया के अन्य देशों के

नई दिल्ली में बिम्सटेक कांफ्रेंस के दौरान अमित शाह और नॉर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना (दाएं)। प्रेट्र

साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ड्रग्स की समस्या पर लगाम लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे लड़ाई में दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार है। दरअसल बिम्सटेक देश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच अहम कड़ी हैं जो ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा रूट भी है।

दुनिया में मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स सिर्फ इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करता बल्कि उसके परिवार के साथ-साथ समाज को तबाह कर देता है। उनके अनुसार पिछले 10 साल में मादक पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या में 30 फीसद इजाफा हुआ है जिसे रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आतंकवाद, अंतरदेशीय संगठित अपराध और ड्रग्स तस्करी की समस्या से नहीं जूझ रहा हो। जाहिर है इसके खिलाफ सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समस्या की विकरालता का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि दुनिया में हर साल लगभग 400 अरब डॉलर की ड्रग्स की तस्करी की जाती है।

चर्चा के लिए तीन दिन में देंगे समय

प्रथम पृष्ठ से आगे

शाह ने कहा, जो कोई भी उनके साथ सीएए से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है वह उनके कार्यालय से समय ले सकता है। 'हम तीन दिनों के अंदर चर्चा के लिए समय देंगे।' उन्होंने कहा, एनआरसी भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा था। हालांकि अब तक सरकार ने एनआरसी को पूरे देश में लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कांग्रेस को धर्म के आधार पर विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। शाह ने कहा कि नेताओं समेत सभी लोग नवगठित जम्मू और कश्मीर में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई रोक-टोक नहीं है। तीन पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सईद को बंदी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा कानून लगाने का फैसला स्थानीय प्रशासन का है। उमर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसलिए इस विषय में न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करें।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब राज्यों में होगी प्रतिस्पर्धा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- बेहतर काम करने वाले राज्यों को मिलेगा ज्यादा पैसा
- योजना तैयार करने में जुटा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जल्द हो सकती है लांच

स्वच्छ शहरों की तर्ज पर अब साफ हवा को लेकर भी शहरों और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। इनमें देश के वो 102 शहर भी शामिल होंगे जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल किया गया है। इसके तहत बेहतर काम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में ज्यादा पैसा दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए मानकों को तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह फैसला तब लिया है जब पैसा देने के बाद भी राज्य इसे लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। मंत्रालय इसे लेकर राज्यों को कई बार फटकार भी लगा चुका है, बावजूद इसके स्थिति जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में मंत्रालय का मानना है कि प्रतिस्पर्धा से राज्य अपनी छवि को ठीक करने के लिए सक्रिय होंगे।

बजट में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मिले 4,400 करोड़ के फंड को लेकर मंत्रालय भी भारी उत्साहित है। फिलहाल वह प्रोत्साहन योजना पर तेजी से काम कर रहा है जिसे जल्द ही जारी किया जा सकता है। इनमें वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय-समय पर मिले दिशा-निर्देशों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। इसके साथ ही साफ हवा से जुड़ी इस प्रतिस्पर्धा में राज्यों और शहरों का आकलन किन मापदंडों पर किया जाएगा, इसका भी ब्योरा तैयार किया जा रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारों पर सबसे ज्यादा फोकस किया रहा है।

सूत्रों के मुताबिक इस पर जोर इसलिए भी है क्योंकि यदि एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया तो वायु प्रदूषण की समस्या को जल्द ही खत्म किया जा सकेगा। इस बीच मंत्रालय ने इन मापदंडों को तय करते हुए राज्यों और इससे जुड़ी दूसरी एजेंसियों की भी राय मांगी है।

वायु प्रदूषण में आई कमी : वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि वायु प्रदूषण से निपटने से लिए पिछले वर्षों में किए गए प्रयासों के चलते पीएम-10 और पीएम-2.5 के स्तर पर में लगातार कमी दर्ज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018 के मुकाबले 2019 में पीएम-10 में करीब 25 फीसद और पीएम-2.5 में 19 फीसद से ज्यादा की कमी दर्ज हुई है। हालांकि ऐसी ही मुहिम आगे भी जारी रखने पर जोर दिया गया है।

'प्राइवेट ट्रेन चलाना आसान नहीं, पर जरूरी'

संजय सिंह, नई दिल्ली

- देश-विदेश की दो दर्जन कंपनियों के साथ हो रही चर्चा : विनोद यादव
- दो साल बाद शुरू हो पाएगा पहली असली प्राइवेट ट्रेन का सफर

प्रतीकात्मक फोटो

100 रूटों पर डेढ़ सौ प्राइवेट ट्रेनें चलाने का हुआ है फैसला

13 हजार पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है मौजूदा समय में

विनोद यादव फाइल फोटो

पूरी तरह से देश की पहली प्राइवेट ट्रेन दो वर्षों के बाद पटरी पर दौड़ पाएगी, लेकिन प्राइवेट ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है और इसलिए रेलवे बोर्ड बहुत फूंक-फूंक कर कदम उठा रहा है। इस संबंध में अब तक दो दौर की बैठक हो चुकी है।

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद यादव ने खास चर्चा में कहा कि सौ रूटों पर डेढ़ सौ प्राइवेट ट्रेनें चलाने का निर्णय यात्री सुविधाओं तथा 'ऑन डिमांड रिजर्वेशन' की मांग को देखते हुए जरूरी माना गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे अभी 13 हजार पैसेंजर ट्रेनें चला रहा है। चार-पांच वर्ष बाद डेढ़-दो हजार ट्रेनें और चलाने की जरूरत पड़ेगी। विनोद यादव का कहना है कि अभी नहीं मालूम कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी और इसीलिए बहुत फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं।

अब तक की चर्चाओं में देश-विदेश की लगभग दो दर्जन कंपनियों ने प्राइवेट ट्रेन चलाने में रुचि दिखाई है। इनके आधार पर ही आरएफक्यू बिड डाक्यूमेंट तैयार होगा जिसके जरिये ट्रेन चलाने में सक्षम कंपनियों का अकेले या कंसोर्टियम के रूप में चयन किया जाएगा। उसके बाद इन चयनित कंपनियों से बोली आमंत्रित की जाएगी। रेलवे को सर्वाधिक राजस्व का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों को ट्रेन संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजस्व में हिस्सेदारी के अलावा प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले सभी आपरेटर को रूट की लंबाई के हिसाब से हालेज चार्ज भी अदा करना होगा। यह हालेज चार्ज 668 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। प्राइवेट ट्रेन आपरेटरों को ट्रेन का किराया तय करने का अधिकार होगा।

विमान सेवाओं की तरह रेलवे किराये की कोई सीमा तय नहीं करेगा और इसे बाजार पर छोड़ देगा। हालांकि कुछ हद तक रेलवे की अपनी ट्रेनें प्राइवेट ट्रेनों के किराये पर अंकुश रखने का काम करेंगी। ट्रेन के भीतर सेवाओं, सुविधाओं और सुरक्षा के लिए ट्रेन आपरेटर अपना स्टाफ रखने को स्वतंत्र होंगे। ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। केवल ड्राइवर और गार्ड रेलवे के रहेंगे।

प्राइवेट ट्रेनों की रेक पूरी तरह भारत में बनेंगी या इन्हें विदेशों से भी आयात किया जा सकेगा? इस सवाल के जवाब में यादव का कहना था कि प्राइवेट आपरेटरों को 'मेक इन इंडिया' के तहत रेक का इंतजाम करना होगा। जिसका मतलब है कि वे जो भी रेक खरीदेंगे उसमें 51 फीसद कलपुर्जे भारत में निर्मित होने चाहिए। वंदे भारत की रेक भी इसी सिद्धांत पर बनाई जा रही हैं। प्राइवेट कंपनियां चाहें तो वंदे भारत की रेक का इस्तेमाल कर सकती हैं या कोई दूसरी नई रेक भी खरीद सकती हैं। लेकिन उसका 51 फीसद निर्माण भारत में आरडीएसओ के मानकों के अनुसार करने की शर्त होगी।

यह पहला मौका है जब रेलवे पूरी तरह से निजी कंपनियों को प्राइवेट ट्रेन चलाने का मौका देने जा रहा है। अभी तक 'तेजस' नाम से जो दो प्राइवेट ट्रेनें चलाई गई हैं उन्हें आइआरसीटीसी पीपीपी मॉडल पर निजी कंपनियों की साझेदारी में चला रहा है।

जयंती की पूर्व संध्या पर दो संस्थानों को दिया गया सुषमा स्वराज का नाम

- प्रवासी भारतीय केंद्र होगा सुषमा स्वराज भवन, विदेश सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेश संस्थान किया गया
- विदेशों में संकट में फंसे भारतीयों की तुरंत मदद करने के लिए जानी जाती थीं पूर्व विदेश मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : विदेश में रहने वाले अपने मूल नागरिकों के साथ संपर्क को प्रतिध्वनित करने वाले सांस्कृतिक केंद्र प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम गुरुवार को पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर सुषमा स्वराज भवन किया गया। भवन का नामकरण दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों से संपर्क साधने में संवेदना प्रदर्शित करने के लिए मशहूर रहीं पूर्व विदेश मंत्री के सम्मान में किया गया है। इसके अलावा राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाले विदेश सेवा संस्थान का नाम भी सुषमा स्वराज विदेश संस्थान किया गया है। सरकार का यह फैसला उनकी 68वीं जयंती से एक दिन पहले सामने आया है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली पहली सरकार में विदेश मंत्रालय संभाल चुकीं सुषमा स्वराज को सहानुभूति और भारतीय कूटनीति के मानवीय रुख प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। पिछले वर्ष छह अगस्त को हृदय गति रुकने के बाद उनका निधन हो गया था।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ट्विटर पर कहा कि संस्थानों का नया नाम देना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहीं महान राजनीतिक हस्ती के प्रति उपयुक्त श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा, 'हम सभी पूरे अनुराग से श्रीमती सुषमा स्वराज को याद करते हैं। शुक्रवार को उनका 68वां जन्मदिवस है। विदेश मंत्रालय परिवार उनकी कमी महसूस करेगा।'

नई दिल्ली में स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र के बाहर पूर्व विदेश मंत्री के नाम पर सुषमा स्वराज भवन की पट्टिका लगा दी गई है। प्रेट्र

स्वराज ट्विटर पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली विदेश मंत्री थीं। उन्हें विदेश में संकट में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए जाना जाता है। ट्विटर पर मदद की गुहार पर वह त्वरित प्रतिक्रिया देती थीं। यहां तक कि पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान में भी लोकप्रिय थीं। भारत में इलाज के लिए वीजा मांगने वाले लोगों को वह त्वरित उत्तर देती थीं।

फेसबुक पर हो सकते हैं 27.5 करोड़ फर्जी अकाउंट

हैदराबाद, प्रेट्र : फेसबुक पर 27.5 करोड़ अकाउंट फर्जी हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर 2019 तक फेसबुक के मंथली एक्टिव यूजर (एमएयू) की संख्या 2.5 अरब थी। गत वर्ष की तुलना में यह आठ फीसद अधिक है। इस बढ़ोतरी में भारत, इंडोनेशिया और फिलीपींस के यूजर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

फेसबुक ने कहा, 'हमारा अनुमान है कि वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में फर्जी अकाउंट का अनुपात हमारे एमएयू का करीब 11 फीसद है। अधिक विकसित बाजारों की तुलना में इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे विकासशील बाजारों में इस तरह के फर्जी अकाउंट की संख्या अधिक है।' फेसबुक के मुताबिक, जब कोई फेसबुक यूजर मुख्य अकाउंट के अतिरिक्त कोई अन्य अकाउंट रखता है तो दूसरे को फर्जी माना जाता है। इन्हें दो श्रेणियों में रखा गया है- पहले में वे अकाउंट हैं जिन्हें व्यावसायिक आदि गतिविधियों के लिए बनाया गया है, दूसरे में वे हैं जिन्हें फेसबुक नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया है। फर्जी अकाउंट की संख्या का अनुमान नमूने की आंतरिक समीक्षा पर आधारित है। वास्तव में इसकी संख्या अलग हो सकती है।

कोहराम

नई विचारधारा के साथ पार्टी को फिर से गढ़ने की पुरजोर मांग, वरिष्ठ नेताओं का सुझाव-हमें देश के लोगों से नए तरीके से जुड़ने के बारे में सोचना होगा

दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस में तेज हुए बदलाव के सुर

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क

पिछले 70 सालों में देश बहुत बदल चुका है। नई विचारधारा, नई सोच और कामकाज के नए तरीकों से पार्टी को खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा।
-ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता

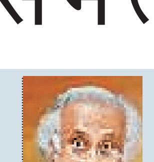
हमें हेकड़ी छोड़नी होगी। छह साल से भी अधिक समय से सत्ता से दूर रहने के बावजूद हममें से कई ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे अभी भी मंत्री हों।
-जयराम रमेश, कांग्रेस नेता

दिल्ली के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से पार्टी में अमूल-चूल परिवर्तन की मांग उठने लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश ने देश की सबसे पुरातन पार्टी को आईना दिखाया है। दोनों ने सुझाव दिया कि पार्टी को अब नई विचारधारा के साथ खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा। अन्यथा उसे भविष्य में निरर्थक होने का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली बदलने की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि हमें देश के लोगों से नए तरीके से जुड़ने के बारे में सोचना होगा।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नई दुनिया के प्रतिनिधि के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली के चुनाव में पार्टी की लगातार दूसरी करारी हार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में देश बहुत बदल चुका है। नई विचारधारा, नई सोच और कामकाज के नए तरीकों से पार्टी को खुद को नए सिरे से गढ़ना होगा। दिल्ली में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। अब देश बदल रहा है और हमें भी बदले हुए परिवेश में जाने की जरूरत है।

वहीं, कोच्चि में दिए इंटरव्यू में जयराम रमेश ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस की खराब स्थिति पर कहा, वास्तव में हम बिहार में कहीं नहीं हैं। उत्तर प्रदेश से लगभग विलुप्त हो चुके हैं। हम राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में मजबूती से वापसी कर पाए। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं को अब खुद को बेदर्दी से गढ़ना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सार्थकता बनाए रखनी है तो उसे पुनर्गठन की जरूरत है। अन्यथा हम औचित्य खोने वाले हैं। हमें हेकड़ी को छोड़ना होगा। छह साल से भी अधिक समय से सत्ता से दूर रहने के बावजूद हममें से कई ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे अभी भी मंत्री हों। स्थानीय स्तर के नेताओं को बढ़ावा देना होगा और उन्हें शिक्षित करना होगा। उन्हें स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। हमारे नेतृत्व के स्वरूप व शैली में बदलाव की जरूरत है।

जयराम ने कहा, वह इस प्रचार से चिंतित हैं कि कांग्रेस देश में अल्पसंख्यकों के कट्टरवाद को लेकर नरमी दिखाती है। पार्टी ऐसे मुद्दों पर केवल एक पक्ष के साथ नजर नहीं आ सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस को पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) जैसे सांप्रदायिक संगठनों के खिलाफ भी बोलना चाहिए। पार्टी को पीएफआइ या जमात-ए-इस्लामी जैसे सांप्रदायिक दलों के खिलाफ भी सख्त होना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को सीएए विरोधी प्रदर्शनों की तरह ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का भी जमकर विरोध करना होगा।

जयराम ने दावा किया कि नई दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ने भाजपा के सांप्रदायिक हितों के साथ ही सांप्रदायिक मुसलमानों के हितों की भी पूर्ति की है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शाहीन बाग के लोग किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का डर है कि उनकी नागरिकता उनसे छिन जाएगी। लेकिन यह उनका भावी डर है। और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें एनपीआर और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए।

कह के रहेंगे माधव जोशी

6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने। गुरुवार को रोहतक के सिविल लाइन थाने में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। उन्हें बिना दर्ज की गई शिकायतें, 2 लोडेड कार्बाइन और 1 पिस्टल मिली।

राजनीति के शुद्धिकरण के लिए है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

प्रतिक्रिया ▸ कांग्रेस ने फैसले को राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई की जीत भी बताया

नई दिल्ली, प्रेट्र : आरोपित नेताओं को टिकट देने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि यह राजनीति के शुद्धिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। पार्टी ने इसे राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई में जीत करार दिया।

पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है जो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। यह स्वच्छ राजनीति की दिशा में आगे बढ़ने में मील का पत्थर साबित होगा।' शेरगिल ने कहा, 'इससे राहुल गांधी की उस लड़ाई की जीत हुई है जो वह राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ लड़ते आए हैं और लड़ रहे हैं।'

उन्होंने दावा किया, 'एक रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव में 42 फीसद भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज थे। भाजपा के 92 सांसदों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। कहा कि यह पार्टी की नीयत और नीति को दिखाता है।'

उन्होंने भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या भाजपा अपने उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी सामने रखेगी? शेरगिल ने आगे कहा, जैसे ही यह ऐतिहासिक फैसला आया, भाजपा ने कर्नाटक में आनंद सिंह को मंत्री नियुक्त कर दिया बावजूद इसके कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 15 मामले हैं।

जनमत मुद्दा

क्या राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के लिए सिर्फ हमारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

चुनावी लोकतंत्र को मजूबत करेगा फैसला : भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र : राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भाजपा ने चुनावी राजनीति को मजबूत करने वाला करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि इससे मतदाताओं को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विकल्प चुनने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करना ही होगा।

चुनाव सुधार की दिशा में स्वागतयोग्य कदम

देश की प्रगति, आर्थिक विकास, आर्थिक सुधारों और जनकल्याण के लिए राजनीतिक व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट या सरकार द्वारा इस दिशा में उठाया गया हर कदम स्वागतयोग्य है। राजनीतिक व्यवस्था में सुधारों की शुरुआत राजनीतिक दलों और चुनाव प्रक्रिया में बदलाव के साथ होनी चाहिए। वर्तमान हालात के लिए सभी दल दोषी हैं। यथास्थिति को बनाए रखने में सभी दलों का निहित स्वार्थ है। आपराधिक छवि के लोग सभी राजनीतिक दलों से आ रहे हैं। इसके लिए किसी एक दल को दोष नहीं दिया जा सकता है। ये देश और जनमानस के लिए घोर चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कदम स्वागतयोग्य है। यह जरूरी था। हालांकि यह छोटा कदम अपर्याप्त है। मूलभूत जरूरत निर्वाचन प्रणाली और राजनीतिक दलों में व्यवस्थाजन्य परिवर्तन की जरूरत है।

सुभाष कश्यप
संविधान विशेषज्ञ

प्रबल होगी राजनीति के अच्छे दिनों की उम्मीद

राजनीति में अपराधियों के प्रवेश को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कई दिशानिर्देश दे रखे हैं। राजनीतिक दल और चुनावी प्रत्याशी उन नियमों–कानूनों का सही तरीके से पालन ही नहीं करते हैं। अगर पहले के ही प्रावधानों का उचित तरीके से पालन होता तो जनता को उन उम्मीदवारों का सारा कच्चा–चिट्ठा पता हो जाता। बहरहाल पारदर्शी लोकतंत्र और चुनावी सुधार की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ये पहल बड़ी है। पहले अपने शपथपत्रों में उम्मीदवार आपराधिक इतिहास का सारा विवरण देते थे जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दर्ज होता था। यहां तक ज्यादातर लोगों की पहुंच नहीं हो पाती थी। अब राजनीतिक दलों की वेबसाइट पर ये सूचना उन्हें सहजता से उपलब्ध होगी। साथ ही दागी प्रत्याशी को चुनने की वजह बताने की शर्मिंदगी से बचने के लिए राजनीतिक दल ऐसे लोगों के चयन से परहेज ही करेंगे। राजनीति के अच्छे दिनों की उम्मीद प्रबल होगी।

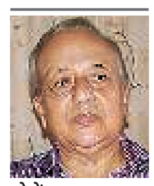

योगेंद्र नारायण
पूर्व महासचिव, राज्यसभा

गालिब ये खयाल अच्छा है...

'हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल के खुश रखने को गालिब ये खयाल अच्छा है।' सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत असर मुझे नहीं दिखाई देता है। वर्तमान में भी अन्य तरीकों के रूप में ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। मसलन दागी उम्मीदवार को अपना सारा विवरण देना होता है। उसे समाचार–पत्रों में प्रकाशित भी कराना होता है लेकिन, कहां बदलाव दिख रहा है। हम लोग पिछले 18 वर्ष से चुनावी सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दैनिक जागरण भी सशक्त मुहिम चलाता रहा है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सारे नियम–कानून बेकार हैं। राजनीतिक दल सबसे बचने की जुगत निकाल लेते हैं। राजनीतिक दलों को दागी प्रत्याशी चयन की वजह उनकी वेबसाइट पर बतानी होगी। वे घुमा–फिराकर इसकी काट के लिए कोई न कोई तर्क गढ़ लेंगे। राजनीति में अपराधियों पर तब तक पूर्णविराम नहीं लगेगा, जब तक गंभीर अपराध के आरोपितों को चुनाव में हिस्सा लेने पर रोक न लग जाए।

जगदीप एस. छोकर
संस्थापक, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स

दागियों के दाग बुरे लगे तो उनकी पत्नियों को बना दिया माननीय

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के राजनीतिक दलों ने कभी दागी और दबंगों से परहेज नहीं किया। बल्कि एक दौर वह भी था कि ये टिकट की गारंटी हुआ करते थे। बाद में दागी सजायाफ्ता होने लगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग के नियम कड़े हुए तो राजनीतिक दलों ने नया रास्ता निकाल लिया। फिर दागियों की पत्नियां सांसद–विधायक बनने लगीं। महीनों से जेल में बंद निर्दलीय विधायक अनंत सिंह 2010 में जदयू टिकट पर चुनाव जीते थे। 2015 के चुनाव में निर्दलीय जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दे दिया। हालांकि वह हार गईं। सिवान के चर्चित दबंग अजय सिंह को जदयू ने लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। उनकी पत्नी कविता सिंह विधायक थीं। उन्हें सिवान से टिकट दे दिया गया। वह जीतीं। उनके इस्तीफे के बाद जब विधानसभा की दारौंदा सीट पर उपचुनाव हुए तो जदयू ने अजय सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया। यह अलग बात है कि उपचुनाव में उनकी हार हो गई। छपरा के दबंग छवि के एक और विधायक मनोरंजन सिंह ऊर्फ धूमल सिंह इस समय जदयू में हैं। राजद के विधायक राजबल्लभ यादव पर नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोप प्रमाणित हुआ। सदस्यता गई। मगर विधायक की हैसियत से राजबल्लभ जब तक जेल में रहे, राजद ने उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया।

राजनीति में बैकफुट पर होंगे उत्तर प्रदेश के दागी

आलोक मिश्र, लखनऊ : देश की राजनीति में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में भी शायद अब दागियों के 'माननीय' बनने की परंपरा टूटे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए गुरुवार को जो फैसला सुनाया है, उससे मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, अतीक अहमद, बृज भूषण शरण सिंह, धनंजय सिंह, गुड्डू पंडित, अजय सिपाही जैसे दबंगों के खादी का दामन थाम विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तय करने की हसरतों का गहरा झटका लगा है।

राजनीतिक दलों के लिए भी किसी सीट को हर कीमत पर हासिल करने की गणित के तहत ऐसे चेहरों को अपनाना मुश्किल होगा। एडीआर की रिपोर्ट पर नजर दौड़ाए तो दागी उम्मीदवारों के चुनाव मैदान में ताल ठोंकने की परंपरा के मजबूत साक्ष्य खुद-ब-खुद सामने आ जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 402 में से 143 विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किये थे। यानी 36 फीसद विधायक दागी थे। इनमें भी 107 ऐसे विधायक थे, जिन्होंने खुद पर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे।

लोकसभा चुनाव में भी इतर न थी तस्वीर : लोकसभा चुनाव 2019 में भी खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा करने वाले उम्मीदवारों की कमी नहीं थी। 24 उम्मीदवारों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की थी, जबकि 21 उम्मीदवारों ने खुद पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी।

बादल बोले, देश की मजबूती के लिए धर्मनिरपेक्ष सरकारों की जरूरत

जागरण संवाददाता, अमृतसर

▸ दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद बुजुर्ग अकाली नेता का आया बयान

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिरोमणि अकाली दल भी अपनी रणनीति बदलता दिख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि देश की मजबूती व विकास के लिए धर्मनिरपेक्ष सरकारें समय की जरूरत हैं क्योंकि कोई भी राष्ट्र सिर्फ धर्मनिरपेक्ष सरकारों से ही सुरक्षित रह सकता है।

बादल गुरुवार को यहां अजनाला में राज्य की कैप्टन सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित रोष रैली को संबोधित कर रहे थे। बादल ने देश के सामाजिक तथा राजनीतिक माहौल पर गहरी चिंता जताई। कहा कि धर्मनिरपेक्षता के पवित्र सिद्धांतों की जरा सी अनदेखी भी देश को कमजोर कर सकती है। राज्यों के सत्ताधारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि देश को संविधान में दर्ज धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चलाया जाए। देश का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहां अल्पसंख्यक न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि सम्मानित महसूस करें।

अकाली दल ने बदली रणनीति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अकाली दल ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए बागी अकालियों के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। पूर्व सांसद रतन सिंह अजनाला के पुत्र पूर्व विधायक अमरपाल सिंह बोनी की अकाली दल में वापसी इसी रणनीति का हिस्सा है। इसकी पटकथा करीब 15 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। इंतजार केवल राजासांसी (अमृतसर) में अकाली दल की रैली का था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ही अकाली दल को लगने लगा था कि अगर पंजाब में उसे अपने बिखरते वोट बैंक को रोकना है तो पहले अकाली दल टकसाली को रोकना ही पड़ेगा।

कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साधते हुए बादल ने कहा कि पंजाब के लोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के धोखे को अब सहन नहीं करेंगे। कैप्टन चुनावों के दौरान पंजाब की जनता के साथ किए वादों को पूरा करें अन्यथा कुर्सी छोड़ दें। शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि लोग कैप्टन को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को तोड़ने में कामयाब नहीं होने देंगे।

सुखबीर पहुंचे अजनाला के घर, बंद कमरे में मुलाकात: रैली से पहले शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल अजनाला स्थित अकाली दल टकसाली की अहम कड़ी माने जाते पूर्व सांसद डॉ. रतन सिंह अजनाला के घर पहुंचे।

यहां सुखबीर ने डॉ. अजनाला पिता-पुत्र के साथ करीब 30 मिनट बंद कमरे में बैठक की। मुलाकात के बाद अमरपाल सिंह बोनी सुखबीर के साथ उनकी गाड़ी में शिअद की रैली में गए और वहां मंच से शिअद में वापसी की घोषणा। हालांकि उनके पिता डॉ. रतन सिंह अजनाला रैली में नहीं गए।

पुनिया ने गोडसे से की पीएम मोदी की तुलना

नईदुनिया, रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से की है। उन्होंने कहा कि मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेककर प्रवेश किया था।

अब उसी संसद का अपमान करने वाले कानून पास करवा रहे हैं। गोडसे ने भी इसी तरह पहले गांधी जी के पैर छुए थे और फिर उनको गोली मार दी थी। यह इनकी संस्कृति है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रेसवार्ता में पुनिया ने आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर भाजपा और संघ पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में 12 से 14 फरवरी तक इसी तरह प्रेसवार्ता के माध्यम से भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरे को उजागर किया जाएगा।

: पुनिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ आठ और 12 उल्लेख किया। इसमें मामले में उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी करने वाले वकीलों का जिक्र है, जिन्होंने कहा कि एसटी-एससी-ओबीसी आरक्षण कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

उद्धव सरकार को यलगार परिषद मामले की एनआइए जांच पर कोई आपत्ति नहीं

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना रुख बदलते हुए कहा है कि उसे यलगार परिषद मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) से जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच पुणे पुलिस से एनआइए को हस्तांतरित कर दी थी। तब इस फैसले की राज्य की शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार ने तीखी आलोचना की थी।

राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि राज्य के गृह विभाग को एआइए को जांच सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जबकि राकांपा नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गेंद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पाले में डालते हुए कहा, 'राज्य की एजेंसियां भीमा कोरेगांव (यलगार परिषद) मामले की जांच कर रही थीं, लेकिन केंद्र ने जांच एनआइए को सौंप दी। गृह मंत्री के तौर पर मेरा रुख था कि केंद्र को फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था। इस दिशा में हम अपना रुख अदालत में रख रहे हैं। मुख्यमंत्री को मेरा रुख अस्वीकार करने का अधिकार है।'

प्रतीकात्मक

इन बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मसले पर मुख्यमंत्री कार्यालय और देशमुख के नेतृत्व वाले गृह विभाग के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। देशमुख ने कहा, 'पुणे की अदालत अपना आदेश (मामले के स्थानांतरण) शुक्रवार को सुनाएगी। शरद पवार की मांग के अनुसार हम यलगार परिषद मामले की जांच के लिए एसआइटी गठित करने पर महाधिवक्ता की राय लेंगे और पूछेंगे कि क्या राज्य सरकार एसआइटी गठित करने पर आगे बढ़ सकती है।'

पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि केंद्र को जांच हाथ में लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे एनआइए को जांच सौंपने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था। उनका कहना था कि यह मामला तब एनआइए के हवाले किया गया जब राकांपा प्रमुख शरद पवार ने इस मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) से करवाने की मांग की।

एनआइए ने पिछले हफ्ते पुणे की सत्र अदालत में एक आवेदन दाखिल किया था जिसमें मामले के कागजात, जब्त डाटा, अदालती रिकॉर्ड्स और प्रक्रिया मुंबई की विशेष एनआइए अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने तब यह कहते हुए एनआइए के आवेदन का विरोध किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में जो कारण गिनाए हैं वे न तो कानूनन सही हैं और न मामला विशेष एनआइए अदालत में स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त हैं। अभियोजन का कहना था, 'अपराध स्थानीय अदालत के न्यायाधिकार में हुआ है, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है।'

नए जम्मू–कश्मीर में पहली बार बजा पंचायत चुनाव का बिगुल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▸ रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंच पदों के लिए होंगे चुनाव

▸ पहली बार दलीय आधार पर होगा चुनाव, आठ चरणों में मतदान

अनुच्छेद-370 हटने के बाद केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में पहली बार बड़ी चुनावी कवायद शुरू हो गई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार को प्रदेश में रिक्त पड़े 1011 सरपंच और 11639 पंच हलकों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। पहली बार यह चुनाव दलीय आधार पर होंगे। शैलेंद्र कुमार ने कहा कि मतदान आठ चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान पांच मार्च और अंतिम चरण का मतदान 20 मार्च को होगा। वहीं, मतदान के लिए वोटिंग मशीन के बजाय मतपेटियां और मतदान पत्र इस्तेमाल होंगे। मतदान सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक होगा। नतीजे भी उसी शाम को आएंगे।

बीते 70 वर्षों में यह पहला मौका होगा, जब जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनावों में उम्मीदवार अपनी पार्टी के चुनाव चिह्न के साथ मतदाताओं के पास जाएंगे। हालांकि केंद्र शासित लद्दाख में रिक्त पड़े पंच-सरपंच पदों के लिए फिलहाल चुनाव नहीं हो रहा है।

जम्मू प्रांत में चुनाव प्रक्रिया पहले चार चरणों में ही : मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जम्मू प्रांत के दस जिलों में यह चुनाव प्रक्रिया पहले चार चरणों में ही संपन्न हो जाएगी जबकि कश्मीर प्रांत में यह पहले चरण से लेकर आठवें चरण तक चलेगी। उन्होंने बताया कि मतदान का शेड्यूल बर्फबारी से प्रभावित इलाकों के मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

ढाई साल होगा पंच–सरपंच का कार्यकाल : शैलेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2018 में जो आरक्षण नियम था, वही इन चुनावों के दौरान लागू होगा। अगर किसी वर्ग विशेष के लिए कोई सीट आरक्षित है तो वह उसके अनुरूप ही रहेगी। वहीं, पंच-सरपंच बनने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल पांच साल नहीं बल्कि लगभग ढाई साल होगा।

बंगाल में विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भाजपा असमंजस में, हुए दो मत

जागरण संवाददाता, कोलकाता

▸ एक वर्ग चाहता है चुनावी रणनीति में हो बदलाव

▸ स्वप्न दासगुप्ता ने कहा, केवल मोदी–शाह के नाम पर नहीं जीत सकते

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद इसकी बंगाल ईकाई के चुनाव प्रबंधक अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विभाजित हैं। उनमें यह विभाजन इसलिए है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर पार्टी की आक्रमक रणनीति को आगे बढ़ाया जाए या इसे हलका किया जाए।

अब बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर भाजपा में दो तरह के विचार सामने आ रहे हैं। भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वप्न दासगुप्ता ने ट्वीट किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पर ही चुनाव जीता नहीं जा सकता है। चुनाव लड़ने से पहले पार्टी को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, आदर्श मुद्दों के बदले विकास मूलक कार्यों को विशेष महत्व देना होगा। दासगुप्ता के ट्वीट के बाद पार्टी के भीतर ही विवाद शुरू हो गया है। दासगुप्ता के ट्वीट पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, जीतने के बाद ही तय किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। स्वप्न द्वारा मोदी-शाह का नाम लेकर बयान देने के सवाल पर कहा कि इसका जवाब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व देगा।

प्रदेश भाजपा सूत्रों के अनुसार बंगाल जहां पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 एवं दिल्ली में सभी सात लोकसभा सीटें जीती थीं। प्रदेश भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, 'कुछ महीनों के भीतर दिल्ली में विपरीत परिणाम देखा गया। इसलिए हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए कि हमने बंगाल में 18 सीटें जीतीं, हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। हमें राज्य के चुनावों के लिए अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। यह नहीं देखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हम क्या काम कर रहे हैं बल्कि राज्य के चुनावों के लिए भी काम करना होगा।

हमारा अभियान न केवल सीएए के कार्यान्वयन और एनआरसी की आवश्यकता को उजागर करने के लिए हो बल्कि शासन की नीतियों पर वैकल्पिक और बेहतर अभियान पर भी जोर होना चाहिए। घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एनआरसी की मांग के साथ ही नया नागरिकता कानून राज्य में नवीनतम फ्लैशप्वाइंट के रूप में उभरा है जिसका तृणमूल कांग्रेस पूरे दम से विरोध कर रही है। वहीं भाजपा इसके कार्यान्वयन के लिए दबाव डाल रही है।

राज्य भाजपा इकाई के एक अन्य वर्ग का मानना है कि पार्टी की रणनीति में बदलाव की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि आक्रामक राजनीति पार्टी के लिए सकारात्मक रही है। यदि तृणमूल जैसी पार्टी का मुकाबला करना चाहते है तो अपनी आक्रामक रणनीति को बनाए रखना होगा।

लालू के समधी का राजद से मोह भंग हुआ, जदयू में जाएंगे

राज्य ब्यूरो, पटना

पुत्री एश्वर्या की लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप से शादी और उसके बाद तलाक के झगड़े को लेकर हाल के वर्षों में चर्चा में रहे राजद विधायक चंद्रिका राय अब जदयू का दामन थामेंगे। वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के पुत्र हैं। उनका दावा है कि राजद के कई और विधायक जदयू के संपर्क में हैं। अगली बार फिर नीतीश कुमार की अगुआई में एनडीए की सरकार बनेगी। राय से पहले राजद के तीन अन्य विधायक महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और डा. फराज फातमी जदयू में शामिल होने के संकेत दे चुके हैं।

चंद्रिका राय राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के समधी हैं। उनकी पुत्री ऐश्वर्या और लालू प्रसाद के पुत्र तेजप्रताप की शादी मई 2018 में हुई थी। फिलहाल दोनों के बीच तलाक का मुकदमा अदालत में चल रहा है। गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान चंद्रिका राय पूछा गया कि क्या उनकी पुत्री ऐश्वर्या राय भी चुनाव लड़ेंगी, इस सवाल पर चंद्रिका राय का जवाब था कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वह इसके बारे में खुद ही फैसला कर सकती हैं।

चंद्रिका राय। फाइल

राजद में अनुशासन नहीं : उन्होंने कहा कि राजद में अनुशासन नहीं है। दल विरोधी आचरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लोकसभा चुनाव में दल के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। उनका इशारा पूर्व मंत्री तेज प्रताप की ओर था, जिन्होंने शिवहर और जहानाबाद के राजद उम्मीदवारों का खुलकर विरोध किया। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कमजोर बताकर मजाक उड़ाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई।

सियासत

दिल्ली जीत के बाद पार्टी ने पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी, पार्टी से किनारा कर चुके नेताओं को एकजुट करेंगे

पंजाब में आप को खड़ा करेंगे प्रशांत किशोर

बरींद्र सिंह रावत, चंडीगढ़

दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी ने अब पंजाब पर अपनी नजरें गड़ाई हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में खुद को जमीनी तौर पर मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर को हायर किया है। दिल्ली में मिली जीत से उत्साहित आप पंजाब में 2022 विधानसभा चुनाव में धमाकेदार उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है।

प्रशांत किशोर की रणनीति से 2017 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल रहे थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में वह आम आदमी पार्टी को पंजाब में मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौजूदा समय में आप का नेतृत्व पंजाब में बिखरा हुआ है। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ राज्य में दमदार एंट्री की थी और चार सीटों पर जीत हासिल की थी। पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी, फतेहगढ़ साहिब से हरिंदर सिंह खालसा, फरीदकोट से प्रोफेसर साधु सिंह और संगरूर से भगवंत मान भारी मतों के साथ जीते थे। पार्टी ने राज्य में 24. 39 प्रतिशत वोट हासिल किए थे, जो अकाली दल से मात्र दो फीसद कम थे। इसके तीन साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को 23 प्रतिशत वोट मिले। पार्टी का जनाधार कुछ कम हुआ, लेकिन वह राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें जीतने में सफल रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी के हाथ सिर्फ एक लोकसभा सीट लगी। संगरूर से पार्टी प्रत्याशी भगवंत मान विजय रहे। पार्टी का वोट फीसद सिर्फ 7.38 रह गया।

प्रशांत किशोर। फाइल

चुनौती होगा नेताओं को एकजुट करना: वर्ष 2016 में आप की पंजाब इकाई में फूट की शुरुआत हो गई थी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अगस्त 2016 को सुच्चा सिंह छोटेपुर को हटाया, तो स्थानीय नेताओं ने दिल्ली नेतृत्व पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया। अगस्त 2018 में सुखपाल सिंह खैहरा ने राज्य इकाई को केंद्रीय नेतृत्व से अलग घोषित कर दिया। खैहरा का साथ छह अन्य विधायकों ने दिया। आखिर खैहरा और कंवर संधू को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण हटाया गया तो खैहरा ने अलग से पंजाब एकता पार्टी की घोषणा कर दी। जिन नेताओं ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया अब वह बिखरे हुए हैं। मानसा के एमएलए नाजर सिंह, रोपड़ के एमएलए अमरजीत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी तो जैतो से एमएलए बलदेव सिंह और दाखा से एमएलए हरविंदर सिंह फूलका ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था।

अपने ही ब्रांड को ध्वस्त करने की बनाएंगे रणनीति

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर को उस 'पंजाब दा कैप्टन' ब्रांड को ध्वस्त करना होगा, जिसे उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में बनाया था। तब उन्होंने अमरिंदर सिंह का कद पार्टी से भी बड़ा कर दिया था। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव के लिए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की सेवाएं ली थीं।

उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर चुनाव को कांग्रेस बनाम अन्य की बजाय कैप्टन बनाम अन्य कर दिया था। 'पंजाब दा कैप्टन', कॉपी विद कैप्टन, कैप्टन की चौपाल के अलावा उन्होंने कर्ज माफी, घर-घर नौकरी जैसे स्लोगन तैयार करवाकर कांग्रेस की मुहिम को बढ़ाया। कांग्रेस की कमजोरियों को छिपाकर उन्होंने आक्रामक शैली में पार्टी की मुहिम को चलवाया।

हालांकि कांग्रेस इससे ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता व कैबिनेट मंत्री ब्रहम मोहिंदरा ने कहा, 'प्रशांत किशोर प्रोफेशनल हैं, उन्हें कोई भी हायर कर सकता है। यह उन पर है कि वह किसके साथ काम करना चाहते हैं।' मोहिंदरा ने कहा, पंजाब दिल्ली नहीं है। 2022 में आप को नानी याद करवा देंगे। इनके पास तो पंजाब की 117 सीटों पर उम्मीदवार उतरने के लिए भी नेता नहीं हैं। अभी जो बीस विधायक हैं, चुनाव में इनकी जमानत भी बच जाए, यही गनीमत होगा। पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रशांत तो पहले से ही आम आदमी पार्टी के साथ हैं।

तेज प्रताप के साथी ने तेजस्वी के खिलाफ दर्ज कराया एनसीआर

जासं, पटना : बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ सनहा (गैर संज्ञेय रिपोर्ट-एनसीआर) दर्ज किया गया है। यह सनहा अभिनंदन कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया है। अभिनंदन अक्सर तेजस्वी के बड़े भाई व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ रहते हैं। वह खुद को ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया नामक संस्था का उपाध्यक्ष बताते हैं। अभिनंदन का आरोप है कि इंटरनेट कॉल कर उन्हें कनपटी में गोली मारने की धमकी दी गई है। उनका आरोप है कि 14 महीने पहले तेजस्वी यादव ने भी उन्हें धमकी दी थी इसलिए उनका शक तेजस्वी पर ही है। 2 नवंबर 2018 की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ अभिनंदन ने एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा से मुलाकात की। इस बाबत एसएसपी ने बताया कि मामला संज्ञान में है।

250 से अधिक एनजीओ की सीबीआइ जांच कर रही है उत्तर प्रदेश में सपा शासनकाल में हुए सचल पालना गृह घोटाले में। इन एनजीओ के संचालकों व समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर जल्द शिकंजा कस सकता है।

अमेरिका-भारत के घनिष्ठ संबंधों का जश्न मनाने के लिए यात्रा : मेलानिया ट्रंप

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में पहली भारत यात्रा को लेकर मेलानिया ट्रंप खासी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा है कि वह और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारत यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का जश्न मनाने का एक अवसर होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति ट्रंप 24 और 25 फरवरी को अपनी आधिकारिक भारत यात्रा पर होंगे।

मेलेनिया ट्रंप की फाइल फोटो। रायटर

राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की प्रथम महिला दिल्ली के अलावा मोदी के गृह राज्य गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद भी जाएंगे। एक ट्वीट में 49 वर्षीय मेलानिया ट्रंप ने भारत यात्रा का आमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे लिखा, 'इस महीने के आखिर में अहमदाबाद और नई दिल्ली की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं इस यात्रा के प्रति बेहद उत्साहित हैं। यह अमेरिका और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों का जश्न मनाने का अवसर होगा।' दरअसल, मेलानिया ट्रंप बुधवार को किए गए प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट का जवाब दे रही थीं। इस ट्वीट में मोदी ने लिखा था कि भारत अपने सम्मानित अतिथियों का यादगार स्वागत करेगा। यह यात्रा बेहद खास है और भारत-अमेरिका दोस्ती को और मजबूत करने में अहम साबित होगी।

लॉकहीड मार्टिन ने तेजस व एएमसीए में मदद की पेशकश की

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका की दिग्गज कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत को तेजस लड़ाकू विमान की क्षमता बढ़ाने तथा अगली पीढ़ी का उन्नत बहुद्देश्यीय लड़ाकू विमान (एएमसीए) विकसित करने के करोड़ों डॉलर के कार्यक्रम में मदद की पेशकश की है। ट्रंप की यात्रा के दौरान दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग के और मजबूत होने की उम्मीद है। लॉकहीड मार्टिन के एक वरिष्ठ अधिकारी विवेक लाल ने कहा कि कंपनी तेजस लड़ाकू जेट के साथ ही अगली पीढ़ी के महत्वाकांक्षी विमान के विकास में भारत की सहायता करने के लिए तैयार है। कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रेटजी एंड बिजनेस डेवलपमेंट) लाल ने कहा कि हम तेजस के साथ-साथ एएमसीए परियोजना के लिए भारत सरकार या भारतीय वायुसेना की किसी भी जरूरत को पूरा करने में मदद के लिए तैयार हैं।

अहमदाबाद में बनाई जा रही 400 मीटर लंबी दीवार

अहमदाबाद, एजेंसियां : अहमदाबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंदिरा ब्रिज से जोड़ने वाले मार्ग के किनारे झुग्गी बस्ती है जिसमें तकरीबन 800 परिवार रहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसी रास्ते से 'केम छो ट्रंप' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगे। उनकी नजर इन झुग्गियों पर न पड़े इसके लिए इस बस्ती के बाहर सात फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह दीवार झुग्गियों को छिपाने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा कारणों से बनाई जा रही है।

तकरीबन 400 मीटर लंबी इस दीवार का निर्माण कर रहे ठेकेदार का बयान सरकारी अधिकारियों के दावे को झुठलाता है। ठेकेदार ने बताया, 'सरकार नहीं चाहती कि जब ट्रंप यहां से गुजरें तो उनकी नजर इन झुग्गियों पर पड़े। मुझे जल्द से जल्द इस दीवार का निर्माण कार्य पूरा करने का आदेश दिया गया है, लिहाजा 150 से ज्यादा मिस्त्री काम पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।'

हालांकि कुछ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह दीवार सौंदर्यीकरण और स्वच्छता अभियान का हिस्सा है। इस बाबत जब शहर के मेयर बिजल पटेल से सवाल किया गया तो उन्होंने इस संबंध में कोई जानकारी होने से इन्कार किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अहमदाबाद दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के लिए महानगरपालिका मलिन बस्ती के पास एक दीवार खड़ी कर रही है। प्रेट्र

न्यूज गैलरी

दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को महाराणा सम्मान

उदयपुर : महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन, उदयपुर के 38वें वार्षिक सम्मान समारोह के राज्यस्तरीय अलंकरणों की घोषणा गुरुवार को कर दी गई। 2020 के लिए महाराणा मेवाड़ सम्मान दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर अनंत विजय को दिया जाएगा। गाजियाबाद निवासी अनंत विजय के अलावा मुंबई के दादाराव बिल्होरे और करौली के पत्रकार प्रकाशचंद्र शर्मा को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सम्मान समारोह एक मार्च, 2020 को शाम 4.30 बजे सिटी पैलेस प्रांगण में आयोजित होगा। अनंत विजय को सामाजिक सौहार्द, पर्यावरण, महिला उत्थान, बाल कल्याण आदि के लिए सम्मानित किया जाएगा। (जेएनएन)

अनंत विजय।

आईशी घोष को कलकत्ता विवि कैंपस में सभा की अनुमति नहीं

कोलकाता : जेएनयू के छात्र संघ की अध्यक्ष आइशी घोष को कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) कैंपस में सभा करने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय कैंपस के गेट के बाहर ही सभा की। (जासं)

चीन से लाए गए लोगों को मिल सकती है 20 को छुट्टी

कोरोना वायरस का प्रकोप ▶ 645 भारतीय और विदेशी नागरिक चीन से लाए गए थे

निगरानी के लिए 16 हजार लोगों पर 28 दिनों से रखी जा रही थी नजर

नीलू रंजन, नई दिल्ली

चीन से लाकर सेना और आइटीबीपी के कैंप में रखे गए 645 भारतीय और सात मालदीव के नागरिकों को अगले 20 फरवरी को घर जाने की अनुमति दी जा सकती है। 15 फरवरी और 18 फरवरी को इन सभी लोगों का कोरोना वायरस का अंतिम परीक्षण किया जाएगा और टेस्ट निगेटिव आने की स्थिति में दो दिन बाद उन्हें घर जाने की इजाजत मिल सकती है। कोरोना वायरस के निपटने की तैयारियों की निगरानी के लिए मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दरअसल कोरोना वायरस से प्रभावित चीन के वुहान से एक और दो फरवरी को 645 भारतीयों को वापस लाकर मानेसर स्थित सेना और छावला स्थित आइटीबीपी के विशेष कैंपों में रखा गया था। माना जा रहा था कि इन लोगों को 14 दिनों तक अलग-थलग रखकर उनकी जांच की जानी थी। 14-15 फरवरी को इनका 14 दिन पूरा हो जाएगा। बीच में दोनों कैंपों में कुछ लोगों को जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद सफदरजंग और सेना के रेफरल हास्पीटल में विशेष निगरानी के लिए भी भेजा गया था। लेकिन उनके कोरोना वायरस के लिए अभी तक हुए सभी टेस्ट निगेटिव पाए गए हैं। 14 दिनों में कोरोना वायरस कमजोर हो जाता है और उसके दूसरे लोगों तक फैलने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे में यहां रखे गए लोगों को 15-16 फरवरी को घर भेजा जा सकता था। मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक में मौजूद में एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। यही कारण है कि 15 और 18 फरवरी को होने वाले टेस्ट के दो दिन बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत देने पर विचार किया जा रहा है।

वहीं, मंत्रिमंडलीय समूह की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सभी मंत्रालय पूरे सामंजस्य के साथ कोरोना से निपटने की तैयारियों में जुटे हैं। सभी चीनी नागरिकों के वीजा निलंबित करने और एडवाइजरी जारी करने के साथ-साथ लगभग चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले ढाई लाख से अधिक लोगों की एयरपोर्ट पर स्कीनिंग की गई है। आशंका के दायरे में आने वाले 15,991 लोगों पर 28 दिनों तक विशेष निगरानी रखी गई, जिनमें से अभी तक 3058 लोग 28 दिनों की निगरानी की सीमा पूरी कर चुके हैं। उनके अनुसार अभी तक केवल तीन लोग केरल में कोरोना वायरस से पीड़ित मिले हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। नेपाल के साथ खुली सीमा को देखते हुए वहां से सटे गांवों में ग्रामसभा के माध्यम से जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है और हर दिन की रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

नई दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना वायरस मामले पर बुलाई गई उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के दौरान। बैठक में वर्तमान स्थिति और रोकथाम के उपायों की समीक्षा की गई। प्रेट्र

कोलकाता एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग में दो और पॉजिटिव

जागरण संवाददाता, कोलकाता

बैंकॉक से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे दो यात्री कोरोना वायरस के लिए की गई थर्मल स्क्रीनिंग में कोरोना वायरस 'पॉजिटिव' पाए गए हैं। हवाई अड्डे के निदेशक कौशिक भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से बयान जारी कर इसका खंडन किया गया है। बयान में कहा गया कि कुछ डिजिटल न्यूज पोर्टल ने हवाई अड्डे के निदेशक के हवाले से दो यात्रियों के कोरोना वायरस के लिए की गई थर्मल स्क्रीनिंग में 'पॉजिटिव' पाए जाने की बात कही है। स्वास्थ्य विभाग आम लोगों को यह सूचित करता है कि बंगाल में अभी तक किसी को भी कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया है।

हवाई अड्डे के निदेशक के हवाले से दिया गया बयान तथ्यपूर्ण नहीं है और गलत है। हवाई अड्डे के निदेशक कौशिक भट्टाचार्य ने कहा कि थर्मल स्क्रीनिंग में हिमाद्री बर्मन और नगेंद्र सिंह नामक दो लोगों को पॉजिटिव पाया गया। दोनों को बेलियाघाटा आइडी अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले अनीता ओरांव नामक एक महिला यात्री को भी थर्मल स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाया गया था।

गौरतलब है कि केरल में इससे पहले तीन मामले सामने आ चुके हैं। तीनों चीन से केरल लौटे थे। पहले से ही दो एयरलाइनों ने कोलकाता-चीन के बीच उड़ानों को रद कर दिया है। इंडिगो ने भी 6 फरवरी से 25 फरवरी तक कोलकाता और गुआंगझू के बीच अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद कर दिया है। इंडिगो के बाद, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने 10 फरवरी से 29 फरवरी तक चीन के कुनमिंग से कोलकाता के बीच अपनी उड़ानों को स्थगित कर दिया। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और बैंकाक से कोलकाता आने वाली उड़ानों के यात्रियों का 17 जनवरी से स्क्रीनिंग की जा रही है। वर्तमान में हांगकांग, सिंगापुर और बैंकॉक से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है।

कोलकाता को एक और मेट्रो सेवा की सौगात

जागरण संवाददाता, कोलकाता

35 साल पहले जिस शहर में देश की पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, उसी कोलकाता को बेहद लंबी प्रतीक्षा के बाद एक और मेट्रो सेवा की सौगात मिली है। बहुप्रतीक्षित ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के पहले चरण का गुरुवार को रेलमंत्री पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया, वहीं समारोह के आमंत्रण पत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम नहीं होने को लेकर राज्य सरकार की तरफ से इसका बहिष्कार किया गया। समारोह में राज्य सरकार का कोई मंत्री, सांसद, विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वह केंद्र सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं से यहां की जनता को वंचित कर रही है। बंगाल में हम कई परियोजनाएं लाना चाहते हैं लेकिन यहां की सरकार इसे लाने नहीं दे रही। ममता सरकार नहीं चाहती कि गरीबों को इसका लाभ मिले। गोयल ने कहा कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना को अभी तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 15- 16 महीने पहले इस योजना के लागू होने के बाद से देश में एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन बंगाल सरकार इस योजना से यहां की जनता को वंचित कर रही है। उन्होंने आगे कहा- 'भाजपा का मूल सिद्धांत ही विकास है। ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना तेज गति से विकास के सपने को साकार करती है। पूर्वी भारत एवं उत्तर-पूर्व को विकास से वंचित रखा गया था। नरेंद्र मोदी सरकार के साढ़े पांच साल के कार्यकाल में वहां विकास हुआ है। केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ वहां के लोगों को ठगा है। पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता।

गोयल ने कहा कि जिस योजना से गरीब को फायदा हो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का भी जिक्र करते हुए कहा कि ममता सरकार ने बंगाल के एक भी किसान को अब तक इस योजना का लाभ नहीं लेने दिया। देशभर के किसान इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल के किसानों को इससे क्यों वंचित किया जा रहा है।

परियोजना के उद्घाटन के आमंत्रण को लेकर विवाद

जागरण संवाददाता, कोलकाता

उद्घाटन समारोह में ममता बनर्जी का नाम आमंत्रण पत्र व मेट्रो रेलवे की ओर से जारी विज्ञापन में नहीं होने को लेकर राज्य व केंद्र में ठन गई। हालांकि, तृणमूल के स्थानीय सांसद काकोली घोष दस्तीदार व विधायक तथा राज्य के मंत्री सुजीत बसु का नाम आमंत्रण पत्र और विज्ञापन में था। लेकिन सीएम का नाम नहीं होने को लेकर विवाद गहरा गया और ममता के वरिष्ठ नेताओं ने समारोह में हिस्सा नहीं लिया। वहीं तृणमूल ममता सरकार की दलील है कि पूरी तरह से राज्य को अंधकार में रख कर उद्घाटन की योजना तैयार की गई। हालांकि मेट्रो रेलवे का कहना है कि बुधवार रात उनके अधिकारी खुद राज्य सचिवालय नवान्न जाकर मुख्यमंत्री को आमंत्रित किए हैं।

मेट्रो रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के निर्देश पर बुधवार को राज्य सचिवालय नवान्न जाकर मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया किया, जिसे वहां के सचिव ने स्वीकार भी किया था। इसके अलावा गुरुवार को भी फोन कर उन्हें आमंत्रित किया गया। इधर, विपक्ष ने भी इस घटना की निंदा करते हुए असभ्य करार दिया है। इस बारे में माकपा नेता ने कहा कि राज्य में ईस्ट-वेस्ट मेट्रो के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री को ही आमंत्रित न किया जाए यह असभ्यता का प्रतीक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हम इसका समर्थन नहीं करते।

विनय का नया पैंतरा, बोला मानसिक रूप से अस्वस्थ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

▶ सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने की इजाजत मांगने वाली केंद्र की याचिका पर भी आज ही सुनवाई

दिल्ली दुष्कर्म कांड के दोषी मृत्युदंड से बचने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। दोषी विनय शर्मा की ओर से राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को गलत बताते हुए कहा गया कि जेल में उसे प्रताड़ित किया गया। इस कारण वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है और राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज करते वक्त उसके मानसिक तौर पर अस्वस्थ होने के पहलू पर विचार नहीं किया। दूसरी ओर, केंद्र और दिल्ली सरकार ने विनय के दावे का विरोध करते हुए कहा कि वह पूरी तरह फिट और स्वस्थ चित्त है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विनय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगा।

इसके अलावा, केंद्र और दिल्ली सरकार की दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सरकार ने याचिका में सभी दोषियों को एक साथ फांसी दिए जाने के हाईकोर्ट के आदेश का विरोध किया है। साथ ही कहा कि जिन दोषियों के कानूनी विकल्प समाप्त हो गए हैं, उनकी फांसी की सजा पर अमल करने की इजाजत दी जाए। गुरुवार को कोर्ट ने चारों दोषियों को सरकार की याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक का समय दे दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पवन की ओर से कोई वकील पेश न होने पर वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश को पवन का वकील नियुक्त करते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी।

गुरुवार को कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। विनय के वकील एपी सिंह ने दया याचिका खारिज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उप राज्यपाल ने दया याचिका प्रेषित करने की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। वकील ने कोर्ट से फाइल दिखाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। परंतु सरकार की ओर कोर्ट मे ओरिजनल फाइल पेश की जिसे कोर्ट ने देखा। कोर्ट ने फाइल देखकर पाया कि उस पर दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री और उपराज्यपाल के हस्ताक्षर थे।

वकील एपी सिंह ने कहा कि विनय शर्मा को जेल में बहुत प्रताड़ित किया गया जिसके कारण वह मानसिक रूप से बीमार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विनय के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि वह पूरी तरह फिट और स्वस्थ चित्त है।

निर्भया के दोषियों के खिलाफ जारी नहीं हो सका डेथ वारंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ अदालत ने दोषी पवन गुप्ता के लिए नियुक्त किया अधिवक्ता

▶ 17 फरवरी को होगी दिल्ली सरकार और परिजनों की अर्जी पर सुनवाई

निर्भया के गुनहगारों के लिए नया डेथ वारंट गुरुवार को भी जारी नहीं हो सका। दिल्ली सरकार और निर्भया के परिजनों की अर्जी पर लंबी बहस के बाद पटियाला हाउस की एक अदालत ने सुनवाई 17 फरवरी के लिए टाल दी। अर्जी में डेथ वारंट जारी करने की मांग की गई है। अदालत ने दोषी पवन गुप्ता के लिए अधिवक्ता नियुक्त कर दिया है।

मालूम हो कि दोषी पवन गुप्ता ने अपने पुराने अधिवक्ता एपी सिंह से खुद को अलग कर लिया था। विधिक सेवा प्राधिकरण को भी अधिवक्ता नियुक्त करने से मना कर दिया था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत अधिवक्ताओं की सूची पवन को दी गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पवन गुप्ता कानूनी प्रक्रिया में देरी कर रहा है। हालांकि अनुच्छेद 21 किसी भी दोषी को अंतिम सांस तक कानूनी मदद की अनुमति देता है।

निर्भया के दोषियों में सिर्फ पवन के पास ही दो कानूनी विकल्प बचे हैं। वह क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका दायर कर सकता है। चूंकि अब उसका पक्ष रखने के लिए कोई वकील नहीं है, ऐसे में उसे वकील मुहैया कराए गए हैं। दोषी विनय के अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को फैसला आना है। विनय की दया याचिका खारिज होने को चुनौती देते हुए रिव्यू पिटिशन दायर की गई थी।

भावनाओं के आधार पर जारी नहीं हो सकता डेथ वारंट

इन दलीलों के बाद जज ने कहा कि डेथ वारंट जारी करना बेहद संवेदनशील विषय है और यह भावनाओं के आधार पर जारी नहीं हो सकता। दोषी को पूरा हक है कि वह अपनी बात अदालत में रखे। इसलिए सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी।

रैली

कांग्रेस व बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बरसे गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी

सीएए के समर्थन में दो किमी लंबा तिरंगा लेकर निकले लोग

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

राजकोट में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में लोगों ने दो किलोमीटर लंबा तिरंगा लेकर रैली निकाली। बहुमाली भवन से दो किलोमीटर लंबे तिरंगे को लेकर शहर के नागरिक, बच्चे व एनसीसी कैडेट निकले और करीब पांच किमी चलकर गांधी म्यूजियम तक पहुंचे। तिरंगा एकता समिति ने यह तिरंगा यात्रा आयोजित की थी। सीएए के समर्थन में सूरत, भावनगर, कडी, भरुच आदि शहरों में रैलियां निकाली जा चुकी हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि पूर्व के शासकों ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम नहीं किया। मोदी व शाह ने वर्षों पुरानी समस्याओं का निराकरण कर कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बनाया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी देश का बंटवारा करने की धमकी देने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय उत्पीड़न का शिकार है। कई परिवार संपत्ति व सामान छोड़कर भारत आए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्हें यहां की नागरिकता नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग देश को तोड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन उनके सपने साकार नहीं होने देंगे। रूपाणी ने कहा कि भाजपा के चुनावी एजेंडे में कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करना, एक साथ तीन तलाक, नागरिकता संबंधी वादे किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा पूरा किया है। रूपाणी ने युवाओं व महिलाओं से नए मजबूत भारत के लिए सीएए का समर्थन करने की अपील की।

जेएनयू पहुंचे चिदंबरम ने कहा, जारी रहेगा सीएए का विरोध

जासं, नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) स्थित साबरमती छात्रावास में गुरुवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और एनपीआर के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। चिदंबरम ने जेएनयू के विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि कानून बनाना ही था तो देश के शरणार्थियों के लिए बनाया जाता तो सही होता। देशभर में सीएए-एनआरसी के खिलाफ लोग विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है और एनआरसी व एनपीआर की लड़ाई जनता और राज्य सरकारें लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस लड़ाई में प्रदर्शनकारियों के साथ है।

शाहीन बाग भाजपा का जाल है, इसलिए हमने दूरी बनाई। भाजपा इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। इसी के चलते कांग्रेस नेता शाहीन बाग जाने से बच रहे हैं कि हम भाजपा के ही जाल में न फंस जाएं।

गुजरात के राजकोट में गुरुवार को सीएए के समर्थन में दो किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जागरण

सीएए विरोध के नाम पर उपद्रव करने वाले 13 लोगों से वसूले जाएंगे 21.76 लाख

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सीएए के विरोध में लखनऊ को हिंसा की आग में झोकने वाले 13 उपद्रवियों से 21.76 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। सात लोगों को साक्ष्य के अभाव में राहत भी मिली है। एडीएम कोर्ट ने उपद्रवियों को अर्थदंड जमा करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। तय समय में अर्थदंड जमा न करने पर संपत्ति कुर्क होगी। लखनऊ में सीएए के विरोध में 19 दिसंबर को विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए प्रदर्शन के दौरान हिंसा व उपद्रव हुआ था। इसमें करीब पांच करोड़ रुपये की संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया गया था। इसी क्रम में एडीएम कोर्ट ने लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र के लिए गुरुवार को आदेश जारी किया है। इस क्षेत्र में कुल 20 उपद्रवियों को रिकवरी का नोटिस जारी हुआ था। इनमें से सात के खिलाफ पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा सकी। 19 दिसंबर को अन्य थाना क्षेत्रों में हुए उपद्रव की जांच भी अलग-अलग कोर्ट में चल रही है। हिंसा में चार थाना क्षेत्रों हजरतगंज, कैसरबाग, ठाकुरगंज और हसनगंज में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर करीब 35 वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। हसनगंज थाना क्षेत्र के मदेयगंज और ठाकुरगंज की सतखंडा चौकी को आग के हवाले किया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

1992 में पहली बार पकड़ा गया था बडगाम निवासी अब्दुल गनी डार को। जेल से रिहा होने के बाद फिर आतंकी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। वर्ष 2002 में उसे बीएसएफ ने लालचौक के पास पकड़ा था।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 14 फरवरी 2020

टिड्डियों से दुनिया में फैल सकती है भुखमरी

150 अंडे
एक टिड्डी एक दिन में दे देती है

20 गुणा
इतनी रफ्तार से अपनी जनसंख्या बढ़ाती हैं टिड्डियां

दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस के खौफ में है तो दूसरी तरफ 'प्लेग' की चपेट में है। थोड़ा रुकें, 'प्लेग' को चूहे से जुड़ी वाली महामारी न समझें, बल्कि यह टिड्डी दलों ने जैसे हालात पूरी दुनिया में पैदा कर दिए हैं उसे बताने वाला मात्र एक विशेषण है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने इस्तेमाल किया है। एफएओ ने आधिकारिक रूप से चेतावनी दी है कि टिड्डियों के कारण दुनिया भुखमरी के कगार पर पहुंच रही है। हालात यह है कि 60 देश टिड्डी दलों के हमलों से पीड़ित हैं, जो कोरोना वायरस से पीड़ित देशों की संख्या से कही अधिक है।

पाक गंभीर संकट में

हमारा पड़ोसी पाकिस्तान तो टिड्डियों के आगे घुटने टेकने की स्थिति में पहुंच गया है और इमरान खान सरकार ने आपातकालीन कदम भी उठाए हैं। महंगाई सातवें आसमान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान और सोमालिया ने परेशान होकर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। भारत में भी हालात खराब हैं। गुजरात और राजस्थान में संकट को राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है, जबकि अब पंजाब और हरियाणा में टिड्डी दल पहुंच गए हैं, जो पूरे भारत को खाना खिलाते हैं।

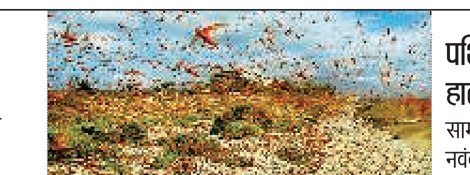

अच्छा मानसून बन गया मुसीबत

अफ्रीका की तरफ से आने वाली टिड्डियों को नम मौसम पसंद है।भारतीय उपमहाद्वीप में वर्ष 2019 में मानसून अच्छा रहा। मानसून जल्दी आया और देर तक रहा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इस बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हालात टिड्डियों के माकूल रहा और अंजाम दिसंबर-जनवरी में भयानक रूप से सामने आया।

पश्चिमी विक्षोभ ने हालात किए बदतर

सामान्य रूप से टिड्डी दल नवंबर के अंत तक भारत छोड़ देते हैं और ईरान की तरफ चले जाते हैं। हालांकि इस बार दिसंबर और जनवरी में भी अच्छी बारिश हुई, जिसका कारण पश्चिमी विक्षोभ था। पश्चिमी विक्षोभ में हवा अफगानिस्तान-पाकिस्तान की तरफ से आती है। ऐसे में टिड्डी दल भारतीय उपमहाद्वीप में ही रह गए।

बहुत पेटू हैं टिड्डियां

एक सेमी. से लेकर अधिकतम चार सेमी लंबी टिड्डियां किस कदर भूखी होती हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि छोटे आकार (चार करोड़ टिड्डियां) का एक टिड्डी दल एक दिन में उतना खाद्य पदार्थ खा जाता है, जिससे 35 हजार लोगों का पेट आसानी से दिन में दो बार भरा जा सकता है।

खुद खाना बन जाती हैं टिड्डियां

टिड्डियों को पूरी दुनिया की विभिन्न हिस्सों में खाद्य पदार्थ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, खासकर एशिया और अफ्रीका में। चीन और आसपास के देशों में इन्हें खाया जाता है।

कठिन काम है नियंत्रण पाना

महंगे कीटनाशकों की मदद से इन्हें नियंत्रित किया जाता है, लेकिन बड़े भाग में ज्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत महंगा साबित होता है, जिसे भारत जैसे देश के किसान नहीं उठा पाते हैं। वैसे शोर मचाकर भी टिड्डियों को भगाने की परंपरा है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। गुजरात, राजस्थान में इन्हें भगाने के लिए थाली बजाई जाती है।

15 करोड़
टिड्डियां हो सकती हैं मध्यम आकार के एक दल में

40%
फसल पाकिस्तान में नष्ट हो चुकी है

35 हजार
हेक्टेयर में लगी फसल भारत में हो चुकी है बर्बाद

3.5 लाख
हेक्टेयर में लगी फसल बर्बादी के कागर पर

5 करोड़
लोगों का पेट भर सकती थीं दुनिया में खराब हुई फसलें

01 हजार वर्ग किमी
क्षेत्र की फसलों को टिड्डियों का बड़ा दल एक दिन में कर सकता है चट

जम्मू-कश्मीर उन्नति और बेहतरी की ओर अग्रसर

मिला साथ ▶ विदेशी राजनयिकों ने जम्मू में प्रशासनिक अधिकारियों से की मुलाकात, कहा-लोगों के जीवन में हो रहे हैं सकारात्मक बदलाव

जम्मू के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर लोगों की आकांक्षाओं को भी जाना

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे विदेशी राजदूतों दूसरे 25 सदस्यीय दल ने गुरुवार को उप राज्यपाल जीसी मुर्मू (बाएं से दूसरे) के साथ बैठक की। एएनआइ

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने के बाद उपजे हालात का जायज लेने दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेशी राजनयिकों ने गुरुवार को जाने से पूर्व कहा कि जम्मू-कश्मीर बेहतरी और उन्नति की ओर अग्रसर है और यहां जरूरी परिवर्तन हो रहे हैं। इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

दो दिवसीय दौरे के दौरान 25 विदेशी राजनयिकों ने बुधवार को कश्मीर घाटी का दौरा किया था, जबकि गुरुवार को उन्होंने जम्मू पहुंचकर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाज के बुद्धिजीवी लोगों से भी मुलाकात की। विदेशी राजनयिकों के दल में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, मेक्सिको, इटली, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, डॉमनिक रिपब्लिक, युगांडा, चेकोस्लोवाकिया, नीदरलैंड, नामीबिया, रवांडा और खाड़ी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे।

इससे पूर्व गुरुवार सुबह जम्मू पहुंचे यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के राजदूतों, राजनयिकों ने जम्मू में उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें की। इसके अलावा पूरा दिन जम्मूवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर जनआकांक्षाओं को जाना। उन्होंने शाम पांच बजे तक जम्मू शहर के एक होटल में स्थानीय व्यापारियों, समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर जनआकांक्षाओं, पर्यटन, विकास, खेल और शिक्षा जैसे मुददों पर उनका पक्ष जाना। दौरे पर आए विदेशी मेहमानों ने स्थानीय लोगों से पाक प्रायोजित आतंक, घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों और पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के दर्द को भी समझा। लोगों ने बताया कि अनुच्छेद 370 हटाकर पुरानी गलती सुधारी है। इसके अलावा लोगों ने कश्मीर केंद्रित सरकारों द्वारा जम्मू से किए भेदभाव की जानकारी भी दी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने राजनयिकों को अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की मुहिम की जानकारी दी।

आतंकवाद के मुद्दे पर जानी लोगों की राय : विदेशी राजनयिकों ने कश्मीरी पंडितों, सभ्य सामाज, गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों, वाल्मीकि समाज, गुज्जर-बक्करवालों, शिक्षाविदों, पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों, गोरखा समाज के प्रतिनिधियों ने अलग-अलग बैठकें कर जम्मू-कश्मीर के बदलाव पर उनकी राय भी जानी। इसके अलावा विदेशी राजनयिकों ने एक साथ प्रतिनिधिमंडल में शामिल 37 लोगों से अनुच्छेद 370 हटने, शासन से उम्मीदों व पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे मुद्दों पर राय ली। इस दौरान लोगों ने कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल में जम्मू को रोजगार, विकास में नजरअंदाज करना और पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को जम्मू-कश्मीर की नागरिकता से वंचित रखने के मुद्दे भी उठा।

नागरिकता संशोधन कानून पर हालात जानें : विदेशी राजनयिकों ने अनुच्छेद-370 हटने से उपजे हालात से अधिक महत्व नागरिकता संशोधन कानून पर जम्मू के लोगों की राय जानने पर दिया। लोगों ने उन्हें बताया कि पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, इसी लिए इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। इस कानून से पश्चिम पाकिस्तान से 70 साल पहले आए रिफ्यूजी बनकर रह रहे लोगों के साथ इंसाफ हुआ है। विदेशी राजनयिकों ने भारत के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी वह ऐसे ही प्रयास जारी रखेगा।

मेक्सिको के राजदूत लोफे ने कहा-आ रही शांति

भारत में मेक्सिको के राजदूत एफएस लोफे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति आ रही है। इसकी स्थिति कश्मीर और जम्मू में बैठकें करने के बाद स्पष्ट हुई है। कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन लोग बेहतर हालात चाहते हैं और अधिकारी उसी कोशिश में जुटे हैं। वहीं, भारत में डॉनमिक रिपब्लिक के राजदूत हैंस डेननबर्ग कास्टेलानोस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में विकास के रोडमैप पर काम हो रहा है। प्रशासन के पास पूरा खाका है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश व मुख्यसचिव से बैठकें कामयाब रहीं।

सेना ने दी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर राज्य के हालात का जायजा लेने आए यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के लगभग 25 राजदूत व राजनयिकों ने गुरुवार को जम्मू रवाना होने से पूर्व चिनार कोर कमांडर सहित सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान चिनार कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने राजनियकों और राजदूतों को कश्मीर घाटी में पाक प्रायोजित जिहादी तत्वों की गतिविधियों, एलओसी पर पाक द्वारा बार-बार जंगबंदी के उल्लंघन करने और आतंकियों की घुसपैठ की कोशिशों और उन्हें नाकाम बनाने की भारतीय सेना की रणनीति से अवगत कराया। विदेशी राजदूतों और राजनियकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कोर कमांडर ने उन्हें घाटी के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में सेना द्वारा संचालित स्कूलों, सद्भावना अभियान और स्थानीय युवकों को आतंकियों की चंगुल से मुक्त करने के प्रयासों से भी अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन होने के बाद कश्मीर में अलगाववादी तत्वों की लोग खुलकर नकारने लगे हैं।

पुलवामा में आज देश को समर्पित होगा शहीद स्मारक स्थल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : पुलवामा के लिथपोरा में गत वर्ष आत्मघाती हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों के नाम पर बने शहीद स्मारक को शुक्रवार को राष्ट्र के नाम समर्पित किया जाएगा। यह स्माकर स्थल लिथपोरा स्थित सीआरपीएफ शिविर में है। सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने कहा कि 14 फरवरी 2019 को शहीद हुए जवानों को यह श्रद्धांजलि है। शहीद स्मारक स्थल पर सभी शहीदों के नाम व तस्वीरें होंगी। इसके साथ स्मारक स्थल पर सीआरपीएफ का लक्ष्य सेना और निष्ठा लिखा है। यह दुर्भाग्यजनक घटना थी। इससे हमने अपने लिए एक सबक लिया है। हम हमेशा से ही अपने जवानों व अधिकारियों की आवाजाही के समय पूरी सतर्कता बरतते रहे हैं।

जेके-पीएसए को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके जम्मू-कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम (जेके-पीएसए), 1978 को चुनौती दी गई है। अनुच्छेद-370 हटने के बाद इसी कानून के तहत कई नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मुख्य संरक्षक भीम सिंह ने दाखिल की है। वह वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। याचिका में उन्होंने कानून को 'मृत' बताते हुए इसे गैरकानूनी घोषित करने की मांग की है।

चावला से पूछताछ में खुलेंगे कई पूर्व खिलाड़ियों व सटोरियों के राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

19 साल बाद लंदन से दिल्ली लाए गए सटोरिये संजीव चावला से पूछताछ में कई पूर्व भारतीय खिलाड़ियों, बड़े सटोरियों और दलालों के काले कारनामों से पर्दा उठ सकता है। डीसीपी क्राइम ब्रांच डॉ. जी राम गोपाल नाइक के मुताबिक क्रिकेट मैच फिक्सिंग के मास्टरमाइंड संजीव से कई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।

जुलाई 2013 में क्राइम ब्रांच ने मैच फिक्सिंग के इस केस में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनिए व संजीव चावला समेत छह लोगों को आरोपित बनाते हुए दिल्ली की एक निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। हैंसी क्रोनिए की 2002 में विमान हादसे में मौत हो चुकी है। इसके बाद बचे आरोपितों में संजीव समेत तीन बुकी व दो दलाल शामिल हैं। दो सटोरियों और एक दलाल को क्राइम ब्रांच ने कई साल पूर्व गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में जमानत भी मिल गई। एक आरोपित मनोहर खट्टर अभी फरार है।

चार्जशीट में बताया गया था कि ब्रिटिश नागरिक चावला भारतीय खिलाड़ियों सहित कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों के साथ जुड़ा हुआ था। उनके नंबर कॉल डेटा रिकॉर्ड्स (सीडीआर) से पता चला था कि कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर उसे लंदन में लगातार फोन कर रहे थे। पुलिस ने जनवरी से मार्च 2000 तक चावला के सीडीआर निकाले थे। उस समय भारत में खेले जाने वाली भारत-दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला के मैच फिक्स करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद चावला लंदन भाग गया, जिस कारण तत्कालीन भारतीय क्रिकेटरों को वैश्विक सट्टेबाज से जोड़ने वाले सीडीआर को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका था।

लंदन में 2001 में गिरफ्तार हुआ था चावला : क्राइम ब्रांच ने स्कॉटलैंड यार्ड से भी दस्तावेज जुटाए थे। वहां की एजेंसी ने 2001 में वहां के खिलाड़ियों से जुड़े एक और सट्टेबाजी रैकेट में चावला को गिरफ्तार किया था।

अंडरवर्ल्ड से संबंधों की भी होगी जांच

दुबई स्थित सट्टे के सिंडिकेट्स के साथ चावला के संबंधों के बारे में दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक सदस्य द्वारा इस्तेमाल किए गए एक यूएई नंबर को शुरुआत में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रेस किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच चावला से पूछताछ कर अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों की भी जांच करेगी। वहीं चावला के सहयोगियों में से एक कृष्ण कुमार (टी-सीरीज म्यूजिक ग्रुप) के फोन नंबर को सीधे तौर पर 2000 की शुरुआत में दुबई में सक्रिय अंडरवर्ल्ड के सदस्य सहेन हेथली के फोन नंबर से जोड़ा गया था।

1996 में पहली बार ब्रिटेन गया था चावला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

चावला दिल्ली का बिजनेसमैन था। उन दिनों उसकी गिनती देश के टॉप क्रिकेट मैच फिक्सरों में थी। क्राइम ब्रांच का कहना है कि चावला पहली बार 1996 में बिजनेस वीजा पर ब्रिटेन गया था। उससे हैंसी क्रोनिए की सीधी बात होती थी। चावला ने हैंसी से कहा था कि तीसरे टेस्ट में भारत की जीत सुनिश्चित करने के लिए अंतिम दिन अगर उसकी टीम ऑल आउट हो जाती है तो वह उसे 30 हजार डॉलर देगा। केस दर्ज होने के बाद हैंसी पर आजीवन क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लग गया था। मैच फिक्सिंग में हैंसी के साथ हर्शल गिब्स व निकी बोए समेत दक्षिण अफ्रीका के कई खिलाड़ियों के नाम आए थे।

2000 में हुई थी क्रोनिए की मौत : एक जून 2002 को विमान हादसे में हैंसी क्रोनिए की मौत हो गई, जिससे मैच फिक्सिंग की जांच रुक गई थी। क्राइम ब्रांच ने विदेश मंत्रालय के जरिए लंदन की कोर्ट से चावला को सौंपने का अनुरोध किया था। कहा गया था कि चावला को तिहाड़ जेल में ठीक तरीके से रखा जाएगा। उसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखा जाएगा। तब चावला ने तर्क दिया था कि भारत की जेल में उसकी जान को खतरा है। वहां उसके मावनाधिकार का हनन हो सकता है।

पूर्व आतंकी कमांडर अब्दुल्ला गजाली की मस्जिद में हत्या

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर के सबसे पुराने आतंकी कमांडरों में शुमार जमीयत-ए-अहल-हदीस के नेता अब्दुल गनी डार उर्फ अब्दुल्ला गजाली की गुरुवार को एक मस्जिद में हत्या कर दी गई। दोपहर बाद उसका खून से सना शव नमाजियों ने एक कोने में पड़ा देखा। फिलहाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। अब्दुल गनी डार उर्फ अब्दुल्ला गजाली की हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं है।

सूत्रों ने बताया कि अब्दुल गनी डार दोपहर में ही मस्जिद में आया था। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि हेलमेट पहने एक युवक से उसका झगड़ा हुआ था। दोनों में हाथापाई कैमरे में कैद हो गई। हमले के बाद गजाली जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर निकलने में कामयाब रहा। पुलिस थाना प्रभारी जहूर अहमद ने कहा कि कुछ संदिग्ध तत्वों की निशानदेही की गई है। गजाली आतंकी संगठन तहरीक-उल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर रह चुका है। उसका कश्मीर में पांव पसार रहे अल-कायदा और आइएसजेके से भी जुड़ाव बताया जाता रहा है। उसके दामाद एजाज अहमद अहंगर उर्फ हुजैफा अल पाकिस्तानी को आइएसजेके का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। गजाली की हत्या लालचौक के साथ सटे मैसूमा में स्थित उसी मस्जिद के भीतर हुई है, जिसके बाहर अप्रैल 2011 में एक शक्तिशाली आइईडी विस्फोट में जमीयत के तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रमुख मौलाना शौकत की हत्या हुई थी। मौलाना की हत्या की साजिश लश्कर ने रची थी और गजाली भी आरोपित था।

एक साल बाद भी पुलवामा हमले में दायर नहीं किया जा सका आरोपपत्र

नवीन नवाज, श्रीनगर

▶ मारे जा चुके हैं साजिश अंजाम देने वाले सभी प्रमुख सूत्रधार

▶ हमले के अगले दिन हुई बारिश के कारण धुल गए थे कई अहम सुराग

देश को दहला देने वाले पुलवामा हमले को आज एक साल हो गया। इसके बावजूद अभी तक मामले में आरोपपत्र तक दायर नहीं किया जा सका है। साजिश को अंजाम देने वाले ज्यादातर सूत्रधार या तो ढेर हो चुके हैं या फिर पाकिस्तान में हैं। ऐसे में जिंदा सुबूत की अभी तलाश है। हालांकि जांच एजेंसियों के पास आत्मघाती हमलावर आदिल का वीडियो है।

जांच से जुड़ी एजेंसियों के अनुसार, फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है, लेकिन हमले में इस्तेमाल उच्च गुणवत्ता वाले विस्फोटक की सही प्रकृति और स्रोत का पता नहीं चल पाया है। इसका कारण हमले के अगले दिन हुई बारिश में कई अहम सुराग धुलना बताया जा रहा है।

14 फरवरी 2019 को श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर पुलवामा में जैश के आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ की बस पर विस्फोटकों से भरी कार के साथ टक्कर मारी थी। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले में आदिल डार के भी परखच्चे उड़ गए थे।

90 दिन में आरोपपत्र दायर करना होता है : गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत जांच एजेंसी को 90 दिन के भीतर अदालत में आरोपपत्र दायर करना होता है। जांच से जुड़े अधिकारियों की मानें अगर आरोपित या संदिग्ध की मौत हो चुकी हो तो आरोपपत्र दायर करने की समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। पठानकोट एयरबेस का हवाला देते हुए संबंधित अधिकारी कहते हैं कि वह हमला भी जैश ने करवाया था। दोनों की साजिश पाक में ही रची गई। पठानकोट हमले में शामिल चारों आतंकी मारे गए थे और आरोपपत्र लगभग एक साल के बाद दायर किया। उसमें मसूद अजहर व उसके तीन अन्य साथियों को आरोपित बनाया है। वे सभी पाकिस्तान में हैं।

अंजाम तक पहुंचे मास्टरमाइंड : पुलवामा की साजिश को अंजाम देने वाला पाकिस्तानी आतंकी गाजी रशीद 18 फरवरी 2019 को मारा गया था। मुदस्सर अहमद खान मार्च 2019 और सज्जाद खान जून 2019 में मारा गया। मुदस्सर ने ही विस्फोटकों को बंदोबस्त किया था। हमले में इस्तेमाल कार सज्जाद की थी। यह कार चार फरवरी 2018 को खरीदी गई थी। मुदस्सर और सज्जाद पुलवामा के रहने वाले थे। आदिल भी पुलवामा के गुंडीबाग का रहने वाला था।

सभी आतंकी मारे जा चुके हैं : जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, हमले को अमलीजामा पहनाने में लिप्त सभी प्रमुख आतंकी मारे जा चुके हैं। आरोपपत्र में सभी आरोपितों की भूमिका का विस्तार से जिक्र करना होता है। कुछ संदिग्धों को चिह्नित करते हुए उनकी भूमिका के आधार पर जल्द आरोपपत्र दायर करेंगे। साजिश में मसूद अजहर और पाकिस्तान में बैठे साथी भी शामिल थे। आरोप पत्र में पाकिस्तान की भूमिका का उल्लेख होगा। जल्द ही आरोपपत्र दाखिल होगा।

कुछ कड़ियां जोड़नी अभी बाकी : सूत्रों के अनुसार, फोरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है। विस्फोटक कहां से कैसे आया? पैसा किस स्रोत से आया? अभी इन कड़ियों को जोड़ना है। पुलवामा हमले में पाक सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का हाथ है। अधिकारियों ने मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि कसाब जिंदा पकड़ा गया था। पुलवामा की साजिश में शामिल आतंकी ढेर हो चुके हैं। गत माह त्राल में मारा गया कारी यासिर मददगार साबित हो सकता था, लेकिन वह भी जिंदा नहीं मिला।

आदिल के डीएनए की रिपोर्ट मिली 10 माह बाद

पुलवामा हमले में शामिल आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार के डीएनए नमूनों की जांच पूरी हो चुकी है। हमले में कार और उसमें सवार आदिल के परखचे उड़ गए थे। आदिल के मांस के लोथड़े को घटनास्थल के आस-पास बिजली के तार, पेड़ों की शाखाओं और कार के मलबे से जमा किया था। इनका आदिल के पिता और मां के डीएनए से मिलान किया गया। गत दिसंबर में ही रिपोर्ट आई है और उसके मुताबिक आदिल डार की पुष्टि हो चुकी है।

पुलवामा का एक साल

अतीत को भुला तरक्की की राह पर नया कश्मीर

हड़ताल, आजादी व अलगाववाद पर नहीं नए कश्मीर पर होती है बहस, अब सेना के करीब आए कश्मीरी, मुश्किल आने पर करते हैं संपर्क, पुलवामा हमला और अनुच्छेद 370 हटने से बदले समीकरण

नवीन नवाज, श्रीनगर

कश्मीर की आबोहवा में बदलाव को सीधा महसूस किया जा सकता है। पहले की तरह हड़ताल, आजादी और अलगाववाद से जुड़े मुद्दों पर अब कोई बात करता नजर नहीं आता। अगर कभी दो लोगों के बीच इन मुद्दों पर बहस शुरू भी होती है तो यह कहकर बात खत्म हो जाती है, बीते 70 वर्षों में क्या पाया, सिर्फ गंवाया है। अब पाने के वक्त है इसलिए अतीत को भुला अमन, ऐसे में अगर कुछ करना है तो यह करो कि जिहादियों के दुष्प्रचार से गुमराह हो तबाही के रास्ते पर निकले युवकों को वापस लाने में सहयोग करो।

बीते एक साल में कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है। पुलवामा हमले और अनुच्छेद-370 हटने के बाद लोगों की सोच बदली है। एक दुकानदार जावेद नक्शबंदी ने कहा कि कश्मीर में आज जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमने सबकुछ खोया है। लाल दस्तकारी की दुकान चलाने वाले जावेद कहते हैं कि पुलवामा हमला जब हुआ तो हम बहुत डर गए थे। हमें लगता था कि कश्मीर कभी नहीं बदलेगा। फिर पिछले अगस्त आया और अनुच्छेद-370 को ले उड़ा और कश्मीर बदलने लगा। आज किसी को पूछोगे हड़ताल कब है, तो जवाब मिलेगा जाओ अपना काम करो। जबकि पहले हड़ताल की अफवाह पर ही कारोबार बंद हो जाते थे।

केंद्र से वादे पूरे करने की दुहाई : पत्रकार : रमीज ने कहा कि कश्मीर के आज स्वायत्तता, स्वशासन, आतंकवाद व पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर नहीं रोजगार-विकास से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती है। हां, बहस में कई बार लोग पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर के विभाजन पर जरूर रोष जताते हैं। इसके साथ वह केंद्र सरकार को अपने वादों को पूरा करने की दुहाई देते हुए कहते हैं कि चलो अब यहां रोज-रोज उठाने वाले जनाजे बंद होंगे। क्योंकि कोई पुलवामा जैसा हमला नहीं चाहता।

70 वर्षों में कश्मीरियों ने सिर्फ गंवाया है : सैफुल्लाह जो पहले आतंकवाद की राह पर चल पड़े थे, लेकिन जब हकीकत पता चली तो घर लौट आए। वह कहते हैं कि पुलवामा हमला और उसके बाद अनुच्छेद-370 की समाप्ति कश्मीर के लिए वरदान साबित हुई है। जिस समय पुलवामा हमला हुआ तो यहां कई लोग कहते थे कि कश्मीर अब अफगानिस्तान बन रहा है, इसे रोको। अब वही लोग कहते हैं कि 70 वर्षों में कश्मीरियों ने सिर्फ गंवाया है।

कश्मीरी हमेशा से ही राष्ट्रभक्त : डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गुलाम हसन मीर ने कहा कि कश्मीरी हमेशा से ही राष्ट्रभक्त रहे हैं। लेकिन अलगाववाद की सियासत से ही कश्मीरी तंग थे। आपने देखा होगा कि अब कश्मीर के कई नए-पुराने सियासतदान पूर्ण राज्य, रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि यही मुद्दे उन्हें यहां प्रासंगिक रखेंगे, अन्यथा लोग उन्हें दरकिनार कर देंगे। समाजसेवी सलीम रेशी ने कहा कि पहले जब हम आम लोगों के बीच जाते थे तो पता चलता था कि लड़के जिहादी बन रहे हैं। जबकि अब कहा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो। नंबर अच्छे होने चाहिए। आतंक की राह पर भटके युवाओं को वापस लाने के लिए लोग खुद पुलिस व सेना से संपर्क करते हैं।

आइएएस बनने का जुनून

शिक्षाविद् मुहम्मद राही ने कहा कि क्या यह बदलाव नहीं है। आतंकवाद से सबसे अधिक ग्रस्त रहे दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में इन दिनों युवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा और कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने का जुनून है। जिला प्रशासन शोपियां ने युवाओं को अधिकारी बनाने के लिए पहल की है।

पुंछ के जंगलों में आतंकी ठिकाना ध्वस्त

जागरण संवाददाता, पुंछ

पुंछ जिले के दूरदराज के इलाके में मंगनाड और खनेतर टॉप के जंगली इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों ने एक आंतकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही आतंकी ठिकाने से हथियार भी बरामद कर लिए हैं। इलाके में संदिग्धों के देखे जाने की सूचना के बाद पिछले तीन दिन से सुरक्षाबलों और पुलिस जवान संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाए हुए थे।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई गोलाबारी के बाद जंगली इलाकों में संदिग्ध देखे जाने की सूचनाएं मिल रही थीं। इसके बाद सेना की 39 राष्ट्रीय राइफल बटालियन और पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने खनेतर और मंगनाड टॉप के जंगली इलाके की घेराबंदी कर संयुक्त तलाशी अभियान चलाया था। गुरुवार शाम को ऑपरेशन के तीसरे दिन सुरक्षाबलों ने कनुइया और मंगनाड टॉप के मध्य जंगली इलाके से आंतकियों द्वारा छुपाए हथियार एक एके-47 राइफल, एक एके-47 की मैगजीन एक, एक पिस्टल और पिस्टल की मैगजीन बरामद की है।

पुलिस के अनुसार जहां से हथियार बरामद किए गए हैं वह इलाका काफी दूर है। जंगल घना और कंटिला होने के कारण अभी सुरक्षाबल जंगली इलाकों से बाहर नहीं आए हैं। इसलिए तलाशी अभियान फिलहाल खत्म नहीं हुआ है।

पाक सेना ने दरगाह को निशाना बना दागे मोर्टार : पाकिस्तानी सेना ने अपनी नापाक हरकतों को दोहराते हुए पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि को 1:35 बजे नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम तोड़ने हुए मोर्टार शेल दागने सहित गोलाबारी की। पाकिस्तानी सेना के निशाने पर पुंछ नगर के गुंतरियां इलाके में नियंत्रण रेखा के नजदीक पुरानी एवं ऐतिहासिक साई मीरा बक्श दरगाह थी। गोलाबारी से सीमा पर किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ।

16 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं मस्जिद, चर्चों के लिए ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने। इस रकम में से एक-एक करोड़ रुपये संबलपुर स्थित पल्टन मस्जिद और सेंट जोसेफ कैथेड्रल को मिलेंगे।

एनएचआरसी ने ग्रामीणों की हत्या के लिए प्रशासन को माना दोषी

आया फैसला ▸ सुकमा जिले में 12 साल पहले हुई थी वारदात

आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने व दोषियों पर कार्रवाई की अनुशंसा

नईदुनिया, बिलासपुर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के ग्राम कोंडासावली, कर्रेपारा और कामरागुडा गांवों में 2007 में सलवा जुडूम (नक्सलियों के खिलाफ आंदोलित लोगों का समूह) और स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी ने 95 घरों को जलाया। इस दौरान सात ग्रामीणों की जान चली गई। आयोग ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। घटना में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की संलिप्तता के साथ ही तत्कालीन राज्य सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। आयोग ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा तत्काल प्रभाव से देने के निर्देश भी दिए हैं।

आयोग के दांत आज भी नहीं, पर उग रहे : जस्टिस दत्तू

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एचएच दत्तू का कहना है कि आयोग के दांत शायद आज भी नहीं हैं, पर उगने लगे हैं। मैंने जब आयोग का पदभार संभाला था तभी ये बातें कही थीं। आज भी इस पर कायम हूं, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। हमें अभी सिर्फ अनुशंसा का अधिकार है, पर राज्य या संस्था उसे माने यह बाध्यता नहीं है। हालांकि, आयोग की सिफारिशों को माने जाने की दर 99 फीसद है। केंद्र सरकार से अधिकार को लेकर आग्रह किया गया है।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट की अधिवक्ता सुधा भारद्वाज ने घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस मामले की जांच की मांग की थी। दरअसल, 2007 में आगजनी और हत्या की घटना के बाद तीनों गांवों के ग्रामीण दहशत के कारण गांव छोड़कर चले गए थे। कुछ वर्ष बाद जब सलवा जुडूम की मुहिम खत्म हुई और सब-कुछ ठीक होने लगा तब ग्रामीण गांव की ओर लौटे। घटना के छह साल बाद ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और घटना की शिकायत के लिए सरपंच का संरक्षण मांगा। तब 2013 में सरपंच ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी थी। शिकायत की जांच के बजाय ग्रामीणों पर एक बार फिर कहर बरपाया गया। पूर्व की घटना में जान गंवाने वाले एक ग्रामीण की पत्नी की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों को पीटा गया। परेशान ग्रामीणों ने हाई कोर्ट की वकील सुधा भारद्वाज से मदद मांगी। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत की। शिकायत को आयोग ने गंभीरता से लिया और संबंधितों से पूछताछ भी की। आयोग की निगरानी में सुकमा पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत पर एफआइआर दर्ज पर जांच के बजाय उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए आयोग ने इस पूरे मामले की स्वयं जांच की और अपना फैसला भी सुना दिया है।

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसे में 14 की मौत

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद

▸ बुधवार रात हुआ हादसा, दो मृतकों के घर का नहीं चल पाया है पता

▸ 32 घायलों में कई की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर बुधवार रात हुए भीषण हादसे के बाद पांच घंटे अफरातफरी मची रही। प्रशासनिक अफसर रात में ही मौके पर पहुंच गए। हादसे में ट्रोला चालक और बस में सवार 14 सवारियों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हो गए। इनमें से कई की हालत गंभीर है। इन सभी को इटावा के सैफई स्थित पीजीआइ अस्पताल भिजवाया गया है।

घटना बुधवार रात साढ़े नौ बजे की है। नई दिल्ली से बिहार के मोतीहारी जा रही प्राइवेट बस उप्र के फीरोजाबाद स्थित नगला खंगर के पास लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर ओवरटेक लाइन पर टायर फटने से खड़े ट्रोला में पीछे से जा टकराई। टक्कर तेज आवाज सुनकर खेतों की रखवाली कर रहे किसान हादसा स्थल पर पहुंचे और कंट्रोल रूम को सूचना दी।

बस में फंसी सवारियों को कटर और क्रेन की सहायता से निकाला गया। राहत कार्य सुबह तीन बजे तक चलता रहा। डीएम चंद्र विजय सिंह और एसएसपी सचिंद्र पटेल मौके पर पहुंच गए।

एडीजी अजय आनंद और आइजी ए. सतीश गणेश ने भी घटनास्थल का रात में ही दौरा किया। डीएम घायलों का हाल जानने सैफई अस्पताल भी गए। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने हादसे में मरने वालों की संख्या 14 और घायलों की संख्या 32 बताई है। नगला खंगर, नसीरपुर, सिरसागंज थानों की पुलिस व यूपीडा की टीम बचाव काम में लगी रही। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में 17 एंबुलेंस लगी रहीं। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अन्य सवारियों को पुलिस प्रशासन ने दूसरे वाहनों से उनके गंतव्य स्थान पर रवाना किया। रात तीन बजे एक्सप्रेस वे पर आवागमन सुचारु हो सका।

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुई बस से बाहर आते घायल यात्री। हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। एएनआइ

ये हैं मृतक

1. मुकेश कुमार, निवासी पछियारी मलाही इब्राहिमपुर थाना बाढ़ जिला पटना, बिहार
2. विनोद कुमार पुत्र अज्ञात
3. कलमुद्दीन, निवासी फैन हारा थाना फेनहारा मोतीहारी, बिहार
4. भगवान चौधरी, निवासी भगवानपुर तेतरिया थाना मधुबन मोतिहारी, बिहार
5. हरिंद्र पासवान, निवासी कोटला पासवान कटवा, पूर्वी दिल्ली
6. भूरा (ट्रक ड्राइवर) निवासी निपनिया रायपुर, दरभंगा
7. चंदन महतो, निवासी मेमोरा थाना पताही जिला मोतिहारी, बिहार
8. नागेश्वर साह, निवासी ग्राम खोरठा थाना बेलशन जिला शिवहर, बिहार
9. गुलशन कुमार, निवासी सरैया खास पोस्ट गोविंदगंज थाना गोविंद गंज, जिला, चंपारण बिहार
10. अनिल साह, निवासी पूर्वी चंपारण थाना कुंडवा चैनपुर, मोतिहारी, बिहार
11. राकेश कुमार, निवासी छोड़ा दानों थाना छोड़ा दानों, मोतिहारी, बिहार
12. प्रभु साह, निवासी खरार थाना मीनापुर मुजफ्फरपुर, बिहार
13. रघुवंश यादव पुत्र अज्ञात
14. अफरूलाल, निवासी हरदिया टोला थाना कुंडवा, मोतिहारी, बिहार

न्यूज गैलरी

छापेमारी में 2,000 करोड़ की अघोषित संपत्ति बरामद

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने हैदराबाद, विजयवाड़ा, कडप्पा, विशाखापत्तनम, दिल्ली और पुणे में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर 2,000 करोड़ से अधिक की अघोषित संपत्ति का पता लगाया है। छह फरवरी को हुई छापेमारी में विभाग ने 85 लाख की नकदी, 71 लाख के गहने और 25 बैंक लॉकरों का भी पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान जारी कर कहा कि छापेमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तीन प्रमुख समूहों के ठिकानों पर की गई। (एएनआइ)

राहुल गांधी को 35 हजार रुपये की नौकरी का ऑफर

वाराणसी : केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र पांडेय ने कहा कि राहुल गांधी बेरोजगारी पर अनावश्यक शोर मचा रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि वह रोजगार मेले में आएं और देखें। 35 हजार रुपये प्रतिमाह की यहां नौकरी मिल रही है। योग्यता के अनुसार उनको भी मिल जाएगी। केंद्रीय मंत्री वाराणसी के पं. दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कौशल महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। (जासं)

जेल जाने के भय से गिड़गिड़ाया माल्या, धन चुकाने को तैयार

▸ प्रत्यर्पण पर लंदन हाई कोर्ट में बहस पूरी, जल्द आएगा फैसला

▸ भारत में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज कर रखा है मुकदमा

लंदन, प्रेट्र : भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर कहा है कि वह भारतीय बैंकों का पूरा बकाया मूल धन वापस करने के लिए तैयार है। प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में अपील पर तीन दिन की बहस पूरी होने के बाद माल्या ने यह बात कही। हाई कोर्ट की जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लेइंग की पीठ अब किसी भी दिन फैसला सुना सकती है।

लंदन हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए माल्या ने कहा, भारतीय बैंकों से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वह उनका पूरा मूल धन चुकाने के लिए तैयार हैं। कहा, भारत में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक ही धनराशि की वसूली के लिए अलग-अलग मुकदमा दर्ज किए हुए हैं। प्रक्रिया में उसके साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा। बीते चार साल से उसके साथ सरकारी एजेंसियां अनुचित व्यवहार कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि दोनों एजेंसियों ने माल्या पर बैंक के कर्ज की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग कानून के तहत मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। माल्या की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। माल्या पर भारतीय बैंकों का नौ हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। इस कर्ज को चुकाने से बचने के लिए माल्या लंदन में रह रहा है। जबकि भारतीय एजेंसियां उसे भारत में लाकर मुकदमा चलाना चाहती हैं और उस पर बैंकों का बकाया वसूल करना चाहती हैं। वहीं, माल्या बार-बार कुछ न कुछ बहाना करता रहता है।

विजय माल्या। फाइल

लखनऊ में वर्चस्व को लेकर वकीलों के दो गुट भिड़े, सुतली बम से हमला

जागरण संवाददाता, लखनऊ : वर्चस्व को लेकर गुरुवार को लखनऊ कचहरी में वकीलों के दो गुट आमने-सामने आ गए। पहले गालीगलौज फिर देखते ही देखते जमकर मारपीट हुई। तभी एक पक्ष ने दूसरे पर सुतली बम से हमला किया। हालांकि, इसमें किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। लखनऊ बार एसोसिएशन के संयुक्त महामंत्री संजीव लोधी ने महामंत्री जीतू यादव समेत छह लोगों पर नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले की एफआइआर दर्ज कराई है।

शहर में पुरनिया रेलवे क्रासिंग अलीगंज निवासी संजीव लोधी के मुताबिक दिन में करीब 11:50 बजे वह सिविल कोर्ट स्थित अपने चैंबर के बाहर खड़े थे। तभी सुधीर यादव, आजम, अजाज, दिलीप सिंह व अन्य आठ-दस लोग वहां पहुंचे। उन्होंने हत्या करने की नीयत से मारपीट शुरू कर दी। सुतली बम से भी हमला किया। बम फटने से कचहरी परिसर में अफरा-तफरी मच गई। हमले में संजीव व उनके साथ खड़े अन्य अधिवक्ताओं को चोट आई है। वारदात के बाद आरोपित अधिवक्ता मौके से फरार हो गए। हमले में जीतू घायल हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दुष्कर्म के बाद दो महिलाओं की हत्या में पूर्व विधायक हिरासत में

नईदुनिया, रायगढ़

▸ वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन अनूप से की गई पूछताछ

▸ छत्तीसगढ़ पुलिस ओडिशा से लेकर आई है पूर्व विधायक को

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संबलपुरी के पास करीब चार साल पहले हुए दुष्कर्म के बाद दोहरे हत्याकांड में ओडिशा के पूर्व विधायक व ओडिशा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन अनूप कुमार साय को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

चक्रधरनगर थाना पुलिस का दावा है कि ग्राम संबलपुरी में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी करीब-करीब सुलझा ली गई है। सात मई 2016 को हुई इस वारदात में संबलपुरी गांव के पास से सड़क पर दो महिलाओं के शव मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या किए जाने की पुष्टि की थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को गाड़ी से कुचलने का भी प्रयास किया था। हत्या के बाद कई महीनों तक मृत महिलाओं की शिनाख्त तक नहीं हो सकी थी, जिससे पुलिस का तनाव बढ़ गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने कोलकाता एवं नागपुर के रेड लाइट एरिया में भी जाकर पड़ताल की थी, जिसके बाद पुलिस को दूसरी अहम जानकारी मिली। पता चला था कि दोनों महिलाएं ब्रजराजनगर ओडिशा की रहने वाली थीं। विवेचना आगे बढ़ी तो महिलाओं से ब्रजराजनगर के पूर्व विधायक अनूप कुमार साय का कनेक्शन होने की बात सामने आई। हालांकि, सुबूतों के अभाव में पुलिस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसी दौरान बुधवार की देर रात एसपी संतोष कुमार के निर्देश पर रायगढ़ पुलिस ब्रजराजनगर पहुंच गई और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को हिरासत में लेकर आ गई। गुरुवार को दिन भर उनसे इस मामले में कड़ाई के साथ पूछताछ की गई।

अनूप कुमार साय पहले कांग्रेस में थे। ओडिशा के ब्रजराजनगर सीट से वे तीन बार कांग्रेस विधायक के रूप में चुने गए। इसके बाद उन्होंने बीजू जनता दल (बीजेडी) में प्रवेश कर लिया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खास माने जाने वाले अनूप साय को ओडिशा सरकार ने वर्तमान में स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के चेयरमैन की कुर्सी दे रखी है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा उनको हिरासत में लिए जाने से ओडिशा में भी राजनीति गर्मा गई है।

नहीं रहे पर्यावरणविद् आरके पचौरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) के पूर्व निदेशक पर्यावरणविद् डॉ. आरके पचौरी का गुरुवार रात निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे। लंबी बीमारी के चलते उन्हें एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उनकी ओपन-हार्ट सर्जरी की गई थी। मंगलवार से उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था।

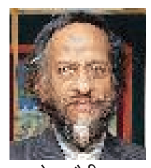

आरके पचौरी। फाइल

20 अगस्त 1940 को नैनीताल में जन्मे पचौरी 1981 में टेरी के निदेशक बने थे। 2001 में उन्होंने महानिदेशक का पद संभाला। वर्ष 2007 में पचौरी की अध्यक्षता वाले इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। अब तक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े तमाम संस्थानों और फोरम में पचौरी ने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 2015 में यौन शोषण के आरोपों के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

भोपाल स्टेशन का 28 साल पुराना जर्जर रैंप ढहा, नौ यात्री घायल

नईदुनिया, भोपाल

भोपाल रेलवे स्टेशन के 28 साल पुराने जर्जर रैंप का एक बड़ा हिस्सा गुरुवार को भरभराकर ढह गया। प्लेटफार्म दो व तीन से यात्री रैंप पर चढ़ रहे थे तभी हादसा हुआ। रैंप के साथ ही कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर गए। हादसे में नौ यात्री घायल हुए हैं। इनमें से आठ को शहर के चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक घायल का रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी घायल भोपाल के रहने वाले हैं।

भोपाल रेलवे स्टेशन के बीना आउटर की तरफ सालों पुराना फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) है। वर्ष 1991-92 में इसका चौड़ीकरण हुआ था। तभी प्लेटफार्म-दो व तीन पर उतरने के लिए रैंप बनाया गया था। इसकी चौड़ाई तीन मीटर और लंबाई करीब 35 मीटर है। गुरुवार सुबह दोनों प्लेटफार्मों पर 500 से ज्यादा यात्री थे। तभी 8.58 बजे प्लेटफार्म-2 पर तिरुपति-निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12707) आकर खड़ी हुई थी। इस ट्रेन से दर्जनों यात्री उतर रहे थे कि एफओबी से लगा रैंप का तीन मीटर चौड़ा और चार मीटर लंबा हिस्सा भरभराकर ढह गया। यदि रैंप के नीचे यात्री होते तो काफी जनहानि हो सकती थी। हादसे की प्राथमिक वजह रैंप पर डाली गई लोहे की रॉड में जंग लगना और उस पर रखी सीमेंट की सिल्लियों का कमजोर होना बताया जा रहा है। अलबत्ता, रेलवे ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश कर दिए हैं।

भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-दो-तीन को जोड़ने वाला यह रैंप ढहा। मौके का जायजा लेने पहुंची रेल डीजी अरुणा मोहन राव। नईदुनिया

हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिसकी भी गलती मिलेगी, उस पर कार्रवाई करेंगे। घायलों का इलाज करवा रहे हैं। आर्थिक मदद भी दी गई है।
-उदय बोरवणकर, डीआरएम, भोपाल रेल मंडल

हैदराबाद में एक शादी में शामिल होकर मैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से लौटा था। रैंप पर चढ़ते वक्त मेरे पिताजी दो कदम आगे थे। उनके पीछे मैं। पिताजी फुट ओवर ब्रिज पर पहुंच गए। मैंने भी अपना कदम पुल पर रखने के लिए आगे बढ़ाया था कि कुछ गिरने की आवाज आई। मैं कुछ समझ पाता इतने में ही नीचे गिर गया।
-मोहम्मद अमान, घायल

अयोध्या में पूर्व में तय मॉडल पर ही बने श्रीराम का मंदिर

जागरण संवाददाता, वाराणसी

▸ स्वामी वासुदेवानंद ने कहा, इसी मॉडल पर लोगों ने भरोसा कर दिया योगदान

▸ रामालय न्यास नाम की कोई चीज नहीं, वह पूरी तरह व्यक्तिगत ट्रस्ट

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि पूर्व में विश्व हिंदू परिषद द्वारा तैयार श्रीराम मंदिर का मॉडल देशभर में लोगों के बीच गया। लोगों ने विश्वास कर सवा-सवा रुपये की मदद की। इससे प्राप्त सवा आठ करोड़ रुपये के सहयोग से श्रीराम मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है। मॉडल भारतीय परंपरा व शिल्प का प्रतीक है। इस कारण उसी मॉडल पर अयोध्या में प्रभु श्रीराम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए।

प्रयागराज से गुरुवार दोपहर बनारस पहुंचे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती गंगा महासभा के महमूरगंज स्थित दफ्तर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि भगवान का मंदिर अतिशीघ्र बन जाए, आगे प्रभु श्रीराम जी जानें। श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए न्यास गठन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने ट्रस्ट बनाया है। उसके अनुरूप ही कार्य भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि रामालय ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, वह पूरी तरह व्यक्तिगत है।

पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व मंत्री उमा भारती द्वारा ट्रस्ट में पिछड़ी जाति को शामिल करने के आग्रह पर कहा कि देश में सवा सौ करोड़ लोग हैं। सभी मांग करते रहेंगे तो भला कैसे काम चलेगा। सभी ट्रस्ट में शामिल होने के बजाय अपना सहयोग दें। श्रीराम जन्मभूमि का मलबा दूसरे पक्ष द्वारा मांगे जाने पर कहा कि वहां प्राचीन मंदिर था। 1992 में ही मलबा खत्म हो गया, अब मुस्लिम पक्षकार उसे खोलते रहें। ज्योतिषपीठ शंकराचार्य पद को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा कि न्यायालय ने तो कोर्ट जाने वाले दूसरे लोगों को भी शंकराचार्य नहीं माना है। पूरा फैसला नेट पर उपलब्ध है।

जितनी होनी चाहिए, उतनी स्वच्छ नहीं हुई गंगा : स्वामी वासुदेवानंद ने कहा कि गंगा जितनी स्वच्छ होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। हालांकि प्रयास चल रहा है। सरकार पूरा प्रयास कर रही है लेकिन, पहले से जो गतिविधियां बनी हैं, उनमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक पूरा प्रयास सार्थक नहीं होगा। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ सहेजनी होगी धरोहर

रघुवरशरण, अयोध्या

67.77 एकड़ के जिस अधिगृहीत परिसर में रामलला के मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है, उस परिसर में पौराणिक महत्व का कुबेर टीला भी शामिल है। 27 वर्ष पहले हुए अधिग्रहण तक यह स्थल रामनगरी के चुनिंदा दर्शनीय स्थलों में शुमार रहा है। अयोध्या का इतिहास विवेचित करने वाले ग्रंथ रुद्रयामल के अनुसार, युगों पूर्व यहां धन के देवता कुबेर का आगमन हुआ था। उन्होंने रामजन्मभूमि के निकट ऊंचे टीले पर शिवलिंग की स्थापना की थी। कालांतर में यहां मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी व कुबेर सहित कुल नौ देवी-देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई और श्रद्धालुओं के बीच यह स्थल 'नौरत्न' के नाम से पूजित-प्रतिष्ठित हुआ।

1902 में एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा ने 84 कोस की परिधि में रामनगरी के जिन 148 पुरास्थलों को चिह्नित किया था, उसमें से एक कुबेर टीला भी था। कालांतर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआइ) की भी निगाह कुबेर टीला पर पड़ी। एएसआइ ने अयोध्या जिला में कुबेर टीला सहित पुरातात्विक महत्व के आठ स्थलों को संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया। ऐसे में मंदिर निर्माण के दौरान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कुबेर टीला की पौराणिकता सहेजना होगा। रामनगरी की पौराणिकता के मर्मज्ञ आचार्य रामदेवदास शास्त्री के अनुसार कुबेर टीला जैसी धरोहर को संरक्षित कर न केवल अतीत की स्मृति अक्षुण्ण रखी जा सकती है, बल्कि ऐसी विरासत जीवंत होने से राममंदिर की चिर परंपरा भी परिभाषित होती रहेगी।

मप्र सरकार की योजना

प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल, ओंकारेश्वर और रामराजा सरकार ओरछा मंदिर के अलावा अन्य स्थलों के प्रचार की रणनीति बनाई गई

'आईफा' अवार्ड के जरिये धार्मिक स्थलों की होगी ब्रांडिंग

राजीव सोनी, भोपाल

मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित होने वाले आईफा अवार्ड के जरिये राज्य सरकार ने प्रदेश के धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों की विश्व स्तर पर ब्रांडिंग का एजेंडा तैयार किया है। इसके तहत प्रमुख ज्योतिर्लिंग महाकाल, ओंकारेश्वर और रामराजा सरकार ओरछा मंदिर के अलावा अन्य प्रमुख स्थलों के प्रचार की रणनीति बनाई गई है। इन स्थलों पर नामी सेलिब्रिटीज की शूटिंग कराकर उनसे 'अजब-गजब मध्य प्रदेश' की ब्रांडिग कराने की योजना बनाई गई है।

आईफा अवार्ड की तैयारियों में जुटे राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम में आने वाले फिल्मी कलाकारों के कार्यक्रम का ब्योरा मांगा जा रहा है। उनके कार्यक्रम में प्रदेश के कुछ अति महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा जा रहा है।

इंदौर में कार्यक्रम के दौरान ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर मंदिर के अलावा उज्जैन के अन्य प्रमुख स्थलों पर इन सेलिब्रिटीज को ले जाकर उनकी शूटिंग भी कराई जाएगी। साथ ही उनसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रोफेशनल अंदाज में मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग भी करवाई जाएगी।

पर्यटकों को लुभाने का बड़ा मौका- प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल ने आईफा अवार्ड जैसे विश्वस्तरीय आयोजन को फिजूलखर्ची बताया है, वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार इसे देश और दुनिया में मप्र को नई पहचान दिलाने वाला आयोजन बता रही है। प्रदेश का पर्यटन विभाग इस आयोजन को दुनियाभर के पर्यटकों को लुभाने का बड़ा मौका मान कर अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भी दिए हैं। फिल्मी सितारों का सबसे बड़ा आईफा अवार्ड एक दिन 21 मार्च को भोपाल और दो दिन 27 व 29 मार्च को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में प्रस्तावित है।

आईफा अवार्ड दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर मप्र के डेस्टिनेशन को स्थापित कराने का बड़ा मौका है। इस आयोजन में आने वाली फिल्मी हस्तियों को कुछ चिह्नित पर्यटन स्थलों पर ले जाने का प्रयास होगा। उनकी शूटिंग भी कराई जाएगी, जिसका उपयोग मप्र की ब्रांडिंग के रूप में होगा।
-फैज अहमद किदवई, प्रमुख सचिव, राज्य के पर्यटन विभाग

आईफा अवॉर्ड फिजूलखर्ची, रोक लगाएं : गोपाल भार्गव

मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने आईफा अवार्ड के आयोजन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदेश की ब्रांडिंग ही करनी है तो अपने बेहतर कामों के जरिये करे, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो वो देश-दुनिया को बता सकें। यही वजह है कि हीरो-हीरोइनों के जरिये प्रदेश की ब्रांडिंग करवा रहे हैं। वित्त विभाग ने भी फिजूलखर्ची पर आपत्ति की है।

एसटी को 100 फीसद आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, एएनआइ : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कानून के इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया कि अनुसूचित इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 100 फीसद आरक्षण दिया जा सकता है अथवा नहीं। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली। दरअसल, चेबरोलू लीला प्रसाद नामक याचिकाकर्ता ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने एसटी को 100 फीसद आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ के हवाले कर दिया था। सुनवाई के दौरान आंध्र प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन का कहना था कि अपील को खारिज कर दिया जाए अथवा जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उसके फैसले को पलटा नहीं जाए।

बेहमई कांड के बीत गए 40 साल, नहीं मिल सका न्याय

जागरण संवाददाता, कानपुर

▸ 14 फरवरी 1981 को नरसंहार से दहल गया था पूरा देश

लो फिर आ गई 14 फरवरी और ताजे हो गए 1981 में डकैत फूलन देवी और उसके साथियों से मिले जख्म। 40 साल पहले हुए जिस बेहमई नरसंहार कांड से पूरा देश दहल गया था, उसमें अपनों को खोने वाले ग्रामीणों को आज भी न्याय का इंतजार ही है। फूलन देवी व साथी डकैतों ने एक जगह एकत्र कर 26 लोगों पर गोलियां बरसाकर 20 को मौत के घाट उतार दिया था, यह मंजर इस नरसंहार के चश्मदीद वादी राजाराम, नरसंहार में जीवित बचे जंटर और वकील सिंह की यादों में ताजा है। उस वीभत्स कांड में अपनों को खोने वालों के लिए 14 फरवरी हर साल जख्म देती रही है।

35 पर था मुकदमा, बचे चार डकैत : मुकदमे के वादी राजाराम सिंह ने मुकदमे में जालौन निवासी फूलन देवी, रामऔतार, मुस्तकीम, बिरही व लल्लू बघेल को नामजद कर कुल 30-35 डकैतों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें से अब कुल चार आरोपित ही बचे हैं जिनमें 75 वर्षीय पोसा 1981 से जेल में बंद है, जबकि 65 वर्षीय भीखा, 54 वर्षीय विश्वनाथ और 70 वर्षीय श्यामबाबू जमानत पर हैं। मामले में कुल 43 गवाह थे। इसमें से 28 की मौत हो चुकी है। कुल 15 की गवाही हुई। पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कोर्ट से फैसले के लिए बीती छह जनवरी की तारीख तय की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मूल केस डायरी तलब की थी लेकिन, उसके उपलब्ध न होने के कारण लगातार तारीखें ही लग रही हैं। एसपी देहात अनुराग वत्स के आग्रह पर कोर्ट ने अब 26 फरवरी तक का मौका दिया है।

Understand or Download Material for UPSC IAS Exam: iasrank.com

दैनिक जागरण

प्रतिभा एक प्रतिशत प्रेरणा और निन्यानवे प्रतिशत पसीना है

पाकिस्तान का ढोंग

पाकिस्तान की एक अदालत की ओर से आतंकी सरगना हाफिज सईद को सुनाई गई सजा पर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि कहीं यह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं? इस संदेह का एक बड़ा कारण यह है कि चंद दिनों बाद ही अंतरराष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ इस पर विचार करने जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने यहां के आतंकी ढांचे पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए या नहीं? चूंकि पाकिस्तान पर यह खतरा मंडरा रहा है कि एफएटीएफ की ओर से उसे काली सूची में डाला जा सकता है इसलिए हैरानी नहीं कि विश्व समुदाय के साथ इस संगठन को झांसा देने के इरादे से ही हाफिज सईद को आनन-फानन सजा सुना दी गई हो। पाकिस्तान के इरादों को लेकर संदेह उभरने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि हाफिज सईद के खिलाफ मुंबई के आतंकी हमले के मामले में कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। इसी तरह पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मामले में भी पाकिस्तान कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर इस नतीजे पर न पहुंचा जाए तो क्या किया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने का दिखावा मात्र कर रहा है? भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में पाकिस्तान की खोखली प्रतिबद्धता को रेखांकित कर सही किया, लेकिन उसे केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

भारत को इसे लेकर सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ को चकमा देने में समर्थ न हो जाए। इसकी आशंका इसलिए है, क्योंकि इस संगठन के कुछ देश इसके लिए सक्रिय हैं कि पाकिस्तान काली सूची में न आने पाए। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि अमेरिका ने हाफिज सईद की सजा का स्वागत किया है। भले ही अमेरिका को यह दिख रहा हो कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकी ढांचे को खत्म करने को लेकर गंभीर है, लेकिन सच यही है कि वह इसका ढोंग करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान न केवल लश्कर, जैश सरीखे आतंकी संगठनों को पाल-पोस रहा है, बल्कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क सरीखे उन आतंकी गुटों को भी पनाह दे रहा है जो अफगानिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। यदि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को निकालने की जल्दबाजी में अमेरिका इस तथ्य की अनदेखी करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वह सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। जो भी हो, विश्व समुदाय को इस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो न्यायपालिका हाफिज सईद के हाल के मामलों को लेकर सक्रियता दिखा सकती है वह 12 साल पुराने मुंबई हमले के मामले में कुंडली मारे क्यों बैठी है?

परंपरा पर प्रहार

कूचबिहार के पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दीक्षा समारोह है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ कार्यभार संभालने के बाद से ही राज्य सरकार के निशाने पर हैं। चूंकि धनखड़ भी राज्य सरकार की खामियां गिनाने का कोई मौका चूकते नहीं हैं इसलिए सरकार के मंत्रियों समेत तृणमूल संगठन के लोग उन पर निशाना साधते रहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शिकस्त के बाद राज्य की तृणमूल कांग्रेस का केंद्र पर हमला तेज हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस जीत को अपने लिए सुखद मान रही हैं। शिक्षण संस्थाओं, छात्रों और युवाओं के बीच राज्यपाल के हर कार्यक्रम को अस्वीकार भाव से देखा जा रहा है। एक तरह कहें तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल से जुड़े लोग राज्यपाल पर हमला करने में ही लगे हैं। जादवपुर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में राज्यपाल को आमंत्रित तो किया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें गो-बैक के नारों का सामना करना पड़ा। छात्रों के एक बड़े हुजूम ने राज्यपाल के खिलाफ जमकर नारे लगाए। राज्यपाल इससे आहत हुए और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। अब कूचबिहार विश्वविद्यालय में शुक्रवार को ही दीक्षा समारोह है और अभी तक उन्हें आमंत्रण न मिलना सवाल खड़े करता है। राज्य के विश्वविद्यालयों में आखिर क्या हो रहा है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति की मौजूदगी में दीक्षा समारोह की गरिमा बढ़ जाती है। देश भर के विश्वविद्यालयों की यह गौरवपूर्ण परंपरा रही है। इस परंपरा को विस्तार देने के साथ ही बाकी राज्यों में नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुलाधिपति की अनदेखी कर परंपरा पर प्रहार हो रहा है। राज्यपाल यह आरोप भी लगाते हैं कि विश्वविद्यालयों में सरकार के हस्तक्षेप के चलते इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी कुलपतियों ने पहली बार अपना संगठन बनाया है। यह बताया गया कि शिक्षा के विकास और उचित मांगों को पूरा करने के लिए संगठन बना है, लेकिन प्रकारांतर से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि यह संगठन कुलाधिपति पर दबाव बनाने के लिए ही बनाया गया है। अगर दबाव की राजनीति न होती तो राज्यपाल की बुलाई बैठक में कुलपतियों ने जाना तक गंवारा नहीं किया जबकि उनमें कई तृणमूल कांग्रेस के सीएए विरोधी धरने में शामिल हुए। निसंदेह यह मसला गंभीर है और राज्यपाल की अनदेखी करके संवैधानिक पद का मखौल उड़ाया जा रहा है। इसके राजनीतिक लाभ चाहे जो मिल जाएं लेकिन समाज में एक गलत परंपरा की नींव पड़ रही है। इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता है।

राष्ट्रीयता की अनदेखी के दुष्परिणाम

डॉ. मनमोहन वैद्य

कांग्रेस ने राष्ट्रीयता से किनारा कर लिया और जागृत जनता ने राष्ट्रीयता से दूर हुई कांग्रेस को किनारे कर दिया

अवधेश राजपूत

भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हजारों वर्षों की सामाजिक यात्रा के कारण उसकी पहचान बन गई हैं। इस पहचान को बनाए रखने का अर्थ है राष्ट्रीय होना। अपनी स्थापना के करीब 20 वर्ष बाद कांग्रेस ने ब्रिटिश विरोधी स्वतंत्रता आंदोलन का रूप लिया। तब कांग्रेस के सभी नेता भारत के परंपरागत समाज की उस विशिष्ट पहचान की साथ खड़े थे जो सदियों की सामूहिक यात्रा के कारण निर्मित हुई थी और जो अनेक आक्रमण और संघर्षों के बाद भी टिकी हुई थी। भारत के समाज का एक वैचारिक अधिष्ठान है जिसका आधार आध्यात्मिक है। इसके कारण भारत का एक व्यक्तित्व और स्वभाव बना। भारत की विशाल भौगोलिक इकाई में रहने वाला विविध जाति-पंथ-भाषा के नाम से जाना जाने वाला संपूर्ण समाज भारत की इन विशेषताओं को साझा करता है।

भारत के व्यक्तित्व के चार पहलू हैं। पहला है, एकम् सत् विप्राः बहुधा वदंति। भारत ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो व्याख्यान में कहा था कि हम सभी मार्गों को सत्य मानकर उनका सम्मान करते हैं। दूसरा है, विविधता के मूल में रही एकता की अनुभूति करना। रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना ही भारत का अंतर्निहित धर्म है। भारत विविधता को भेद नहीं मानता और पराए को दुश्मन नहीं समझता। इसीलिए नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे। उनकी विशेषता को पहचान कर उसे सुरक्षित रखते हुए उन्हें अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है। तीसरी विशेषता भारत की यह मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। चौथा लक्षण, यहां प्रत्येक व्यक्ति को अपना-अपना 'मुक्ति' का मार्ग चुनने की स्वतंत्रता होना है।

भारत का स्वभाव धर्म है। यह धर्म 'रिलीजन' अथवा उपासना नहीं है। मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, व्रत करना इत्यादि धर्म नहीं, उपासना हैं। उपासना करने से धर्म का आचरण करने के लिए शक्ति मिलती है। धर्म तो समाज को अपना समझ कर देना है। यह धर्म संकल्पना भारत की है। भारत की प्रत्येक भाषा के अभिजात्य और लोकसाहित्य में इसका वर्णन विपुलता से मिलता है। इसीलिए अंग्रेजी में धर्म का प्रयोग करना ही ठीक होगा। विद्या प्राप्त करने की इच्छा वालों को विद्या देना, प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, निराश्रित को आश्रय, रोगी को दवाई देना-धर्म कार्य माना गया है। इसीलिए धर्मशाला, धर्मार्थ अस्पताल शब्द प्रचलित हैं। धर्म का एक वर्णन कर्तव्य भी कर सकते हैं। बिना भेदभाव परस्पर सहयोग से सामाजिक समृद्धि को बढ़ाना धर्म है।

भगिनी निवेदिता ने कहा है, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एकत्र हुई पूंजी के आधार पर समाज समृद्ध बनता है और परिणामतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति संपन्न-समृद्ध बनता है, परंतु जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने पास रखते हैं उस समाज में कुछ लोग तो संपन्न होते हैं, लेकिन शेष समाज दरिद्र रहता है। जो सहायता करते समय भेदभाव करता है वह धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म समाज को जोड़ता है और इसीलिए धर्म की परिभाषा है, जो धारणा करता है वह धर्म है। भारत के संविधान निर्माण के समय संविधान समिति के सदस्यों को इस 'धर्म' तत्व की जानकारी थी। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का बोधवाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' है। लोकसभा में 'धर्मचक्र प्रवर्तनाय' लिखा है। राज्य सभा में 'सत्यं वद धर्मं चर' लिखा है। राष्ट्रध्वज पर जो चक्र अंकित है वह धर्म चक्र है।

1988 में गुजरात के कुछ हिस्से में भीषण अकाल था। मैं तब वड़ोदरा में प्रचारक था। अकालग्रस्त क्षेत्र में भेजने के लिए 'सुखड़ी' नामक एक पौष्टिक पदार्थ घर-घर बनवाकर संघ कार्यालय में एकत्र हो रहा था। एक दिन एक वृद्धा वहां आई। क्षीण आवाज में उसने एक कार्यकर्ता से कहा, सुखड़ी। उस कार्यकर्ता ने कहा माताजी, यह सुखड़ी अकालग्रस्त लोगों को भेजने के लिए है। तब उस वृद्धा ने अपनी साड़ी में समेटी एक पुड़िया निकाल कर देते हुए कहा, बेटा, मैं मांगने नहीं, देने आई हूं। ऐसे छोटे-छोटे कृत्यों द्वारा धर्म पुष्ट होता है और धर्मचक्र प्रवर्तन होता रहता है। भारत का यह वैचारिक अधिष्ठान जिस कारण बना उसका एक व्यक्तित्व और स्वभाव है। इसे दुनिया हिंदुत्व के नाम से जानती है। इसीलिए भारत और भारतीय समाज की पहचान दुनिया में हिंदू है। यह हिंदुत्व सबको जोड़ने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने वाला है। विविधता से संपन्न, अनेक भाषा बोलने वाला, विविध उपासना पंथों का अनुसरण करने वाला भारत का राष्ट्रीय समाज एक है। विविधता भेद न होकर हमारा वैशिष्ट्य है। आवागमन और संदेश व्यवहार के आधुनिक साधनों के कारण अब दुनिया बहुत करीब आ गई है। दुनिया में भाषा, वंश, उपासना, विचार का वैविध्य रहने वाला ही है। इस विविधता के मूल में एकता को देखने की दृष्टि भारत के पास है। इसीलिए भारत ने 'वसुधैव कुटुंबकम' को प्रस्थापित किया है।

स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस के अधिकांश नेता और असंख्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय वृत्ति के थे। कांग्रेस में साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने से इस 'राष्ट्रीय' को हाशिये पर धकेलने की वृत्ति बढ़ती गई। 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद यह प्रक्रिया और तेज हुई। इसी के साथ किसी भी प्रकार सत्ता में आना अथवा सत्ता में बने रहने की दिशा में कांग्रेस की यात्रा शुरू हुई। इसी कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनेक लोक नेता और साधु-संतों के प्रयास से राष्ट्रभाव जागरण का कार्य अधिक गति से हुआ और उसका प्रभाव समाज में दिखने लगा। एक तरफ राष्ट्रीय जागरण हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप समाज जाति, पंथ, प्रांत, भाषा आदि पहचान से ऊपर उठकर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार और आचरण करने लगा तो दूसरी तरफ कांग्रेस जाति, पंथ, प्रांत, भाषा आदि विविधताओं को भेद की तरह प्रस्तुत कर, भावनाएं भड़काकर सत्ता में टिके रहने या सत्ता प्राप्त करने के प्रयासों में उलझी रही। इसके फलस्वरूप कांग्रेस ने राष्ट्रीयता से किनारा कर लिया और जागृत जनता ने राष्ट्रीयता से दूर हुई कांग्रेस को किनारे कर दिया। वास्तव में कांग्रेस की कमजोर होती स्थिति का यही एक बड़ा कारण है।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं)

response@jagran.com

राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़े स्थानीय मुद्दे

हरेंद्र प्रताप

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को शाहीन बाग, जेएनयू, सीएए से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए

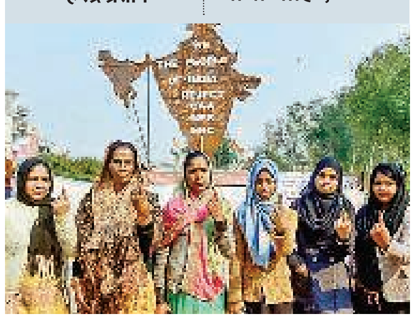

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सफलता का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। 2019 में लोकसभा की सभी सातों सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार विधानसभा की 70 में से मात्र आठ सीटें ही जीत पाई। दिल्ली में 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस पिछले बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खोल पाई। दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व और मुद्दों के मामले में अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस और भाजपा पर भारी पड़ रही है। इस पर दोनों राष्ट्रीय दलों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणामों से यह साबित हो गया है कि लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावी भूमिका अदा करते हैं, वहीं विधानसभाओं के चुनाव में मतदाता स्थानीय नेतृत्व और मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। अनुच्छेद 370 का खात्मा, तीन तलाक के खिलाफ कानून, नागरिकता संशोधन कानून, अयोध्या जैसे विषय राष्ट्रीय मुद्दे हैं और इन्हें राष्ट्रीय ही रहने देना चाहिए। दिल्ली के नतीजे बता रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी जैसे समस्याओं से जूझता व्यक्ति इन्हीं से जुड़े मसलों को प्राथमिकता देता है।

हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करते हुए कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए आदि से जोड़ रहे हैं। यह निष्कर्ष गलत है। ऐसा निष्कर्ष निकालने वाले मोदी सरकार को उसी प्रकार डरा रहे हैं जिस प्रकार 1977 में पराजित कांग्रेस को डराया गया था। मालूम हो कि 1977 के पहले भारत में चुनाव के समय फतवा जारी करने की परंपरा नहीं थी। आपातकाल के दर्द से कराहते भारत की आह कांग्रेस को लग गई और कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल हो गई। उस समय हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण करते हुए कुछ तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक और नेताओं ने अति उत्साह में आकर यह कह दिया कि 'कांग्रेस की यह अप्रत्याशित पराजय इसलिए हुई, क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया।' देश में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पुत्र संजय गांधी न केवल लोकसभा का चुनाव हार गए थे, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आपातकाल में दिल्ली के तुर्कमान गेट पर अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिसिया जुल्म और जबरन नसबंदी के कारण कांग्रेस के परंपरागत मतदाता माने जाने वाले मुस्लिम आक्रोशित अवश्य थे, पर जनता पार्टी की विजय का सारा श्रेय केवल मुसलमानों को देना चुनावी राजनीति का सांप्रदायिक विश्लेषण था, जो आगे एक प्रचलन बन गया। हालांकि आपसी कलह के कारण जनता पार्टी टूट गई और पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही सत्ता से बेदखल हो गई। उसके बाद 1980 में हुए लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गईं। भले ही कांग्रेस केंद्र और कई राज्यों में पुनः सत्ता में लौटी हो, लेकिन वह 1977 की अपनी पराजय से इतना भयभीत हो गई कि उसने सत्ता में आने के साथ ही मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण शुरू कर दिया। 1977 के लोकसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस कांग्रेस का सफाया हो गया था उन्हीं राज्यों में उसने मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का लालच दिया। बिहार के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्रा ने 1980 में और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 1982 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की घोषणा की। मुस्लिम तुष्टीकरण का वीभत्स रूप 1985 में सामने आया। कांग्रेस ने शाहबानो मामले में 'मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण विधेयक 1986' द्वारा उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय तक को निष्प्रभावी बना दिया। कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अमानवीय अत्याचार हुए और पूरा देश असहाय होकर उसे देखता रहा। वोट बैंक की इस मजबूरी ने भी देश में जिहादी आतंकवाद को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम, दोनों ने अंगेजी हुकूमत के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति के तहत मुसलमानों को इस तरह सशंकित किया कि वे अपने लिए एक अलग देश की मांग कर बैठे। हालांकि कांग्रेस ने मुसलमानों को मनाने के लिए अनेक प्रलोभन दिए, लेकिन वह विभाजन को राक नहीं पाई और देश खंडित हो गया। आज एक बार फिर से वही गलती दोहराई जा रही है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले लोग देश को एक और विभाजन की तरफ धकेल रहे हैं। वे विरोध के नाम पर अराजकतावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इसकी कुछ बानगी देखिए। कलकत्ता महानगरपालिका में आधार कार्ड के अद्यतन करने का जब विरोध हुआ तो नगरपालिका ने इस काम को रोक दिया। आंध्र में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के लोगों पर आक्रमण हुआ। कोटा, राजस्थान में आर्थिक सांख्यिकी गणना के लिए गईं नसरीन बानो को न केवल अपमानित किया गया, बल्कि उनका मोबाइल छीन कर उसका सारा डाटा डिलीट कर दिया गया। उत्तराखंड के नैनीताल, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बिहार के दरभंगा आदि जगहों पर भी सर्वे या सरकारी सूचना एकत्रित करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर हमले किए गए। जाहिर है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार सभी को है, पर देश में यह जो अराजकतावाद को बढ़ाया जा रहा है उसका परिणाम राष्ट्रहित में नहीं होगा।

(लेखक बिहार विधानपरिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन से संवाद

कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब मनुष्य अपने मन की बात करना चाहता है, किंतु किससे करे यह संकट खड़ा हो जाता है। मनुष्य अपनी भावनाएं मन में ही रखने को विवश हो जाता है और उसका दबाव सहन करता रहता है। जिनके साथ सदैव रह रहा उनसे भी मन के तल पर दूर रहता है। दावे जितने भी कर लिए जाएं, किंतु संसार में कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसे समरस कहा जा सके। एक मनुष्य का मन ही है जो उसकी समस्त भावनाओं और विचारों के मौलिक रूप का साक्षी होता है, क्योंकि मन को शब्दों की आवश्यकता भी नहीं होती। कोई विचार कहां से उपजा है, किस उद्देश्य को लेकर चलने वाला है यह स्वयं का मन ही जानता है।

मन मनुष्य के विचारों के मूल रूप का साक्षी होता है। वह उनका परीक्षण करने में भी समर्थ होता है। मनुष्य का स्वयं के मन से विमर्श उसे सदैव सच का मार्ग दिखाने वाला होता है। बहुत से धर्म मन को परमात्मा का सूक्ष्म रूप मानते हैं। भारत के कई संतों ने मन में परमात्मा को खोज लेने की बात कही है। विज्ञान ने भी मन की शक्ति को सभी शक्तियों से ऊपर माना है और उसे संकल्पशक्ति का नाम दिया है। जो सभी सांसारिक शक्तियों से श्रेष्ठ है वह परमात्मा ही है। मन की शक्ति को पहचानना ईश्वर को पहचानना है। मन से वार्ता ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना है।

मन से संवाद करना है तो उसे विकारों, मोह-माया के अंधेरे से बाहर लाना होगा। मन में प्रतिष्ठित ईश्वर के दर्शन के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। मनुष्य जब अपने मन के निकट होता है तो सारी सृष्टि से निकटता बन जाती है। जो बात वह अपने मन से कर सकता है वह किसी से भी कर सकता है। यदि उसे दुर्भावना भली नहीं लगती तो वह किसी के लिए भी दुर्भावना नहीं रखेगा। जो स्वयं को स्वीकार्य है वही अन्य के लिए हो तभी संतुलन बनता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

रीत रहा सह-अस्तित्व का भाव

डॉ. मोनिका शर्मा

जरूरी है कि दिखावे की सोच के बजाय प्रेम के वास्तविक भाव को पोषित किया जाय

भारतीय संस्कृति में प्रेम को जताने से ज्यादा निभाने का भाव माना गया है। सर्मपण के सार्थक भावों से जोड़कर देखा गया है। विश्वास और स्नेह की अनुभूति कहा गया है। प्रेम जो सृष्टि के कण-कण में विद्यमान है उसका अर्थ आज दिखावे की चमक में कुछ और ही चला है। प्रेम जो परिवार के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण की सीख देता है वह अब महंगे उपहारों और क्षणिक साथ का किस्सा बन कर रह गया है। गौरतलब है कि युवाओं की नब्ज पकड़ने वाला बाजार भी इस इस प्रेम को खूब समझता है, जो संवेदनाओं और अहसासों से दूर दिखावे की होड़ में लगा है। आए दिन प्रेम के नाम पर होने वाली घटनाएं हिंसक और विकृत होते प्रेम के भाव की बानगी बन रही हैं। ऐसे मामले बताते हैं कि यह एक दिन मनाने के जाल में फंसे लोग प्रेम के सही मायने ही भूल गए हैं।

बीते साल आए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि किसी व्यक्ति की हत्या होने के बड़े कारणों में प्रेम संबंध यानी कि लव अफेयर एक बड़ा कारण है। एनसीआरबी के मुताबिक हमारे यहां हत्याओं के ऐसे मामले 2001 से 2017 के बीच बढ़े हैं। गौरतलब है कि इस दौरान अन्य कारणों से होने वाले कत्ल के मामलों में कमी आई है। डेढ़ दशक से ज्यादा के इस समय में लोगों की जान ले लेने वाली घटनाओं में करीब 21 फीसद कमी देखी गई। इस दौरान आपसी रंजिश के चलते होने वाली हत्याएं 4.3 फीसद कम हुई हैं। साथ ही जमीन-जायदाद के विवाद में होने वाले कत्ल 12 फीसद घट गए हैं, लेकिन इसके उलट प्रेम संबंधों में होने वाली हत्याओं के मामले 28 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। चिंतनीय है कि प्रेम संबंधों से जुड़ी इन जानलेवा घटनाओं में ऑनर किलिंग और अवैध संबंधों के मामले भी शामिल हैं। दुखद है कि समाज में प्रेम के नाम पर हिंसा और बर्बरता के मामले बढ़ रहे हैं।

मौजूदा दौर में प्रेम का स्वरूप भारत ही नहीं दुनिया भर में बदला-बदला सा है। उपभोक्तावाद, बाजारीकरण और डिजिटल जुड़ाव के मौजूदा समय में प्यार बाजार की धुरी बन गया है। नतीजतन अब प्यार का दखल जीवन में सकारात्मक रवैया नहीं लाता। संवेदनशीलता को पोषित नहीं करता। जुड़ाव और समझ का आधार नहीं बनता। इसकी अहम वजह यह है कि दिखावे ने प्रेम के अर्थ ही गुम कर दिए हैं। साथ ही कुत्सित मानसिकता के लोगों ने संसार के सबसे सुंदर मानवीय भाव को हिंसक भी बना दिया है। हालिया बरसों में बाजार ने प्रेम का महिमामंडन कुछ यूं किया है कि इससे जुड़ी व्यावहारिक और संवेदनशील सोच खो गई है। तभी तो प्यार को रिश्ते की बुनियाद बनाकर समाज और परिवार को सार्थक संदेश देने वाले शालीन और अनुकरणीय उदाहरण अब कम ही देखने को मिलते हैं। जरूरी है कि दिखावे की सोच के बजाय प्रेम के वास्तविक भाव को पोषित किया जाय। इससे जुड़े मानवीय पहलुओं को सहेजा जाय।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बराबर हैं सभी धर्म

तलाशनी होगी कट्टरता की राह शीर्षक से लिखे अपने लेख में क्षमा शर्मा ने धर्म की आड़ में जो नफरत फैलाया जा रहा है, उसका हल निकालने के कुछेक उपायों का वर्णन किया है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके दिल और दिमाग एक कोरे कागज की तरह होते हैं, लेकिन घर-परिवार और समाज में वह जैसा माहौल देखता है, वैसे ही संस्कार ग्रहण कर लेता है। फिर जिंदगीभर उसी राह पर चलता रहता है। कट्टरता से मुक्ति की राह बच्चों को हर धर्म का सम्मान करने की शिक्षा के गलियारे से निकल सकती है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि कुछ लोग बच्चों को दूसरे धर्मों से नफरत करने का सबक पढ़ा रहे हैं। हमें जानना चाहिए कि कोई भी धर्म हिंसा की शिक्षा नहीं देता। जो धर्म की आड़ में हिंसा, नफरत फैलाते हैं, उन्हें धर्म का असली मतलब पता नहीं होता। न किसी धर्म विशेष से नफरत करो, न किसी जाति या गरीबी से, अगर नफरत करनी है तो करें उनके गलत कामों और विचारों से। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुरा तो वह है जो इंसानियत के खिलाफ चलता या गलत काम करता है। जिस तरह पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होतीं, उसी प्रकार सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। इसी सोच को अपना कर हम कट्टरता से लड़ सकते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सबसे अच्छे मित्र पेड़

देश में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। जलवायु का दूषित होना इसका मुख्य कारण है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। बढ़ता प्रदूषण संपूर्ण पृथ्वी के लिए खतरा है। जमीनी स्तर पर प्रकृति संसाधनों के रखरखाव और संरक्षण पर विश्लेषण की जरूरत है। स्वच्छ जलवायु हम सभी का अधिकार है, परंतु इसके लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। सरकार जल बचाओ, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है, परंतु यह कितने कारगर साबित हो रहे हैं? आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति दवाइयों के सहारे जीवन यापन करने पर मजबूर है। यदि पर्यावरण को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वह दिन दूर नहीं जब जीवन संभव ही नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार की मानसिक अथवा शारीरिक बीमारी से लड़ने में हमारे सबसे अच्छे और सच्चे मित्र पेड़-पौधे होते हैं। यह जीव जगत को शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ-साथ अनमोल औषधि भी प्रदान करते हैं। मानव जाति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण अनेकों जीव-जंतुओं के जीवन पर भी संकट आ गया है। पौधे ही एकमात्र ऐसे मित्र हैं जो किसी से कुछ नहीं लेते, सदैव हमको प्राणवायु, शीतल छाया, बरसात लाने में सहायक और औषधि, फल, फूल आदि अनेकों प्रकार के अनमोल उपहार देते रहते हैं। प्रकृति हमारी मां है जो हम सभी का बिना भेद-भाव के भरण पोषण करती है। हम मनुष्यों का भी यह कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, जल संरक्षण एवं जीवों पर दया करते हुए प्रदूषण करने वाले कारकों पर नियंत्रण करें। यह हम सभी की जिम्मेदारी बनती है।

आचार्य राम कुमार बघेल, पलवल

मेलबाक्स

कट्टरवादी सोच

दैनिक जागरण के 12 फरवरी के अंक में प्रकाशित क्षमा शर्मा का लेख, तलाशनी होगी कट्टरता की काट, में लेखिका की बात उचित है कि शिक्षित होने के बाद समाज की उससे यही अपेक्षा होगी कि उसमें तर्कशीलता, मानवतावादी व व्यावहारिक गुणों का समावेश होगा। यदि उसमें कट्टरतावादी सोच पनपेगी तो वह राष्ट्र व समाज किसी के हित में नहीं होगा। असल में कट्टरता का शिक्षा या अशिक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। यह एक मानसिकता है जो हमें समाज में व्याप्त एक माहौल से उत्पन्न होती है। धार्मिक कट्टरवाद का राजनीति में धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है। कुछ उच्च शिक्षित लोगों ने कट्टरवाद को एक रोजगार के रूप में अपना लिया है। वे उच्च शिक्षा व आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर समाज में धर्म के नाम पर जहर उगलते हैं, जबकि आम लोगों का इससे कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिल आम लोग इन साजिशों का शिकार हो जाते हैं।

sureshgoyal8@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

77 करोड़ रुपये मात्र घाटे में था उत्तर प्रदेश विद्युत निगम वित्तीय वर्ष 2000-01 में, जो आंकड़ा आज बढ़कर 83 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। बिहार में यह 67 हजार और मध्य प्रदेश में यह 52 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

आजकल

'मेक इन इंडिया' में हो व्यापक सुधार

डॉ. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

'मेक इन इंडिया' को शुरू हुए पांच वर्ष हो चुके हैं और इसके मूल्यांकन का समय आ गया है। निश्चित रूप से विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहा है जो मुख्य रूप से स्वत: प्रेरित है और एक अच्छी स्थिति में है। भारत में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था, उसे आज वास्तव में हासिल कर लिया गया है या फिर हम उसे हासिल करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन चीजों के बारे में भी व्यापक रूप से समझना चाहिए

'मेक इन इंडिया' अभियान की शुरुआत बहुत उत्साह और वाहवाही के साथ की गई थी। इसकी अवधारणा और लक्ष्यों की काफी तारीफ की गई थी। इसके अपेक्षित प्रभाव की बात करें तो इसने न केवल आम आदमी की कल्पना को नई उड़ान दी, बल्कि उद्योग जगत की उम्मीदों को भी पुनर्जीवित किया। उद्योग जगत ने इससे व्यापक स्तर पर प्रक्रियाओं में बदलाव की परिकल्पना की थी और उससे भी महत्वपूर्ण यह कि 'न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन' की सोच के कार्यान्वित होने की उम्मीद थी।

विनिर्माण क्षेत्र में महज दो फीसद हिस्सेदारी : विनिर्माण क्षेत्र से देश को नई उम्मीदें हैं। ऐसे समय में जब चीन ने खुद को इस संबंध में दुनिया की 'कार्यशाला' के रूप में स्थापित किया है, वैश्विक विनिर्माण में हमारा हिस्सा महज दो प्रतिशत है। एक अध्ययन के अनुसार विनिर्माण वैश्विक बाजार में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धिशील हिस्सेदारी 50 लाख नई नौकरियां पैदा करेगा। कई लोग यह मानते हैं कि भारत दुनिया के विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। इन सबके बीच हमारे नीति निर्माता और राजनेता एक जैसे हैं। एक पक्ष को समग्र समझ और प्रोत्साहन की कमी है, तो दूसरे पक्ष में वास्तविकता की कमी है। इस तरह की योजना की घोषणाओं में काफी कोलाहल सुनने को मिलता है जिन्हें सुनकर कोई भी यकीन कर लेगा कि दुनिया की 'कार्यशाला' में भारत के आगमन से चीन के इस संदर्भ में कायम एकाधिकार को खत्म किया जा सकता है। हालांकि यह हकीकत से कोसों दूर है। टेक्सटाइल, चमड़े और जूते के व्यापार का बांग्लादेश और वियतनाम में स्थानांतरित होना इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

दो कदम सीधा, एक कदम टेढ़ा : सरकार इस संबंध में कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही है। रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोल दिया गया है। विनियामक ढांचे को उदार बनाया गया है। विनिर्माण में मदद करने वाली योजनाओं को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी 'कारोबारी सुगमता' पर ध्यान देने से उद्देश्य के प्रति विश्वसनीयता बढ़ गई है।

सरकार की इस बात के लिए सराहना करने की जरूरत है कि प्रतिस्पर्धा तथा उन्नयन के लिए नई तकनीक से युक्त अनुसंधान विकास के साथ ही गुणवत्ता के बारे में आधुनिक विनिर्माण जरूरतों, विशेषज्ञता व आधुनिक तकनीक, स्पष्टता, परिपक्वता आदि का ध्यान रखा जा रहा है।

बदल रहा है विनिर्माण क्षेत्र : इसकी मुख्य विशेषता अकुशल श्रम और कम पूंजी की तुलना में व्यापक पूंजी और कुशल श्रम पर अधिक निर्भरता है। यहां तकनीकी विशेषज्ञों की कमी है। इस बीच, सरकार कमजोर योजनाओं, गलत कार्यान्वयन वाली कौशल विकास कार्यक्रमों में हजारों करोड़ का निवेश कर रही है। आज उद्योग जगत की कर्ज से दबी दशा 'मेक इन इंडिया' की धीमी प्रगति के कारण है, जो एनपीए क्रेडिट की दुर्दशा और अंततः डूबते उद्योग के दुष्चक्र को बढ़ाने का काम करते हैं। फंडिंग, विशेषज्ञता और नौकरशाही बाधाओं की पैठ जैसी अंतर्निहित चुनौतियों से निराश, हमारी अधिकांश बुनियादी परियोजनाएं या तो पूरी नहीं होती हैं और यदि होती हैं तो उनमें काफी समय लगता है और वे लोगों की जरूरतों के लिहाज से अपर्याप्त होती हैं।

भारत तत्पर है, लेकिन तैयार नहीं : अप्रचलित और अवरोधक रूपरेखाओं को खत्म करना होगा और एक पारदर्शी प्रणाली के साथ इसे बदलना होगा। नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल को बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने आदि सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। इसे एकल-खिड़की, ऑनलाइन पोर्टल, ईबिज के अतिरिक्त विभिन्न सेवाओं से एकीकृत किया गया है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है।

दिवालिया अधिनियम पारित होना तथा जीएसटी का कार्यान्वयन एक अनुकूल कदम है, लेकिन यह सिर्फ छोटे कदम हैं। हमारे नेताओं की सोच के साथ-साथ अंतर्दृष्टि, डिजाइन और वितरित करने की हमारी क्षमता, नौकरशाही का लचीलापन तथा योग्यता 'मेक इन इंडिया' के मुख्य पहलू हैं और हमारे कारोबार को जीवंत करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। कम मुद्रास्फीति, कम ब्याज दर और उच्च विकास से युक्त परिवेश प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक हैं। प्रचलित श्रम कानून और नौकरशाही की परेशानी ही इसे कम करते हैं। इसके अलावा, उद्योग को एक पुनरुद्धार योजना की आवश्यकता है जो बाधाओं को हटा सकती है और अनेक मौजूदा तथा घाटे वाली परियोजनाओं को पुनर्जीवित और पुनर्गठित कर सकती है। हमें भूमि अधिग्रहण, कर संरचना और श्रम सुधारों के लिए नीतियों को तैयार करने की आवश्यकता है। साथ ही निवेश को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकसित करने की नीतियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जरूरत है।

दिवालिया अधिनियम, जीएसटी अनुकूल पहल है, लेकिन वित्तीय क्षेत्रों में सुधारों को मजबूत और समग्र बनाने की जरूरत है। जब तक मांग को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, तब तक केवल कॉरपोरेट करों में कटौती करने से निवेश को नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमें एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की जरूरत है जो विनियामक मंजूरी को सक्षम बनाता हो, कठोर प्रक्रियाओं को आसान बनाता हो और नीतियों के कार्यान्वयन को गति देता हो और नवाचार तथा परिणामों को पुरस्कृत करता हो। हमारा लक्ष्य विदेशी निवेश के लिए एक साधन के रूप में इसे जोड़ने के साथ भारत को विनिर्माण, डिजाइन व नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना होना चाहिए। यह व्यापक लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने, अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान करने, रोजगार पैदा करने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और विकसित देशों के संगठन में भारत को शामिल करने के इर्द-गिर्द होना चाहिए।

सुस्ती के दौर से आगे बढ़ेगी अर्थव्यवस्था

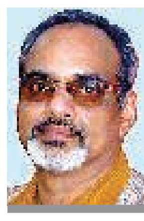

अनंत मित्तल
स्वतंत्र टिप्पणीकार

मोदी सरकार का सातवां बजट क्रांतिकारी भले ही न हो, मगर सुस्ती के भंवर में फंसी भारत की अर्थव्यवस्था को उबारने के पिछले दस माह से जारी उसके प्रयासों में इसके प्रावधानों से जमीन पर तेजी आने के आसार जरूर बन सकते हैं। बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने से लेकर प्रोफेशनलों को आयकर में राहत, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने जैसे समयानुकूल जरूरतों पर ध्यान दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस दूसरे बजट में ऐसे किसी भी प्रावधान को लागू करने की गुंजाइश नहीं बची थी जिससे अर्थव्यवस्था में कोई चमत्कारी बदलाव आ जाता, क्योंकि सुस्त हालात के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले आठ महीने से वित्तीय और प्रक्रियात्मक सुधारों की घोषणा लगातार करती आ रही हैं। वित्त मंत्री ने इस दौरान कम से कम चार बार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए रियायतों, राहत पैकेजों की बौछार की है। बजट में यह प्रावधान किया गया है कि निवेश को निर्बाध करने के लिए इंटरनेट पोर्टल आधारित निवेश निर्गम प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर भी सर्वांगीण सहायता सेवा देगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में घरेलू उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहन से रोजगार भी बढ़ेंगे। देश के प्रत्येक जिले में किसी उत्पाद विशेष का निर्यात केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षी घोषणा है, पर इसमें दो-तीन साल लग जाएंगे। बिजली के सामानों पर आयात शुल्क पांच से दस फीसद तक बढ़ा कर उन्हें भारत में ही 'मेक इन इंडिया' के तहत बनाने को बढ़ावा देने की कोशिश है।

दीवानी मामलों में आपराधिक कार्रवाई से राहत पर वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि करदाताओं का शोषण खत्म करने को सरकार प्रतिबद्ध है और कंपनीज एक्ट 2013 के कई प्रावधानों को आपराधिक श्रेणी से हटाने की तैयारी है। पिछले साल नवंबर में कंपनी कानून समिति ने 46 दंडात्मक प्रावधानों को केवल जुर्माने की श्रेणी में डालने या सिर्फ सुधार की अनुमति देकर मामला निपटाने के विकल्प की अनुशंसा की थी। सुस्ती के दौर में जीएसटी वसूली में पिछड़ी सरकार ने अपनी आमदनी चालू रखने के लिए सरकार द्वारा ई-कॉमर्स के तहत लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस के रूप में नए शुल्क का प्रस्ताव किया है। इसके लिए कानून में नई धारा 194-ओ जोड़ी जाएगी और ई-कॉमर्स विक्रेता भी कर के दायरे में आ जाएंगे। इसके साथ-साथ धारा 197 (कम टीडीएस), धारा 204 (किसी राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति को परिभाषित करना) और धारा 206 एए (गैर पैन आधार मामलों में पांच प्रतिशत की कटौती के लिए) में भी संशोधन का प्रस्ताव है। ये संशोधन आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे।

आयकर चुकाने के लिए और अधिक करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के बाद करदाताओं के लिए कर वाद में अपील करना भी आसान किया जाएगा। नई व्यवस्था में करदाताओं की अपील पर उनकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी। सरकार अब करदाताओं के अधिकारों का चार्टर भी लाएगी। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा संबंधित कानून में बदलाव किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे करदाता और प्रशासन के बीच भरोसा बढ़ेगा। इसी मंशा से सरकार पिछले चार साल में कर प्रशासन से संबंधित करीब 50 अफसरों को सेवा पूरी होने से पहले रिटायर कर चुकी है।

आयकर बचाने के नाम पर धर्मार्थ संस्थाओं को दान देने में फर्जीवाड़े पर लगाम के लिए अस्पताल और धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए हर पांच साल में पंजीकरण नवीनीकरण का प्रावधान लाया गया है। दानदाताओं की सूची भी सालाना नहीं जमा करने पर दंड लगेगा। संस्थाओं को विशिष्ट पंजीकरण संख्या मिलने से दान देने वाले करदाताओं के लिए आइटीआर में छूट लेना आसान हो जाएगा।

खरी-खरी

प्रेम का आपातकाल बनाम स्वर्णकाल

पीयूष पांडेय

'वो' प्रेम का आपातकाल था। यह प्रेम का स्वर्णकाल है। 'वो' यानी वह दौर, जब हम अपने कस्बे में इश्क की संभावनाएं उसी शिद्दत से खंगाल रहे थे, जैसे हेमंत बिरजे और चंकी पांडे जैसे कलाकार बॉलीवुड में अपनी सफलता खंगाल रहे थे। बाप-दादा के जमाने में प्रेम की संभावनाओं को देखा ही नहीं, तो उस पर नो कमेंट।

हमारे जमाने में लड़की से बात करना ओलंपिक मेडल जीतने सरीखा था। उस वक्त जिस तरह ओलंपिक से भारतीय खिलाड़ी प्रायः बिना पदक लिए ही वापस आते थे, उसी तरह 99.9 फीसद मामलों में लड़के भी बिना बात किए ही वापस आते थे। अपवाद के तौर पर पूरे कस्बे में एक-दो वीर बहादुर ही होते थे, जो बिना धरे और बिना ठुके यह कारनामा कर दिखाते थे। लड़की से दो-चार बार, दो-चार मिनट की बात को ही अफेयर का पर्यायवाची मान लिया जाता था।

आर्थिक उदारीकरण के बाद प्रेम प्रस्ताव के मामले में भी इतना उदारीकरण आ गया है कि कई बार लड़का-लड़की एक-दूसरे को प्रस्ताव देकर जवाब पूछ लेते हैं। सामने वाला इंट्रेस्टेड होता है तो हां कहता है। नहीं तो 'आइ एम ऑलरेडी एंगेज्ड' बोलकर कट लेता है। आजकल इन्कार पर ना तो प्रस्तावक बुरा मानता है और ना प्रस्ताव ग्रहणक।

वेलेंटाइन पीढ़ी पुराने प्रेमियों के इस दर्द को भी नहीं समझ सकती कि बिना प्रेमी-प्रेमिका की तस्वीर के प्रेम में डूबे रहना कितना कठिन होता है। बिना तस्वीर के बहुत रूहानी टाइप इश्क हो लेता था।

हमारे जमाने में प्रेम एक चुनौती थी। प्रेम को परवान चढ़ाते वक्त एक पार्टी का दूसरी पार्टी को संदेश भिजवाना ही मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाने जैसा मुश्किल था। किस्मत से मामला सेट हो जाए तो भी महबूब के साथ सुकून के दो पल बिताने की कोई जगह नहीं थी। चूंकि वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए लोग ज्यादा सोशल थे।

आज यकीनन प्रेम का स्वर्णकाल है। लेकिन इस स्वर्णकाल में भी लड़की के इन्कार के बाद एसिड फेंकने और दुष्कर्म करने की खबरें पढ़ने में आती हैं तो संत वेलेंटाइन की कसम मन करता है ऐसे आशिकों पर सरेआम कोई व्यंग्य लिख दूं।

ट्वीट-ट्वीट

नेहरू परिवार ने स्वयं को तीन भारत रत्न दिए (नेहरू, इंदिरा, राजीव) और सरदार पटेल को नजरअंदाज कर दिया। यह देख कोई आश्चर्य नहीं रह जाता कि नेहरू सरदार पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते थे।
ईशकरण सिंह भंडारी@ishkarnBHANDARI

अपराधी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पर क्या अपराधी नेता चुनावों में जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं? दिल्ली में मनीष सिसोदिया बड़ी मुश्किल से जीतते हैं, पर 12 मुकदमों वाले दागी अमानतुल्लाह खान जीत का रिकॉर्ड बना देते हैं।
अशोक श्रीवास्तव@ashokshrivasta6

सभी राज्यों और केंद्र को मिलकर सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और पढ़ाई की गुणवत्ता पर एक समयबद्ध अभियान चलाना चाहिए। तभी भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली सरकारें राष्ट्र को विकसित बनाने की राह में रोड़ा हैं।
मनीष सिसोदिया@msisodia

आप की जीत से उत्साहित दुखी आत्मा जरा सा तृप्त होकर अब बिहार की तरफ आशा वाली नजरों से देख रहे हैं, लेकिन दुखी आत्माओं की किस्मत में दुखी रहना अभी लंबा लिखा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के सामने कौन होगा, यही तय करने में विपक्ष का चुनाव खत्म हो जाएगा।
डॉ. अजय आलोक@alok_ajay

झारखंड डायरी

खत्म हुई आदिवासी चेहरे की तलाश

प्रदीप शुक्ला
स्थानीय संपादक, झारखंड

देर से ही सही, झारझंड विकास मोर्चा के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हो रही है और पूरे दम-खम से। भाजपा जहां बांह पसार कर उनका स्वागत कर रही है वहीं वह भी अपने मातृसंगठन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की कसमें खा रहे हैं। दो महीने पहले तक भाजपा को पानी पीकर कोसने वाले बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो वह दिल से स्वीकार करेंगे।

खैर, ये राजनीति है। इसमें जो दिख रहा अथवा बोला जा रहा है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो भी रहा हो। कई बार जो सामने दिखता है, होता ठीक उससे उलट है। भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी के बीच में काफी समय से खिचड़ी पक रही थी। लोकसभा चुनाव में आदिवासियों की नाराजगी के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। पार्टी उस समय राज्य की चौदह में से बारह सीटें जीतने में कामयाब रही थी इसलिए आदिवासियों की नाराजगी जगजाहिर नहीं हुई थी। इसके अलावा राज्य में रघुवर दास के रूप में गैर आदिवासी चेहरा देने का जो प्रयोग किया था पार्टी उससे पीछे कदम नहीं खींचना चाहती थी। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले यह गठजोड़ परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन विधानसभा चुनाव में रघुवर के साथ ही पार्टी की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और न ही झारखंड विकास मोर्चा अध्यक्ष बाबूलाल के पास। यदि भाजपा ने सत्ता गंवाई तो झाविमो की ताकत भी और क्षीण हो गई। उनके अलावा जीते दोनों विधायक पार्टी के दम पर कम अपनी शख्सियत के आधार पर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल के मिलन का यह सबसे सही समय था और दोनों ने अपने दंभ को मारना ही बेहतर समझा।

बाबूलाल मरांडी। फाइल फोटो

सत्रह फरवरी को रांची में एक बड़ी रैली के माध्यम से उनकी भाजपा में दमदार एंट्री कराई जाएगी। भाजपा में बाबूलाल की वापसी का मकसद पार्टी को एक दफा फिर सत्ता के करीब लाना है। स्थानीय मुद्दों को हवा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में बने राजनीतिक गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से हटाने में कामयाबी पाई। बाबूलाल मरांडी के जरिये भाजपा अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस पाने की फिराक में है। बाबूलाल मरांडी राज्य में आदिवासियों के सबसे बड़े धड़े संताल समुदाय से आते हैं और उसी समुदाय से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के मुकाबले के लिए भाजपा उन्हें तैयार करेगी।

झारखंड में भाजपा का गैर आदिवासी चेहरे को आगे कर राजनीति करने का प्रयोग विफल हो चुका है। अब उसके समक्ष एकमात्र विकल्प आदिवासी नेतृत्व को बढ़ाना है। बाबूलाल इसमें पूरी तरह फिट बैठते हैं। बड़े दलों की मौजूदगी के बीच उन्होंने अभी तक अपना अस्तित्व बरकरार रखा है और उनकी लोकप्रियता संदेह से परे है। भाजपा उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर स्थापित करेगी। रणनीति के मुताबिक वे भाजपा में एंट्री के साथ ही पूरे प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने करने की मुहिम आरंभ करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे खुद को भाजपा की अपेक्षाओं के अनुरूप ढाल पाते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और उसे मजबूत विपक्ष के तौर पर जनमुद्दों के साथ जोड़ना बाबूलाल की चुनौती होंगे। इसके अलावा अर्जुन मुंडा, रघुवर दास सरीखे भाजपा के कद्दावर नेताओं को भी उन्हें साधना होगा।

केजरीवाल का असर : आम आदमी पार्टी की दिल्ली में प्रचंड जीत की गूंज झारखंड में भी महसूस की जा सकती है। वैसे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही अरविंद केजरीवाल के प्रशंसकों में शामिल रहे हैं लेकिन उनकी सरकार के तमाम मंत्री भी जिस तरह दिल्ली के विकास मॉडल की चर्चा कर रहे हैं उससे यह तो जगजाहिर हो चुका है कि आने वाले समय में दिल्ली की कई योजनाएं झारखंड में भी धरातल पर उतरती दिख सकती हैं। शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जल्द ही राज्य से एक टीम दिल्ली जाने वाली है। बिजली मुफ्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत 300 मेगावॉट तक मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 मेगावॉट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणापत्र का भी हिस्सा है।

सरकार वित्तीय हालात को लेकर लगातार बयान दे रही है कि खजाना खाली है और ऐसे में मुफ्त की बात कहां तक उचित है इस पर विमर्श हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो सरकार अपनी मुफ्त वाली योजनाओं को लागू करने के लिए पूरा गुणाभाग लगा रही है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बड़ी परियोजनाओं पर नहीं जाएगी। इसका असर राज्य के विकास पर भी पड़ सकता है। बेशक रघुवर सरकार सत्ता गंवा चुकी है लेकिन विकास को लेकर जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनसे आने वाले समय में राज्य को फायदा ही होने वाला था। यदि बड़ी योजनाएं पूरी तरह से ठप हो जाती हैं तो नौकरियों का भी संकट खड़ा होगा ही।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय महत्व के मसलों को उठाना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है?

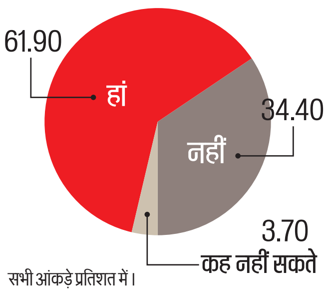

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि खुदरा महंगाई दर में बढ़ोतरी अस्थाई है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

इक सौतन का पति मरे तो दूजी खुशहाल,
बिल्कुल वैसा जानिए कांग्रेस का हाल।
कांग्रेस का हाल रह गई स्वयं लफद्दू,
फिर भी मन में फूट रहे हैं उसके लड्डू।
सुन बीजेपी नाम कुढ़ा करता उसका मन,
ज्यों दूजी को देख जला करती इक सौतन!
– ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

लाभकारी बने बिजली वितरण व्यवस्था

डॉ. अजय खेमरिया
स्वतंत्र टिप्पणीकार

आज सरकारी बिजली कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें बेलआउट पैकेज दिए जाने की जरूरत है। साथ ही इसके प्रबंधन से अफसरशाही का दखल भी खत्म किया जाए, तभी इस सेक्टर को ध्वस्त होने से बचाया जा सकता है

उत्तर प्रदेश विद्युत निगम वित्तीय वर्ष 2000-01 में 77 करोड़ रुपये घाटे में था। आज यह आंकड़ा 83 हजार करोड़ पहुंच गया है। बिहार में 67 हजार करोड़ है। मध्य प्रदेश में यह 52 हजार करोड़ है। देश के सभी डिस्कॉम के घाटे को जोड़ दें तो यह करीब 10 लाख करोड़ हो जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन के मौजूदा प्रस्ताव का देश भर में विरोध हो रहा है। सभी राज्यों के बिजली अभियंताओं ने एकजुट होकर सरकार से न केवल इस संशोधन को वापस लेने, बल्कि सभी विद्युत कंपनियों को भंग कर पुरानी निगम/ बोर्ड व्यवस्था बहाल करने की मांग भी दोहराई है।

इस विरोध का बुनियादी आधार 2003 कानून की व्यावहारिक विफलता ही है जिसके तहत तत्कालीन बिजली बोर्डों को विघटित करके कंपनियों में बदला गया, ताकि उत्पादन, पारेषण और वितरण को व्यावसायिक और उपभोक्ता अधिकारों के मानकों पर व्यवस्थित किया जाए। लेकिन आज यह प्रयोग विफल होता दिख रहा है। इसके मूल में अफसरशाही को देखा जाता है जिसने कंपनीकरण के नाम पर प्रशासनिक खर्चे तो बेतहाशा बढ़ा लिए, लेकिन जिस टेक्नोक्रेटिक और प्रोफेशनल एप्रोच की आवश्यकता थी, उसे अमल में नहीं लाया गया। पहले राज्यों में रेलवे की तर्ज पर एक निगम/ बोर्ड होता था। अब वितरण, पारेषण, उत्पादन, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, होल्डिंग कंपनियां बनाकर सभी की कमान आइएएस अफसरों को दे दी गई, जिन्होंने सरकारी महकमों की तरह ही इन कंपनियों को चलाया है। कंपनीकरण यह कहकर किया गया कि उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प, सस्ती और निर्बाध सुविधाएं मिलेंगी। अनुभव इसके उलट कहानी कहते हैं। एक तो देश के सभी सरकारी डिस्कॉम दिवालिया होने के कगार पर हैं तो दूसरी तरफ निजी बिजली कंपनियां

करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं।

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 और इंडियन इलेक्ट्रिक एक्ट 1948 बिजली क्षेत्र में किसी भी निजी भागीदारी को रोक रहा था। कॉरपोरेट दबाव के बाद देश में 2003 का विद्युत एक्ट पारित कर निजीकरण की नींव रखी गई। केंद्रीय मदद, विश्व बैंक, जापान बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे वितीय संस्थानों से कर्ज लेकर बुनियादी ढांचा सुदृढ़ीकरण पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए। सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, उदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण, दीनदयाल ग्राम ज्योति और उजाला जैसी भारी भरकम बजट वाली योजनाओं के जरिये करीब आठ लाख करोड़ रुपये इस मकसद से पिछले 15 वर्षों में खर्च किए जा चुके हैं। सिस्टम सुधार के नाम पर कंपनियों को हजारों करोड़ के टेंडर जारी किए गए। जो नेटवर्क सरकारी निगमों ने 50 वर्षों में खड़ा किया, उससे दोगुने 33 केवी, 11 केवी, एचटी लाइनें, पावर और वितरण ट्रांसफार्मर गांवों-कस्बों में खड़े कर दिए गए। शहरों में हजारों करोड़ के टेंडर पर रिनोवेशन, अपग्रेडेशन और केबलिंग के काम हुए। इन सभी टेंडर में ग्लोबल और केंद्रीकृत प्रक्रिया को अपनाया गया जिनके सर्वाधिकार आइएएस चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने अपने पास रखे।

विसंगति यह रही कि इतना बड़ा नेटवर्क एक साथ खड़ा किया जाता रहा और इसकी देखरेख के लिए कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई। नतीजन हजारों किलोमीटर तार चोरी हो गए। टेंडर भी बड़ी कंपनियों को उनकी सुविधा के अनुरूप बनाई गई शर्तों पर दिए गए। ठीक टेलीकॉम लाइसेंस घोटाले की तरह। मसलन ऐसी कंपनियों को ये ठेके दिए गए जिन्हें इस कार्य का अनुभव नहीं है। निजी कंसल्टिंग फर्मों की निगरानी में कंपनियां फायदे के काम कर भाग गईं। टेंडर पांच वर्षों में लाइन लॉस यानी विद्युत चोरी को 15 फीसद पर लाने की शर्त पर मिले थे, लेकिन एक भी कंपनी इस पर खरी नहीं उतरी। किसी डिस्कॉम का लाइन लॉस आज 30 फीसद से कम नहीं है। जाहिर है करोड़ों का ये काम आइएएस अफसरों एवं बड़ी कंपनियों के गठजोड़ की भेंट चढ़ गया और डिस्कॉम कर्ज में दबते गए।

दूसरा पक्ष प्रशासनिक खर्चे का भी है। निगमों में कार्मिक, वाणिज्य, उत्पादन सदस्य पूरे राज्य के काम देखते थे, लेकिन कंपनी में सर्किल ऑफिस में एचआर, आइटी मैनेजर, अकाउंट ऑफिसर के अलावा बड़ी संख्या में नॉन-टेक्नीकल लोगों की भर्तियां कर ली गईं। बिलिंग सॉफ्टवेयर के नाम पर घोटाले हुए। कॉल सेंटर, कलेक्शन सेंटर, फ्यूज कॉल रिस्पॉन्स जैसे कामों पर बेतहाशा धन खर्च हुआ। ये सब कर्ज के बोझ में ही हुआ, ताकि निजी कंपनियों के लिए वितरण व्यवस्था बढ़िया बनाकर दी जा सके। महंगी बिजली खरीदी के अनुबंध भी निजी कंपनियों से ऐसी शर्तों पर हुए हैं कि डिस्कॉम को बगैर बिजली लिए करोड़ों के भुगतान करने पड़ रहे हैं।

अब सरकार फिर विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करने जा रही है जो मूलतः निजी कंपनियों के हितों की ओर झुका है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में इसे उपभोक्ताओं के हितों के अनुकूल बताया है, लेकिन बुनियादी रूप से यह गांव, गरीब और किसानों के विरुद्ध है। इसके तहत निजी कंपनियां मुनाफे वाले बड़े उपभोक्ताओं को बिजली देकर पैसा बनाएंगी और सरकारी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, गरीबों और आम उपभोक्ताओं को बिजली देगी जिससे वह हमेशा घाटे में ही चलेंगी। क्रॉस सब्सिडी खत्म होने से उपभोक्ताओं को महंगी बिजली लेनी पड़ेगी। बेहतर होगा कि सरकार बिजली एक्ट में प्रतिगामी संशोधन वापस ले और बिजली बोर्डों की व्यवस्था को बहाल करे। साथ ही बिजली को जीएसटी के दायरे में लाया जाए और प्रबंधन से अफसरशाही का दखल भी खत्म किया जाए। अन्यथा इस सेक्टर को बचाना मुश्किल होगा।

31 लाख तीर्थयात्री पिछले साल चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस बार तीर्थयात्रियों का आंकड़ा और अधिक बढ़ने की संभावना है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 14 फरवरी 2020

हिमाचल प्रदेश

विदेश जाने के लिए अपनाएं सही प्रक्रिया

विदेश जाकर अधिक पैसा कमाने की चाहत होने में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन इसके लिए सही राह का चुनाव किया जाना जरूरी है। कई लोग अधिक कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग जालसाज एजेंटों के आसान शिकार बन जाते हैं। ऐसे लोगों को कई सब्जबाग दिखाए जाते हैं। कई लोग नौकरी के झांसे में आकर लूट का शिकार बन जाते हैं। कई मामले सामने आए हैं, जब विदेश के सुहाने सपने लेकर गए लोगों को वहां पर बंधक तक बनाया जाता रहा है। इसके बावजूद लोग सबक नहीं सीखते हैं। हर बार एक ही तरह की गलती कर वे जालसाजों की बातों में आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विदेश जाने की चाहत में लोग अपनी व्यापक धनराशि भी गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार गलत तरीके से विदेश जाने वाले बड़ी संख्या में लोग कानूनी प्रक्रिया के तहत लंबे समय तक जेलों में भी रखे जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वे वहां से छूट पाते हैं। लिहाजा हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

विदेश जाने के लिए पंजीकृत एजेंटों की सेवाएं लेना ही सही है। अन्यथा मेहनत का पैसा लुटाने के साथ परेशानी झेलने के लिए तैयार रहें

ताजा मामला मंडी जिला में सामने आया है। यहां के युवकों को मलेशिया में टूरिस्ट वीजा पर भेज दिया गया और वहां पर इन लोगों को बंधक बना लिया गया। 15 दिन तक बंधक रहने के बाद साढ़े तीन लाख रुपये और देने के बाद इन्हें छुड़ाया जा सका है। इन युवकों को मलेशिया में एक मॉल में 35 हजार रुपये की नौकरी देने का वादा कर चार लाख रुपये एजेंट ने लिए थे। इन युवकों ने अब पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी थी, पुलिस महानिदेशक ने सुंदरनगर पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अब जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी, लेकिन यह गंभीर चिंतन का विषय है कि जालसाजी व लूट के कई मामले सामने आने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। विदेश में लिए सही तरीके व हर तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ही जाना चाहिए। यह सही है कि लंबी प्रक्रियाओं से बचने के लिए लोग एजेंटों का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे पहले लोगों को यह जानकारी अवश्य लेनी चाहिए कि एजेंट सरकार से पंजीकृत है या नहीं। उस एजेंट के बारे में हर तरह की जानकारी लेने के बाद ही उसे फीस इत्यादि देनी चाहिए।

यह भी चिंतन का विषय है कि लोगों में ऐसी धारणा घर कर गई है कि किसी भी तरीके से धन एकत्र किया जाए। इस चक्कर में वे कई गलत कामों में हाथ डाल देते हैं और अपना जीवन संकट में फंसा देते हैं। इसे कतई सही नहीं कहा जा सकता है। देखा गया है कि कई लोग लालच में आकर अज्ञात लोगों को अपने बैंक इत्यादि की गोपनीय जानकारी दे देते हैं। इस बात को अहसास उन्हें तब होता है जब लुट चुके होते हैं। लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि ईमानदारी से किए गए काम का हमेशा अच्छा परिणाम निकलता है। लोग भविष्य से जुड़े मामलों की गंभीरता से जांचें ताकि उनके साथ किसी तरह की ठगी न हो सके।

झारखंड

अब योजनाओं पर खींचतान

झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बंद होने की संभावना के बाद अब पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की एक और बड़ी योजना एक रुपये में महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री भी बंद हो सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से की गई समीक्षा बैठक में इसके संकेत मिले हैं। बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि अब केवल वही योजनाएं चलेंगी जो गरीबों के घर में खुशहाली ला सकें। इस योजना को बंद किए जाने को लेकर दो तर्क दिए जा रहे हैं।

पहला पूर्व की सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने से राजस्व को बड़ी चपत लगी है। करीब 300-400 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के राजस्व की क्षति का आकलन किया गया है। दूसरा, इस योजना का लाभ गरीब तबके की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। कहा जा रहा है कि झारखंड में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण कोई भी गरीब परिवार जमीन की खरीद-बिक्री नहीं करता है। इस योजना का सबसे अधिक फायदा अमीर परिवारों ने उठाया है। बता दें कि जून 2017 को तत्कालीन रघुवर सरकार ने राज्य में महिलाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की जमीन खरीद पर रजिस्ट्री का शुल्क मात्र एक रुपये कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में इसे बड़ा कदम बताया था।

हालांकि नए सरकार के स्तर से इन योजनाओं को

अभी झारखंड की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पुरानी योजनाओं के साथ नई योजनाओं को भी चलाया जा सके। नई योजनाएं जनता की उम्मीदों के अनुरूप हों, इसका ध्यान रखना नई सरकार के लिए ज्यादा अहम है

प्रतीकात्मक फोटो

बंद किए जाने की अब तक अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, बावजूद इसके इसे लेकर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर निशाना भी साधना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और एक रुपये में महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री निवर्तमान सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार थी। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर इन योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को मिला है, लेकिन एक सच यह भी है कि हर राजनीतिक दल का अपना एजेंडा होता है। जनता से किए गए वादे को सत्ता में आते ही अमल में लाने की कोशिश हर सरकार शिद्दत से करती है। नई सरकार भी संभवतः उसी दिशा में काम कर रही है। राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि पुरानी योजनाओं के साथ-साथ नई योजनाओं को चलाया जा सके। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना हो या किसानों की कर्ज माफी, दोनों ही योजनाएं किसानों के हितों से जुड़ी हैं। कर्ज में डूबे अन्नदाता से यह कतई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह पूरी तन्मयता के साथ देशवासियों का पेट भरने में सक्षम होगा।

ऐसे में नई सरकार की संभावित कर्जमाफी की योजना किसानों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। कल्याणकारी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वंचित तबके के हित को सबसे ऊपर रखे। नई सरकार ने मजबूत जनादेश के साथ सत्ता संभाली है। लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। पुरानी योजनाएं बंद कर नई लाई जा रही हैं तो बेशक लाई जाएं, लेकिन राज्य की जनता की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए। वहीं नई सरकार को भी अपने तरीके से काम करने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

पंजाब

इस अदला-बदली के पीछे क्या है?

यह हर किसी को हैरत में डालने वाली घटना है कि पंजाब के मालवा क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल से संगरूर जिले के व्यक्ति का शव उत्तर प्रदेश के गोंडा पहुंच गया। हर किसी के जहन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि प्रतिष्ठित राजिंदरा अस्पताल के शव गृह में दो शवों की यह अदला-बदली आखिर कैसे हो गई? गोंडा के व्यक्ति का शव संगरूर के मृतक के परिजनों को दिया जाने लगा तो उन्होंने पहचाना कि यह शव तो बदल गया है। इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दोनों के शव जहर खाने से मरे व्यक्तियों के थे।

नियमानुसार ऐसे मामलों में मेडिको लीगल केस बनता है और शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाता है। बेशक इस मामले में डॉक्टरों की लापरवाही नहीं मानी जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि गोंडा के व्यक्ति का शव उसके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद सही तरीके से क्यों नहीं सौंपा गया? यह जाहिर है कि शव जल्द वहां से ले जाने के चक्कर में यह गफलत हुई है, लेकिन यह सवाल

प्रतीकात्मक फोटो

उठना स्वाभाविक है कि अस्पताल से शव को बिना शिनाख्त कराए कैसे ले जाने दिया गया? इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बड़े अस्पताल में इसी तरह मेडिको लीगल केसों से बचने के लिए शव को जल्दी वहां से ले जाने दिया जाता है? अगर ऐसा है तो व्यवस्था में यह एक बड़ा छेद है। ऐसी आशंकाएं तब और भी बलवती होती हैं जब यह मालूम होता है कि इस अस्पताल में कुछ ही दिन पहले ऐसा मामला पकड़ा जा चुका है जब पटियाला का एक व्यक्ति अपनी खुदकुशी करने वाली पत्नी का शव यह कह कर बिना पोस्टमार्टम करवाए वहां से लेकर चलता बना कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है।

अब भी यह सब सामने न आता यदि एक ही दिन जहर खाने के दो मामले न होते और दोनों शव वहां आसपास रखे जाने से गफलत न हुई होती। जहर खाने या अन्य कारणों से खुदकुशी के मामलों में कैसे शवों को आनन-फानन में ले जाने दिया जा रहा है? किसी न किसी स्तर पर तो यह ढील या नरमी बरती जा रही है। ऐसा किसी एक कर्मचारी के कारण संभव ही नहीं है। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच होनी चाहिए। पुलिस व स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों को देखना होगा कि किस तरह यह सब हो रहा है? तभी भविष्य में ऐसी विचित्र घटनाओं को रोका जा सकेगा।

उत्तराखंड

कम नहीं हैं चारधाम यात्रा की चुनौतियां

प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने को अब दो ही माह बचे हैं। केदारनाथ को छोड़ शेष तीनों धाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री और बदरीनाथ के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो चुकी है। इसके साथ ही अब सरकार और शासन के सामने यात्रा को सुचारू और सफलतापूर्वक संचालित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। कारण यह कि इस बार भारी बर्फबारी और बरसात के कारण तमाम व्यवस्थाओं को यात्रा से पहले दुरुस्त करना आसान नहीं होगा। देखा जाए तो हर साल खासी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन चारों धामों के दर्शन करते हैं। चारधाम के साथ ही हेमकुंड साहिब तक पिछले वर्ष लगभग 31 लाख यात्री पहुंचे।

इस बार यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की संभावना है। यात्रा मार्ग पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती चारधाम ऑलवेदर रोड के निर्माण कार्य के चलते कई स्थानों पर होने वाले भूस्खलन की है। दरअसल चारधाम ऑल वेदर रोड के लिए मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए पहाड़ों का कटान हो रहा है। जहां पहाड़ कच्चे हैं वहां भूस्खलन हो रहा है। इस कारण मार्ग बाधित हो रहा है। यदि समय से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो यात्रा के सुचारू संचालन को लेकर काफी दिक्कतें आ सकती हैं।

दो माह बाद, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में सरकार को अभी से इसकी तैयारियों पर फोकस करना होगा

चौड़ीकरण के कारण सड़कें जगह-जगह पर टूटी हुई हैं। कई जगह नए डेंजर जोन बने हैं जो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। यात्रा मार्ग पर सेफ्टी वॉल और पेराफिट की खास जरूरत महसूस की जा रही है, जिन पर अगले दो माह में तेजी से काम नहीं होता तो फिर इससे दुर्घटना होने की आशंका बढ़ सकती है। चारधाम यात्रा के दौरान शौचालयों और अन्य यात्री सुविधाओं का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसकी रफ्तार नहीं बढ़ाई गई तो यात्रियों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने की रहेगी। यह देखने में आया है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना के अलावा सबसे अधिक मौत हृदयाघात से होती हैं। इसके लिए जगह-जगह स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात करने की जरूरत है। बीते वर्ष हालात ये रहे कि यात्रा शुरू होने के बावजूद कई स्थानों पर चिकित्सक तैनात नहीं हो पाए थे। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार को इन पुराने अनुभवों से सबक लेने की जरूरत है। इसके साथ ही अभी से यात्रा की तैयारियों को गति देनी होगी ताकि बाहर से आने वाले यात्री उत्तराखंड से सुखद यात्रा का अनुभव लेकर वापस लौटें। उत्तराखंड की आर्थिकी का एक बड़ा जरिया यह पर्यटन ही है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में लोग वहां के मनमोहक सौंदर्य देखने और धार्मिक स्थलों के दर्शन करने जाते हैं। उत्तराखंड में पर्यटकों की यह आवाजाही बनी रहे इसके लिए उन्हें जरूरी सुविधाएं और सुरक्षा भी मिलती रहनी चाहिए।

अनूठा है आइआइटी का मानवरहित सोलर यान मराल-2

जागरण विशेष ▸ आइआइटी कानपुर के शोध छात्र ने बनाया दुनिया का पहला एक्सीरॉन तकनीक वाला यूएवी

विक्सन सिक्रोड़िया, कानपुर

- 20 किग्रा पेलोड भारवर्ग में अब तक का सबसे अधिक उड़ान बैकअप
- सर्वाधिक 18 घंटे उड़ाकर किया गया परीक्षण, नौसेना में हो सकता है इस्तेमाल
- प्राकृतिक आपदा के समय सामग्री पहुंचाने और सर्विलांस में हो सकेगा उपयोग

तकनीक की दुनिया में नित नए प्रतिमान गढ़ रहे कानपुर आइआइटी के शोध छात्र ने दुनिया में नाम रोशन किया है। छात्र ने सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला ऐसा मानव रहित यान (यूएवी) सोलर मराल-2 बनाया है, जो एक्सीरॉन तकनीक से लैस है। इस तकनीक से यूएवी के पैनल हमेशा सूर्य की ओर होंगे और उसकी सबसे अधिक ऊर्जा ग्रहण करेंगे। इस तकनीक ने मराल-2 को अपने पेलोड वर्ग में दुनिया का सर्वाधिक समय तक उड़ने वाला सोलर यूएवी बना दिया है।

इस सोलर यूएवी को एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. एके घोष और डॉ. जीएम कामत के दिशानिर्देशन में पीएचडी छात्र विजयशंकर द्विवेदी ने दो साल के शोध के बाद तैयार किया है। आइआइटी की एयर स्ट्रिप पर 18 घंटे की सफल उड़ान के बाद तकनीक को पेटेंट करा लिया गया है।

12 किलो के इस यूएवी का पेलोड (सामग्री के साथ उड़ते समय वजन) 20 किग्रा है। इसमें सर्विलांस निगरानी के पूरे सिस्टम मौजूद हैं। यह सोलर यूएवी सौ किमी तक क्षैतिज (लंबाई में) और पांच

आइआइटी कानपुर में विकसित मानव रहित यान (यूएवी) सोलर मराल-2। जागरण

किमी तक ऊर्ध्व (ऊंचाई) में उड़ सकता है। इसे 250 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए रिमोट की जरूरत होती है, फिर ऑटो पायलट तकनीक यूएवी को नियंत्रित कर लेती है। अधिकतम ऊंचाई पर भी इसके कैमरे जमीन पर हो रही हरकत पकड़ लेते हैं।

इस सोलर यूएवी का इस्तेमाल सर्विलांस के अलावा आकस्मिक परिस्थितियों व प्राकृतिक आपदा के समय भोजन व दवाओं के पैकेट पहुंचाने में अधिक कारगर होगा। चर्चा है कि नेवी ने भी इसे लेकर

कानुपर आइआइटी के शोध छात्र विजय शंकर द्विवेदी। जागरण

उत्सुकता जताई है। अधिक ऊंचाई और लंबाई तक उड़ने की क्षमता के कारण सेना के लिए भी यह काफी मददगार है।

यूएवी में एक्सीरॉन कंट्रोल तकनीक का उपयोग किया गया है। यह तकनीक हमेशा सोलर पैनल को सूर्य की दिशा में रखेगी। इसीलिए अपेक्षाकृत छोटे (2.2 वर्ग मीटर) सोलर पैनल वाला यह यूएवी सूर्य की सर्वाधिक ऊर्जा ग्रहण करेगा। इससे यह सर्वाधिक एंडुरेंस (सौर ऊर्जा क्षेत्र का चयन करना, ग्रहण करना, इस्तेमाल करना और भंडारण कर बैकअप बनाना) वाला सोलर यूएवी बन गया है। इसके सोलर सेल 240 वाट सौर उर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि उड़ने के लिए महज 170 वाट की जरूरत होती है। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता होने के कारण यह रात में भी उड़ान भर सकता है। पहले 14 घंटे तक उड़ान भर सकने वाले यूएवी की उड़ान क्षमता अब 18 घंटे हो गई है। पंखों की विशेष डिजाइन के कारण यह किसी भी दिशा में नियंत्रित उड़ान भर सकता है।

नौसेना को भी भाया, मुंबई की कंपनी करेगी उत्पादन... : शोधार्थी विजय ने बताया कि पेटेंट मिल चुका है और अब मुंबई की विटॉए एविएशन कंपनी इसका व्यावसायिक उत्पादन करने जा रही है। सोलर यूएवी को भारतीय नौसेना ने भी पसंद किया है और समुद्र की निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

मरीजों की जिंदगी में खुशियों का उदय हैं डॉ. रवि

- कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि कानन को हालही मिला है पद्मश्री सम्मान
- असम में कछार कैंसर अस्पताल चला रहे हैं डॉ. कानन, 100 बेड वाले अस्पताल में गरीबों के इलाज की बेहतर व्यवस्था

कैंसर रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉ. रवि कानन असम के सिलचर स्थित कछार कैंसर अस्पताल में अपनी टीम के साथ। सौजन्य : डॉ. कानन

मनु त्यागी, नई दिल्ली

असम में कछार कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र (सिलचर कैंसर संस्थान) चला रहे 55 वर्षीय डॉ. रवि कानन को हालही पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। सौ बेड वाले इस अस्पताल में गरीबों के इलाज की बेहतर व्यवस्था है। अन्य राज्यों से भी लोग सिलचर स्थित इस अस्पताल में इलाज को पहुंचते हैं।

डॉ. कानन ने दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कहा, डॉक्टर का एक ही मकसद होता है मानव सेवा। किसी का भी इलाज रुकना नहीं चाहिए। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. कृष्णमूर्ति मुझसे हमेशा यही बात कहते थे कि डॉक्टर और अस्पताल का फर्ज है कि मरीज उनके पास कैसी भी स्थिति में आए, उसकी जेब नहीं उसके हालात देखने चाहिए, उसकी बीमारी का तुरंत इलाज देना चाहिए। उसकी आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तो कैसे भी उसके लिए सहयोग के रास्ते बनाए जाएं, लेकिन मरीज बगैर इलाज के न लौटे...। उनकी इसी सीख को आत्मसात कर बरसों से इस पेशे के माध्यम से मानव सेवा कर रहा हूं।

स्वस्थ समाज

सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रवि कानन को जब पद्मश्री प्रदान किया गया, तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी उन्हें गुमनाम सितारे की तरह बताया था। डॉ. रवि ने बताया कि वह चेन्नई के एक बड़े अस्पताल में काम करते हुए करियर से संतुष्ट थे, सब ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन असम से डॉ. चिन्मॉय चौधरी का फोन आया। उन्होंने उन्हें असम के सिलचर में बुलाया। रवि कहते हैं, ये वर्ष 2007 की बात है। मैं वहां गया। देखा कि लोगों के लिए इलाज की आसपास कोई व्यवस्था नहीं थी। इलाज के लिए 300 किमी दूर जाना पड़ता था। डॉ. चिन्मॉय के सहयोग से गांव में धीरे-धीरे लोगों ने जमापूंजी लगाकर एक छोटे से अस्पताल की शुरुआत की थी, अब उसमें इलाज का दायित्व मेरा था। ऐसी स्थिति थी कि वहां हर घर में कैंसर के मरीज होते थे। एक तो लोगों के पास पैसा नहीं, ऊपर से ऐसी बीमारी जिसमें गरीब परिवार की तीन पीढ़ियां तक उबर नहीं पातीं। अंततः मैंने और पत्नी सीता ने तय किया और हम असम में ही बस गए। अब इस अस्पताल में असम के विभिन्न हिस्सों के अलावा बिहार और आसपास के अन्य राज्यों से भी लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं।

डॉ. रवि ने कहा, मेरा मानना है कि कैंसर का इलाज बहुत दूर जाकर नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इलाज लंबा चलता है, बार-बार अस्पताल जाना होता है। यह भी जरूरी है कि इलाज एक ही अस्पताल में पूरा हो। मरीज बहुत उम्मीद से आते हैं। ऐसे में उन्हें यहां ठहराने की भी व्यवस्था है ताकि इलाज पाकर ही लौटें। दूर से आने वाले मरीज व उनके तीमारदारों के रहने की व्यवस्था सुलभ की गई है। महज 15 रुपये में कमरा और 10 रुपये में खाना। यदि किसी के पास वह भी नहीं है तो कोई बाध्यता नहीं है...। कम से कम में या निश्शुल्क इलाज, अस्पताल का रखरखाव, नई मशीनें, कर्मचारियों का वेतन आदि के लिए सरकार, असम एयरपोर्ट अथॉरिटी, टाटा जैसे संस्थानों और सीएसआर इत्यादि के रूप में आर्थिक सहयोग मिलने लगा है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

निजी विवि के लिए अंब्रेला एक्ट पर असमंजस में सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- उच्च शिक्षा में निजी पूंजी निवेश को देखते हुए सरकार बरत रही सावधानी

उत्तराखंड के डेढ़ दर्जन निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को अंब्रेला एक्ट को लेकर अभी इंतजार करना होगा। मनमानी फीस पर रोक समेत निजी विवि के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए प्रस्तावित इस अंब्रेला एक्ट पर सरकार वेट एंड वाच मोड में है। उच्च शिक्षा में निजी पूंजी निवेश बढ़ाने पर जोर दे रही सरकार इस मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने से बचना चाहती है।

प्रदेश सरकार अंब्रेला एक्ट का मसौदा तैयार कर चुकी है। मसौदे पर निजी विश्वविद्यालयों संग मशविरा किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि निजी विश्वविद्यालय अंब्रेला एक्ट लाने के पक्ष में नहीं हैं। सरकार के साथ बैठक में वे अपना रुख जाहिर कर चुके हैं। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि अंब्रेला एक्ट के जरिए उत्पीड़न करने की मंशा नहीं है। छात्रों और अभिभावकों से मिलने वाली शिकायतों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों के खुद अपने ही एक्ट के प्रविधानों का पालन नहीं करने की जानकारी के बाद सरकार यह कदम उठाने को बाध्य है।

प्रस्तावित एक्ट में निजी विश्वविद्यालयों में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अपर सचिव स्तर के अधिकारी को नामित करने का प्रविधान किया गया है। यह अधिकारी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर नजर भी रखेगा, ताकि वे फीस तय करने या अन्य मामलों में मनमानी न कर सकें। हालांकि नए एक्ट को जल्द अमलीजामा पहनाने से कदम पीछे खींचे गए हैं।

दरअसल, प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। नए विश्वविद्यालयों से जुड़े करीब आधा दर्जन प्रस्तावों पर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। बीते रोज कैबिनेट ने रुड़की में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को निजी विश्वविद्यालय बनाने के विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। इस संबंध में विधेयक आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार उक्त सत्र में ही सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट लाने का फैसला तकरीबन कर चुकी है। उच्च शिक्षा प्रमुख सचिव आनंद बर्द्धन का कहना है कि अंब्रेला एक्ट को लेकर सरकार अभी मंथन कर रही है।

अब ट्रेनों में 'चाय-चाय' के बजाए गुड मॉर्निंग बोलकर यात्रियों को जगाएंगे वेंडर

मुकेश कुमार, समस्तीपुर

- पहले चरण में मुजफ्फरपुर और पटना के प्रशिक्षण संस्थानों में 600 वेंडरों को प्रशिक्षित किया गया
- स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस में प्रशिक्षित वेंडरों को ट्रायल के तौर पर लगाया गया
- लंबी दूरी की प्रमुख ट्रेनों में वेंडर यात्रियों को करा रहे सुखद अनुभूति, आचरण संबंधी शिकायतों में गिरावट

सुबह होते ही ट्रेन में अब 'चाय-चाय' की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसकी जगह प्रशिक्षित वेंडर बेड टी के साथ 'गुड मॉर्निंग' बोलकर यात्रियों को जगाएंगे। यह भी बताएंगे कि कौन सा स्टेशन आने वाला है या ट्रेन कितनी विलंब से चल रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आइआरसीटीसी) ने वेंडरों को इसके लिए प्रशिक्षित किया है।

पहले चरण में मुजफ्फरपुर और पटना के प्रशिक्षण संस्थानों में 600 वेंडरों को प्रशिक्षण दिया गया है। वेंडरों को कौशल विकास के तहत यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार की ट्रेनिंग दी गई। इसकी शुरुआत एक महीना पहले पूर्व मध्य रेलवे से की गई। इस दौरान पाया गया कि यात्रियों से मधुर व्यवहार करने पर ट्रेन में यात्रा के दौरान होने वाली शिकायतों में भी कमी आई है। फिलहाल, इस रूट में स्वतंत्रता सेनानी, बिहार संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस में प्रशिक्षित वेंडरों को ट्रायल के तौर पर लगाया गया है।

एसी से लेकर स्लीपर तक में लागू हुई व्यवस्था : यह व्यवस्था ट्रेन के एसी बोगी के साथ स्लीपर क्लास में भी लागू की गई है। जहां ट्रेन के अंदर यात्री को देख वेंडर सुबह, दोपहर और शाम के अनुसार उनका अभिवादन करेंगे। सामान खरीदारी करने के दौरान पैसा लेने और खुले पैसे वापस करने के दौरान थैंक्यू कहेंगे। इस दौरान साफ-सफाई और रेल नियमों के पालन आदि के लिए भी प्रेरित करेंगे। वहीं, रेल प्रशासन स्टेशन के वेंडरों को भी ट्रेनिंग देने में जुटा है। उन्हें यात्रियों के साथ सौम्य व्यवहार करने, खाना परोसने के सलीके, खाने की शुद्धता बनाए रखने आदि के बारे में बताया जा रहा।

प्रतीकात्मक

एयर सर्विस से मिली प्रेरणा : आइआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि एयर होस्टेस के पैटर्न पर वेंडरों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया। पूर्व मध्य रेलवे के 600 वेंडरों को प्रथम चरण में प्रशिक्षित कर लंबी दूरी की विभिन्न ट्रेनों में लगाया गया है। शीघ्र ही दूसरे चरण का प्रशिक्षण कार्य आरंभ होगा। कौशल विकास के तहत मिले इस प्रशिक्षण से आचरण संबंधी शिकायतों में 80 फीसद की गिरावट आई है।

दैनिक जागरण
सबरंग
प्लान वीकेंड के
नई दिल्ली, शुक्रवार, 14 फरवरी, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें :sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

अद्भुत है नई और पुरानी दिल्ली का संगम

प्रेम के विविध रूप, हों भी क्यों न हर किसी ने इसे अपने नजरिए से जो देखा। आज की सांझ भी खास होगी जब एक ओर दो पहर का मिलन होगा। और दूसरी ओर शरण्या चंद्रन लव इन द टाइम ऑफ कामा में प्रस्तुति देंगी। प्रेम की अभिव्यक्ति को वह किस तरह देखती हैं...नृत्य के साथ पेश करेंगी। क्या खास होगा इस प्रेम उत्सव में...शरण्या चंद्रन की नृत्य यात्रा और दिल्ली...इसी पर संजीव कुमार मिश्र से विस्तार से बातचीत हुई। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश :

शरण्या चंद्रन। सौजन्य : सोशल मीडिया

बातचीत

● आपकी मां गीता चंद्रन इतनी बड़ी कलाकार हैं, उनसे नृत्य-संगीत का प्रशिक्षण कैसे मिला?
-हंसते हुए... मैंने चार साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया था। उसी समय मां ने नाट्य वृक्ष की स्थापना की थी। मुझे किसी तरह की अतिरिक्त सहुलियत ना मिले, इसलिए उन्होंने अन्य बच्चों के साथ ग्रुप में शामिल किया। मां, कितनी सख्त रहीं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यदि मुझे कक्षा में पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो जाती तो दरवाजे बंद हो जाते। फिर तो कक्षा खत्म होने के बाद ही प्रवेश मिलता। इस सख्ती के जरिए मां ने समय प्रबंधन का पाठ पढ़ाया।

● पहली प्रस्तुति तो आज तक जेहन में होगी?
-हां, वैसे तो पांच-छह साल की उम्र में ही प्रस्तुति देनी शुरू कर दी थी। लेकिन 13 साल की उम्र में जैसे ओडिशी में मंच प्रवेश होता है वैसे ही भरतनाट्यम में अरंगेत्रम होता है। भरतनाट्यम की परंपरा है कि जब शिष्य एकल प्रस्तुति के लायक हो जाता है तो उसे गुरु के सामने फाइनल प्रस्तुति देना होती है, जिसे अरंगेत्रम कहा जाता है। इसके बाद गुरु प्रदर्शन से संतुष्ट होकर गुरु उन्हें एकल प्रस्तुति की आज्ञा देते हैं। इस तरह 13 साल की उम्र में मैंने पहली प्रस्तुति दी। पहली प्रस्तुति की शुरुआत भी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर से हुई थी। डेढ़ घंटे तक एक के बाद एक प्रस्तुति थी। यह एक परीक्षा की तरह होता है। जिसमें पास होने के बाद कलाकार नृत्य संगीत समुदाय में शामिल हो जाता है।

● और मां के साथ मंच साझा करने का अवसर कब मिला? प्रस्तुति के वक्त कलाकार की तरह पेश आती हैं या मां तरह?
-करीब दस साल पहले पहली बार त्रिवेणी कला संगम में साथ प्रस्तुति दी थी। इसके बाद बेंगलुरु और दिल्ली में कई बार प्रस्तुति दीं। प्रस्तुति के दौरान उनसे प्रेरणा मिलती है। वो बहुत ही विनम्र हैं। प्रस्तुति से पहले व दौरान मेरे प्रति उनका व्यवहार एक प्रस्तुतिकर्ता की तरह ही होता है। बेटी की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करतीं। हां, वो कई बार मेरे कोरियोग्राफी संबंधी इनपुट पर अमल भी करती हैं।

● लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, पॉलिसी प्रोफेशनल्स भी पढ़ रही हैं..तो दोनों विपरीत विषयों में संतुलन कैसे बनाती हैं?
-बचपन में जब सड़कों के किनारे किसी गरीब को देखती तो उनके उत्थान के लिए सोचती। मेरी ख्वाहिश थी कि बड़े होकर कुछ ऐसा काम करूं जिससे समाज में बराबरी आए। इसलिए संगीत के साथ मैंने विभिन्न कोर्स किए। मैने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी की संस्था से जुड़ी। मैं तमिलनाडु, पंजाब आदि सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हूं। इसके तहत सरकारी योजनाओं में विभिन्न सुझावों के जरिए उन्हें और हितोपयोगी बनाने में मदद करती हूं।

● दिल्ली की कौन सी खासियत आपके दिल के करीब है?
-यह मेरा शहर है, मैं यही पली-बढ़ी हूं। हिंदी मीडियम सरदार पटेल स्कूल से पढ़ाई की। यहां के ऐतिहासिक स्मारकों से खास लगाव है। ये शहर एक तरह से नए और पुराने का संगम है...इसकी यही खूबसूरती मुझे बहुत लुभाती है। कुतुबमीनार के साथ आधुनिक रेस्त्रां का कंबिनेशन बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली की हर गली, चौक अपने अंदर कहानियां समेटे हैं। मुझे चांदनी चौक की पराठे वाली गली बहुत पसंद है।

● वैलेंटाइन डे के दिन प्रस्तुति, यह महज संयोग या खास प्रयोजन?
-वैलेंटाइन डे की वजह से ही हमने इस आयोजन का टाइटल भी ऐसा चुना। प्रेम की सब अलग व्याख्या देते हैं। मेरी प्रस्तुति अर्ध नारीश्वर है। यानी दो अलग-अलग अंग, लेकिन एक-दूजे में प्राण समाए हैं। इसी भावना को मंच पर अभिव्यक्त करूंगी। दूसरी व तीसरी प्रस्तुति में भी प्रेम के रंग दिखेंगे। इसमें शिव वृहदेश्वर के प्रेम में डूबी नायिका अपनी सखी से कहती है, 'हे कमलनयनी सखी, यह समय प्रेम के लिए कितना अनुदकूल है। मेरे प्रिय को मेरे पास ले आओ। मैं अद्वितीय वृहदेश्वर से एकाकार हो जाना चाहती हूं। क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? शीघ्रता से जाओ। कोयल लगातार खुशी के गीत गा रही है...उसकी यह खुशी...मेरे वियोग को बढ़ा रही है। क्या तुम मेरे लिए वृहदेश्वर को नहीं पुकार सकती हो? ये पुष्पों के तीर मुझे भेद रहे हैं। कृपया जाओ और मेरे इष्टदेव को मेरे पास ले आओ। वहीं कटाना भेदन में विद्यापति ने शिव के स्वरूप का वर्णन किया है। विद्यापति ने इसमें राधा को मुख्य चरित्र बनाया है जो कृष्ण की प्रतीक्षा करते समय कामदेव के बाणों का शिकार हो गई हैं। यह पीड़ा उनके लिए असहनीय होती जा रही है। वह कामदेव पर दोषारोपण करती हैं कि उन्होंने उसे शिव समझ लिया। इस क्रम में वह शिव से तुलना करते हुए अपने सौंदर्य का वर्णन करती हैं। वह बताती हैं कि शिव और उसका सौंदर्य कितना भिन्न है।

● आज होने वाली प्रस्तुति लव इन द टाइम ऑफ कामा के बारे में कुछ बताइए?
-यह बहुत ही यूनिक कांसेप्ट पर आधारित है। आमतौर पर भरतनाट्यम में दक्षिण भारतीय भाषा या फिर संस्कृत का समावेश होता है लेकिन हम विद्यापति के मैथिली में लिखे जीवन जीने के दो प्रेरणात्मक पदों का प्रयोग करेंगे। जो बयां करते हैं कि अर्ध नारीश्वर, शिव और शक्ति कैं। इन्हें अलग नहीं देखा जाए, ये एक ही हैं। विद्यापति लिखते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं...प्राण हैं। इसमें विद्यापति ने स्त्री व पुरुष और योग व भोग, पौरुष व स्त्रीत्व और निर्माण एवं विनाश के बीच अनूठे संतुलन को जीवंत किया है। मूलत : इनका अस्तित्व पृथक होता है, जो धीरे-धीरे एकाकार होते जाते हैं। इसके अलावा वरनम और कटाना भेदन की प्रस्तुति भी खास होगी।

- **कब** : 14 फरवरी, शाम 6 :30 बजे
- **कहां** : सीडी देशमुख ऑडिटोरियम, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

इस बार यहां चलें

ए मेलोडी इन कलर

भावनाओं की गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए इसे बड़ी ही संजीदगी से कैनवस पर उकेरा गया है। मानवीय संवेदनाओं के विविध भावों को समझने का बेहतरीन जरिया है ए मेलोडी इन कलर प्रदर्शनी, जिसमें सबरीना गिल ने जिंदगी जीने का फलसफा बताया है।

- **कहां** : कंवेंशन सेंटर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- **कब** : 14 से 17 फरवरी, सुबह दस से रात आठ बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

संगीतकारों की शाम

इंडो-फ्रेंच संगीत कलाकारों की महफिल सजेगी, जिसमें महुआ शंकर, गुलाबों सपेरा, मुराद अली खान, शोएब हसन, डिनो बंजारा, अमान अली खान सरीखे प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने का मौका मिलेगा। सारंगी मास्टर मुराद अली खान और फ्रेंच कंपोजर टीटी रॉबिन की जोड़ी दर्शकों को पसंद आएगी।

- **कहां** : एमएल भारती ऑडिटोरियम, लोदी इस्टेट, नई दिल्ली।
- **कब** : 14 फरवरी, शाम साढ़े छह बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

एक बार फिर 11वां स्मरण

युवा कलाकारों को एक बेहतरीन मंच प्रदान करता स्मरण एक बार फिर हाजिर है। इसके 11वें संस्करण में कई युवा कलाकार अपने हुनर से दिल्ली वालों का दिल जीतने को तैयार है। तबला पर इशान घोष, वोकलिस्ट डॉ अदिति शर्मा गर्ग समेत अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।

- **कहां** : अमलतास, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली।
- **कब** : 18 फरवरी, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

भारत के विविध रूप

भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक दिखता है। भारत की इसी विविध कला संस्कृति को प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। प्रदर्शनी में 70 कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी।

- **कहां** : मस्ट आर्ट गैलरी, एस-67, पंचशील पार्क, नई दिल्ली। ● **कब** : 31 मार्च तक, सुबह दस से शाम छह बजे तक।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

पालक पनीर फ्लेवर्ड खिचड़ी। सौजन्य : खिचड़ी एक्सपेरिमेंट

खिचड़ी के 16 अवतार

जायका

घर में अकेले हैं, खाना बनाने का मन नहीं है या तबीयत नासाज है... सबसे पहले हेल्दी खिचड़ी ही याद आती है। और अब तो खुद बनाने की भी झंझट नहीं। घर बैठे बिठाए ऑर्डर करो और आपके लिए खिचड़ी के 16 अवतार सुस्वाद के साथ हाजिर हैं। सबसे खास बात है कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों के स्वाद की विविधता का भी खयाल रखा गया है। हम बात कर रहे हैं खिचड़ी एक्सपेरिमेंट क्लाउड किचन की। जिसका स्वाद आपको ऑनलाइन फूड के विभिन्न एप ओला, स्विगी, जोमेटो पर मिल जाएगा।

-हर राज्य की खुशबू : अब तक विविध राज्यों के सिग्नेचर फूड...मसलन साउथ का डोसा-सांभर...गुजरात का फाफड़ा...महाराष्ट्र का वड़ा-पाव...वगैरहा...वगैरहा सुने होंगे, लेकिन खिचड़ी के ये 16 अवतार आपको देश के जायके साथ ही भाषा के विविध रूपों की तरह ही नजर आएंगे। आप यदि गुजराती स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको मूंग दाल से बनी मसालेदार खिचड़ी में लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची लहसून, प्याज हरी मिर्च, टमाटर आदि का स्वाद भी मिलेगा। इसमें हल्की सी मिठास का भी स्वाद ले पाएंगे। राजस्थानी और मराठी खिचड़ी का स्वाद भी कुछ इसी तरह का होता है। इसके अलावा यदि आपको दक्षिणी राज्यों की मसालेदार खिचड़ी का स्वाद लेना है तो उसमें आपको सांभर में इस्तेमाल होने वाले सारे खड़े मसाले तो मिलेंगे ही, उसके साथ खिचड़ी में सहजन के पीस भी मिलेंगे। जिससे खिचड़ी के स्वाद में सांभर जैसा फील मिलता है। इसके अलावा हेल्दी खिचड़ी में लंगरवाली, पालक पनीर, अचारी, मेथी, मुंबई पाव भाजी, बंगाली पंच फोरन खिचड़ी...जैसे विविध अवतारों में भी खाने को मिलेगी। इतना ही नहीं आप चाहें तो नॉनवेज खिचड़ी भी ऑर्डर कर सकते हैं। पापड़ और अचार का भी स्वाद ले पाएंगे।

स्वाद की मौलिकता : खिचड़ी एक्सपेरिमेंट के सारे फ्लेवर अब आपके लिए ओला फूड पर भी उपलब्ध हैं, इस पर ओला फूड के सीईओ प्रणय जीवराजका कहते हैं कि 'खिचड़ी एक्सपेरिमेंट का जन्म बाजार से ऑयली, मसालेदार खाने की अव्यवस्था से बचने और भोजन के अच्छे अनुभव के निर्माण के लिए किया गया है। इसमें हमने देश के राज्यों के विविध स्वादों का भी खयाल रखा है। हमारे देश में अलग-अलग राज्यों में कई तरह के मसालों का प्रयोग खाने में होता है, इसी के अनुकूल वही खड़े मसालों का टेस्ट इस खिचड़ी में भी मिलता है। खिचड़ी के स्वाद में लगातार बदलाव पर कहते हैं कि अपने उपभोक्ताओं द्वारा मिली प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कई खिचड़ी के स्वादों में मसालों का प्रयोग भी किया है। अपने प्रयासों को लगातार बढ़ाया है और इन्हीं प्रयासों की सहायता से उपभोक्ताओं के लिए सेहतमंद एवं अनुकूल विकल्पों के साथ उपस्थित हैं।

मनु त्यागी

पत्थरों में सूखीं तो रंगों में बसीं 'बावली'

दिल्ली को अपने ही अंदाज में जीने वाले ये कलाकार कैनवस पर जब कल्पनाओं को आकार देते हैं तो दर्शक भी मुग्ध हो जाते हैं। जागरण

स्केच प्रदर्शनी

शांत...उथला पानी होता था। चौड़ी सीढ़ियों पर सुकून और आनंद की तलाश में बावलियों के किनारे लोग बैठते थे। अच्छी यादें संजोते थे। पानी में बच्चे मछलियों की तरह अठखेलियां करते थे। लेकिन ये बावली खुद शांत हो गई हैं...खामोश हो गई हैं। पानी में अब कोई उछलकूद नहीं करता। किनारे पर इनके बैठकर अब कोई गीत नहीं गुनगुनता...प्रेम का अफसाना नहीं बुनता। हां, कुछ चुनिंदा बावली हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई को पार कर गईं और विकास की तेजधार से अपनी जान अब तक बचा गईं। आज ये अपने आगोश में सैकड़ों साल के दिल्ली के सफर की कहानियां समेटे खामोश नजर आती हैं। कहानियां, जिसका एक सिरा बूंद-बूंद पानी के संग्रहण और संरक्षण से जुड़ा है तो दूसरा नायाब वास्तु से। दिल्ली की बावलियों की इन्हीं कहानियों को अर्बन स्केचर दिल्ली ने प्रदर्शनी के जरिए लोगों के सम्मुख रखने की पहल की है। 29 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में कलाकारों ने बावलियों में अपनी कल्पनाओं का रंग भर उन्हें एक बार फिर से जीवंत कर दिया है, जिसे दिल्ली वाले खूब पसंद भी कर रहे हैं।

वक्त के साथ बदलती दिल्ली की कहानी: राजाओं की बावली महरौली के सुनहरे इतिहास से पर्दा उठाती है तो गंधक की बावली, निजामुद्दीन बावली, अग्रसेन की बावली, हिंदू राव की बावली, लाल किला बावली, द्वारका, वजीरपुर, अरब की सराय, फिरोजशाह कोटला, पुराना किला की बावली, तुगलकाबाद किला की बावली वक्त के साथ बदलती दिल्ली की कहानी सुनाती है। अर्बन स्केचर दिल्ली से जुड़े नीरज गुप्ता कहते हैं कि दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत किसी से छिपी नहीं है। गर्मियों में यह समस्या और बढ़ जाती है लेकिन ये बावलियां आज भी हमारे सामने सैकड़ों साल पुराने पानी के संग्रहण का नायाब उदाहरण पेश करती हैं। इनकी वास्तु तो आज भी अध्ययन योग्य है। हमारी कोशिश है कि बावलियों के स्केच के बहाने ही सही लोग इन बावलियों के इतिहास, इनकी महत्ता और इन्हें बनाने के दौरान की कहानियां जानें।

नौ कलाकारों की कलाकृतियां: दिल्ली की दिलचस्प कहानियां अपने भीतर समेटे इन बावलियों को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उकेरने का काम नौ पेशेवरों ने किया है। सप्ताह में छह दिन अपने काम में व्यस्त रहने के बावजूद रविवार को ये सभी सदस्य मिलते हैं और दिल्ली को अपने ही अंदाज में जीते हैं। नीरज निजी कंपनी के एमडी हैं तो जुजाना स्लोवाकिया दूतावास में राजनयिक हैं, जबकि जूही कुमार त्रिवेणी कला संगम से प्रशिक्षित हैं, वहीं दिशा चौहान कहती हैं कि मैं दिल्ली की इमारतों, स्मारकों की कहानियां स्केच के जरिए सुनाना चाहती हूं। लेडी इरविन कॉलेज की एल्युमिनाई गीता गुप्ता कहती हैं कि ये कलाकृतियां लोगों को अपने इतिहास से जुड़ी कहानियां सुनाती हैं। टीम के अन्य सदस्य सुनीता माथुर, सुमित नाहर, रणविजय कुमार और रजातेंदू विश्वास हैं। ये कहते हैं हम किसी निश्चित जगह पर मिलते हैं फिर आपस में विचार विमर्श करते हैं। अब तक इंडिया हैबिटेट सेंटर, महरौली, लोदी गार्डन, सफदरजंग मकबरा, राजाओं की बावली समेत 30 से ज्यादा जगहों पर हम बैठक कर चुके हैं। विचार विमर्श के बाद निश्चित स्थल को सब अपने कूची से कैनवस पर उतारते हैं। स्केच पैमाने पर खरा उतरा है नहीं यह जानने के लिए हम स्केचिंग के बाद दोबारा बैठक करते हैं।

संजीव कुमार मिश्र

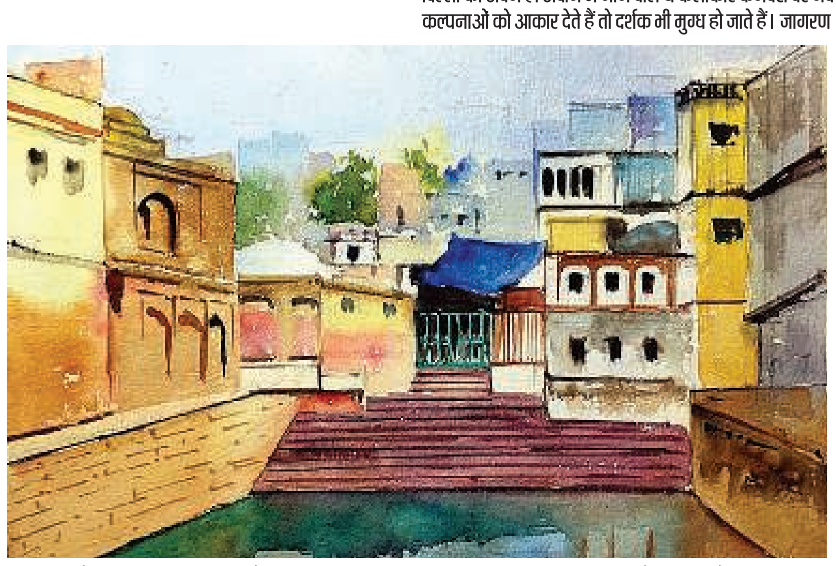

जल संरक्ष और नायाब वास्तु की मिसाल है दिल्ली की बावलियां। जूही कुमार ने बड़ी ही खूबसूरती से स्केच तैयार किया है। जागरण

बावली से जुड़ी कल्पनाओं का अद्भुत संयोजन है गीता गुप्ता के इस स्केच में। जागरण

- **आयोजन** : दिल्ली की बावली
- **कहां** : इंडिया हैबिटेट सेंटर
- **कब** : 29 फरवरी तक
- **प्रवेश** : निश्शुल्क
- **नजदीकी मेट्रो स्टेशन** : खान मार्केट

पं अनोखे की याद में

तबला सम्राट व बनारस घराने के पंडित अनोखे लाल मिश्र की याद में आयोजित यह कार्यक्रम संगीत प्रेमियों के लिए यादगार होगा। कार्यक्रम में अनोखे लाल मिश्र से जुड़े संस्मरण तो होंगे ही डॉ कुमार ऋषितोश और पंडित संतोष नाहर की शानदार प्रस्तुति होगी। वीकेंड पर यहां का रुख कर सकते हैं।

- **कहां** : इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली।
- **कब** : 14 फरवरी, शाम सात बजे।
- **प्रवेश** : निश्शुल्क।

गुल्लू के बेहतरीन स्वाद

नार्थ इंडियन में वेज और नॉनवेज जायकों का स्वाद लेना चाहते हैं तो गुल्लू बेहतरीन जगह है। यहां का मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी आदि खाने के लिए दिल्ली ही नहीं एनसीआर से भी ग्राहक आते हैं। यहां का फिश टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन टिक्का भी लोग खूब पसंद करते हैं।

- **कहां** : खुरेजी खास, शिवपुरी शाहदरा, पूर्वी दिल्ली।
- **कब** : दोपहर 12 से रात 11 बजे तक।
- **शुल्क** : 500 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

चाइनीज, इटालियन एक साथ

चाइनीज, जापानी और इटालियन जेन रेस्त्रां में सब कुछ एक ही टेबल पर उपलब्ध है। यहां सुशी, टॉम यॉम सूप, चिली पनीर, हक्का नूडल्स, चिली चिकन आदि का स्वाद ग्राहकों को दूर-दूर से खींच लाता है। सिर्फ खाना ही नहीं, वातावरण भी बेहद लाजवाब है।

- **कहां** : बी-25, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
- **कब** : सुबह साढ़े ग्यारह से रात साढ़े ग्यारह बजे तक।
- **शुल्क** : 1500 रुपये प्रति दो व्यक्ति।

इलाहाबाद बैंक ने कर्ज सस्ता किया

नई दिल्ली, प्रेट्र : इलाहाबाद बैंक ने कर्ज सस्ता करने का एलान किया है। बैंक ने तत्काल प्रभाव से एमसीएलआर में 0.05 फीसद की कटौती की है। इस कटौती के बाद एक साल की अवधि के लिए एमसीएलआर अब 8.25 फीसद हो गई है। रिटेल, ऑटोमोबाइल और पर्सनल लोन समेत ज्यादातर उपभोक्ता लोन पर ब्याज एक साल के एमसीएलआर के आधार पर ही लिया जाता है। बैंक ने एक दिन, तीन महीने और छह महीने की अवधि के लिए भी एमसीएलआर में कटौती की है।

बैंकों के पास आम जनों की पूंजी होती है। ऐसे में उन पर नियंत्रण और देखरेख बेहद जरूरी है। लेकिन बैंकों पर कानून का खौफ नहीं होना चाहिए।
— अरिजीत बसु
एमडी, एसबीआइ

सेंसेक्स	41,459.79	▼ 106.11
निफ्टी	12,174.65	▼ 26.55
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 41,484	▲ ₹266
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 46,630	▼ ₹55
डॉलर	₹ 71.31	▼ ₹0.02
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 55.32	

कारपोरेट हलचल

नाइजीरिया में एमजीआइसीसी का उद्घाटन

नाइजीरिया के राष्ट्रपति महमदोऊ इसोफू और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नाइजीरिया के नियामी में 21 जनवरी, 2020 को महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एमजीआइसीसी) का उद्घाटन किया। अफ्रीका में यह पहला स्थापित एमजीआइसीसी है। इसे भारत सरकार की नवरत्न कंपनी एनबीसीसी ने 14 महीनों के अल्प समय में तैयार किया है। एनबीसीसी के डायरेक्टर (कॉमर्शियल) राजेंद्र चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे।

वन धन योजना पर वर्कशॉप का आयोजन

नई दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में 11 फरवरी की शाम को प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) के तहत वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यमंत्री रेणुका सिंह और इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा अन्य प्रतिभागी इस वर्कशॉप में शामिल हुए। पीएमवीडीवाई का मकसद वन संपदाओं से संपत्ति अर्जन के तरीकों पर विचार करना और जनजीतीय लोगों की आमदनी और जीवन-स्तर में सुधार करना है।

गडकरी ने किया गेल स्टॉल का अवलोकन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने इसी सप्ताह ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुए ऑटो एक्सपो में गेल के स्टॉल का अवलोकन किया। गेल के निदेशक (वित्त) एके तिवारी ने उन्हें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में गेल के बढ़ते कदमों और ऑटो ईंधन के रूप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी।

पावरग्रिड ने केएसबी से किया एमओयू

भारत सरकार की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) के साथ एक एमओयू या समझौता किया है। इसके तहत गेल अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फंड से आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड (एएफएफडीएफ) 15 करोड़ रुपये देगी। इस फंड से पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनकी विधवाओं के बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में मदद दी जाएगी। एमओयू पर इसी सप्ताह बुधवार को पावर ग्रिड के डायरेक्टर (पर्सनल) वीके सिंह और केएसबी के सचिव ब्रिगेडियर मृगेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किए।

महिला कर्मियों के सशक्तीकरण के पक्ष में स्कोप

फोरम ऑफ वुमन इन पब्लिक सेक्टर (डब्ल्यूआइपीएस) ने स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (स्कोप) के तत्वावधान में हैदराबाद में 30वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसकी थीम 'पावर टु ट्रांसफॉर्म – डिसीजन टु एक्शन' रखी गई थी। तेलंगाना की राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया। इस मौके पर स्कोप के महानिदेशक अतुल सोबती भी मौजूद थे, जिन्होंने उद्घाटन भाषण दिया। कार्यक्रम में देशभर में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों की 600 से ज्यादा महिला कर्मचारियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण को दुनियाभर में प्राथमिकता दी जा रही है।

एएआइ ने किया बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआइ) एवं स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने चार दिवसीय ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसका उद्घाटन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में जवाहर कला केंद्र (जयपुर) की महानिदेशक किरन सोनी गुप्ता तथा जयपुर एयरपोर्ट के डायरेक्टर जेएस बलहारा समेत कई सम्मानित अतिथियों ने किया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार रमेश सचदेवा एवं राजस्थान बैडमिंटन संघ के उपाध्यक्ष मनोज दासोत भी मौजूद थे।

हुडको ने मनाया वार्षिक खेल दिवस 2020

हुडको ने त्यागराज स्टेडियम में अपना वार्षिक खेल दिवस आयोजित किया। इस मौके पर हुडको के चेयरमैन व एमडी एम. नागराज ने भाग लेने के लिए पधारे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा तथा मंत्रालय के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। मिश्रा ने नियमित व्यायाम के फायदों का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में व्यायाम को एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए।

निर्यात के लिए दर्जनभर क्षेत्रों पर दांव

पीयूष गोयल बोले ▸ कपड़ा क्षेत्र 10 वर्षों में सालाना 100 अरब डॉलर तक निर्यात कर सकता है

निर्यात तभी बढ़ता है जब विभिन्न क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के लिहाज से अग्रणी स्थिति में हों

प्रतीकात्मक

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा के लिहाज से बेहतर स्थिति वाले 12-13 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इनमें टेक्सटाइल जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं, जहां भारतीय निर्यात के बेहद मजबूत स्तर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। गोयल ने कहा कि निर्यात तभी बढ़ता है जब विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक, दोनों लिहाज से अग्रणी स्थिति होती है। उन्होंने कहा, 'हम अब 12-13 ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जहां हमारा मानना है कि भारत प्रतिस्पर्धा के लिहाज से बेहतर स्थिति में है और अधिक निर्यात कर सकता है।'

गोयल ने मानव निर्मित कपड़े का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार इस क्षेत्र पर कई वर्षों से ध्यान दे रही है। भारत ने हमेशा सूती कपड़ों पर ज्यादा ध्यान दिया है। इस दौरान दुनिया ने भी मानव निर्मित कपड़ों की तरफ ज्यादा लगाव दिखाया है। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि कपड़ा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से उन्होंने कहा है कि अगले 10 वर्षों के दौरान इस सेक्टर का निर्यात 100 अरब डॉलर (करीब सात लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचने की संभावना है, जो इस वक्त 37 अरब डॉलर (करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये) है। उन्होंने कहा, 'यही वजह है कि हम कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम कर रहे हैं।'

सर्विस सेक्टर की स्थिति बेहतर

गोयल ने कहा कि सर्विस सेक्टर का निर्यात अच्छी वृद्धि दर के साथ बढ़ रहा है। हालांकि दिसंबर में भारत का निर्यात कारोबार 1.8 प्रतिशत घटकर 27.36 अरब डॉलर का रह गया। यह लगातार पांचवां महीना रहा, जब निर्यात में पिछले साल के मुकाबले गिरावट आई है। इस दौरान प्लास्टिक, रत्न एवं आभूषण, लेदर प्रोडक्ट और रसायन कारोबार के निर्यात में भारी गिरावट दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ महीनों में कुल निर्यात एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 1.96 प्रतिशत कम यानी 239.29 अरब डॉलर का रहा। इस अवधि में आयात भी 8.9 प्रतिशत घटकर 357.39 अरब डॉलर का रहा।

एफडीआइ नियमों का पालन करें ई-कॉमर्स कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को चेताया है कि वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करें। उनका कहना था कि जब कोई कंपनी पांच हजार करोड़ रुपये के राजस्व पर छह हजार करोड़ रुपये का घाटा दिखाती है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ गड़बड़झाले का अंदेशा होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर ई-कॉमर्स कंपनियां एफडीआइ नियमों का पालन करें, तो भारतीय स्पर्धा आयोग (सीसीआइ) या भारत सरकार को जांच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गोयल ने दोहराया कि देश के कानून का पालन करने वाली कंपनियों का स्वागत है।

संरक्षण के उपाय जरूरी

सरकार द्वारा संरक्षणवाद की ओर जाने के कारणों के बारे में गोयल ने कहा कि जहां देश के पास खुद की क्षमता हो तो वहां संरक्षण एक जरूरत बनती है। जहां अनुचित प्रतिस्पर्धा हो या घरेलू उत्पादन लागत ऊंची हो तो इस तरह का व्यवहार जरूरी होता है। सरकार ने आम बजट में कई सामानों के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार का तर्क है कि कई क्षेत्रों में घरेलू कंपनियों को पर्याप्त मौके मिलने चाहिए।

टीवी आयात रोकने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : गैर-जरूरी चीजों का आयात घटाने के लक्ष्य के साथ सरकार टेलीविजन सेट के आयात पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय इस संबंध में प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि सरकार टेलीविजन सेट के आयात को रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी में रखने पर विचार कर रही है। इसका अर्थ है कि इसके आयात के लिए कारोबारियों को वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस लेना होगा। 2018-19 में भारत में करीब एक अरब डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) के टीवी सेट का आयात हुआ था। इसमें आधे से ज्यादा हिस्सेदारी चीन की थी। भारत को टीवी के अन्य आपूर्तिकर्ता देशों में वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और जर्मनी शामिल हैं।

घरेलू उत्पादन बढ़ाने और गैर-जरूरी वस्तुओं का आयात घटाने के लक्ष्य के साथ सरकार फर्नीचर आयात पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। हाल में पाम ऑयल पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। 2018-19 में हुए कुल 500 अरब डॉलर के आयात में से 'अन्य' की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं का आयात 100 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा था।

अगले पांच साल में सुरंग निर्माण पर एक लाख करोड़ का निवेश

▸ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने में मददगार होंगी सुरंगें

▸ परिवहन मंत्री गडकरी ने परियोजनाओं के लिए शर्तों में नरमी पर दिया जोर

नई दिल्ली, प्रेट्र : रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ने के लिए सरकार सुरंग निर्माण पर जोर दे रही है। इनकी मदद से किसी भी मौसम व परिस्थिति में उन इलाकों तक आवागमन सुचारु रखना संभव हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अगले पांच साल में इस दिशा में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जाएगा।

एक कार्यक्रम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री गडकरी ने कहा, 'देश में सुरंगों की जरूरत है, विशेषरूप से रणनीतिक रूप से महत्व वाले इलाकों में। इससे हर परिस्थिति में वहां आवागमन संभव होगा।' उन्होंने कहा कि सुरंग निर्माण समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी एवं वित्तीय शर्तों में नरमी की जरूरत है। इससे छोटी कंपनियां भी इनका हिस्सा बन सकेंगी। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रेक्ट मिलने के बाद काम ऐसी छोटी कंपनियों को सौंप देती हैं, जो कुछ कड़े मानकों के चलते सीधे बोली लगाने में अक्षम थीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी मैनेजमेंट के लिए नीति भी लाई जाएगी, क्योंकि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में खामी के कारण कई बार हाइवे सेक्टर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि देश में होने वाले कुल एक्सीडेंट में 40 फीसद राष्ट्रीय राजमार्गों पर होते हैं। इनमें गलत डीपीआर की भूमिका भी अहम होती हैं, क्योंकि इनके कारण सड़कों का डिजाइन मानक के अनुरूप नहीं हो पाता है।

इलेक्ट्रिक लेन के लिए आगे आएं कंपनियां : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1.03 लाख करोड़ रुपये के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर प्रस्तावित इलेक्ट्रिक लेन में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कंपनियों को नीतिगत मोर्चे पर सहयोग का भरोसा भी दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 1,320 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे का दिल्ली-जयपुर हिस्सा दिवाली से पहले पूरा हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेस-वे के इलेक्ट्रिक लेन के लिए भारतीय निवेशकों को आगे आना चाहिए। बायो-सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में भी व्यापक अवसर हैं।

कनाडा सरसों को बांग्लादेशी बताने के षडयंत्र का पर्दाफाश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ बांग्लादेश से आयातित सरसों तेल पर नहीं लगता सीमा शुल्क

▸ कनाडा के केनोला ऑयल को बांग्लादेशी बताकर ला रहे थे भारत, ड्राइवरों के नाम पर कंपनी, श्रमिकों के नाम पर सारा काम

कनाडा के केनोला ऑयल को बांग्लादेशी सरसों का तेल बताकर आयात करने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश राजस्व ब्यूरो विभाग (डीआरआइ) ने किया है। इस गैंग के शातिराना अंदाज का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि एक कंपनी के उपर एक कंपनी की लेयर बना रखी थी और आयात करने वाली मुख्य कंपनी के निदेशक के पद पर अपने ड्राइवरों व श्रमिकों को बिठा रखा था। इन्हें बखूबी मालूम है कि देश में अमेरिका व कनाडा के केनोला ऑयल की मांग बढ़ रही है। लेकिन इसके आयात पर 35 फीसद के शुल्क से बचने के लिए वे इनका आयात बांग्लादेश के जरिये करते थे और इसे बांग्लादेशी सरसों बताते थे। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते (साफ्टा) के मुताबिक बांग्लादेश से कई तरह के उत्पाद बिना शुल्क दिए ही लाए जाते हैं। इन्होंने सिर्फ दो महीनों में सरकार को 25 करोड़ रुपये के राजस्व की चपत लगाई है।

डीआरआइ के सूत्रों के मुताबिक भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित गोजाधंगा पोस्ट पर अचानक ही सफेद सरसों, पीली सरसों का आयात बढ़ने से उनका संदेह बढ़ा। पिछले वर्ष दिसंबर और इस वर्ष जनवरी में इनका 15 हजार टन आयात किया गया। जांच करने पर पता चला कि पहले कभी इनका आयात यहां से नहीं किया गया। यह बात भी सामने आई कि देश में अभी तक सालाना इनका आयात महज 500-1,500 टन होता रहा है। लेकिन अब अचानक ही दो महीनों में ही 10 गुना आयात हो चुका था। ये उत्पाद बेंगानी कमोडिटीज नाम की कंपनी आयात कर रही थी और यह कंपनी एक कार्टेल बनाकर काम कर रही थी।

लेकिन जांच एजेंसियों को बड़ी जानकारी मिलनी अभी बाकी थी। इस वर्ष आठ फरवरी को जब छापेमारी की गई और कंपनी के गोदाम पकड़े गए तो यह बात सामने आई कि कंपनी को चलाने वालों और मालिक के नाम में कोई समानता नहीं है। संभवतः बंगाल में कार्टेल में गनेट ट्रेडर्स के नाम से एक आयातक फर्म सामने आया। इसके सुरेश हलदर व पवन शा नामक दो निदेशक बताए गए। कंपनी के कागजों में इन्हें बस सातवीं व 10वीं पास बताया गया है। जांच आगे बढ़ी तो यह बात सामने आई कि किसी प्रदीप्तो मजूमदार की सौविक एक्सपोर्ट्स नाम की एक दूसरी कंपनी गनेट ट्रेडर्स को चलाती है। हलदर व शा दोनो प्रदीप्तो मजूमदार के ड्राइवर हैं। जिस व्यक्ति को कंपनी के रोजाना कामकाज की जिम्मेदारी कागजों में दी गई थी वह एक अशिक्षित और असल में कंपनी में काम करने वाला एक श्रमिक था। बहरहाल, अब इस ग्रुप का पर्दाफाश हो गया है और डीआरआइ के सूत्रों का कहना है कि इस तरह के दूसरे तमाम गिरोहों पर भी जल्द ही कानून का चाबुक चलेगा।

एसएंडपी ने बरकरार रखी भारत की 'बीबीबी-' रेटिंग

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल की नरमी के बावजूद वैश्विक रेटिंग एसएंडपी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश की रेटिंग को स्टेबल आउटलुक के साथ 'बीबीबी-' पर बनाए रखा है। एजेंसी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से तेज वृद्धि की स्थिति में बनी हुई है। विकास दर में अगले दो से तीन साल बाद लंबी अवधि तक सुधार की उम्मीद है। किसी देश की 'बीबीबी-' रेटिंग वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी पर्याप्त क्षमता को दर्शाती है। एसएंडपी ने कहा, 'हाल की तिमाहियों में भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद हमारा मानना है कि यहां स्ट्रक्चरल ग्रोथ बेहतर बनी हुई है। इस लिहाज से जीडीपी वृद्धि में अगले दो से तीन साल में दीर्घकालिक रुझान के साथ सुधार की संभावना है।' रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सुधरकर छह फीसद, उससे अगले वर्ष में सात फीसद और उसके बाद 7.4 फीसद तक पहुंच जाएगी। एजेंसी ने कहा, 'जीडीपी वृद्धि में हाल में आई सुस्ती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था उसकी समकक्ष दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी।' एसएंडपी ने कहा कि 2020 से 2024 के बीच मौद्रिक, वित्तीय एवं अन्य कारकों के समर्थन से आर्थिक सुधार को गति मिलेगी।

इस वर्ष मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस रद

▸ कोरोना वायरस की चिंता के चलते जीएसएम एसोसिएशन ने किया फैसला

▸ 24-27 फरवरी को स्पेन के बार्सिलोना में होना था यह आयोजन

लंदन, एजेंसियां : दूरसंचार क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (एमडब्ल्यूसी) कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। दूरसंचार कंपनियों के वैश्विक संगठन जीएसएम एसोसिएशन (जीएसएमए) ने कोरोना वायरस से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण स्पेन के बार्सिलोना में होने वाले एमडब्ल्यूसी का इस वर्ष का संस्करण रद करने का फैसला किया है। यह कार्यक्रम 24-27 फरवरी को होना था।

जीएसएमए ने गुरुवार को अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा है कि एमडब्ल्यूसी-2020 को लेकर आगे बढ़ना असंभव हो गया था। बयान के मुताबिक 'बार्सिलोना और स्पेन में सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाए रखने के लिए संगठन ने इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस रद कर दिया है। इस समय हमारी सहानुभूति चीन और दुनियाभर में कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के साथ है। हम मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के 2021 और आगे के संस्करणों के लिए साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।'

जीएसएमए के सीईओ जॉन हॉफमैन ने एक बयान में कहा, 'कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच यात्रा और अन्य परिस्थितियों को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जताई जा रही है।' एमडब्ल्यूसी में हर वर्ष लगभग एक लाख लोग आते हैं। इनमें 6,000 से अधिक लोग केवल चीन से बार्सिलोना आते हैं। लेकिन पिछले लगभग एक महीने में कोरोना वायरस से 1,100 से ज्यादा मौतें हो जाने की वजह से आयोजकों ने एमडब्ल्यूसी को रद करना ही ठीक समझा।

निराशाजनक फैसला : सीसीएस इनसाइट कंसल्टेंसी के टेलीकॉम इंडस्ट्री विश्लेषक बेन वुड ने कहा, 'यह बेहद निराशाजनक है कि इस साल शो नहीं होगा। ऐसी छोटी कंपनियां जो खास तौर पर ऐसे मौकों के लिए अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा निवेश करती हैं, उनके नुकसान को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। एमडब्ल्यूसी कई लोगों के लिए बड़ा मौका होता है। अब उन्हें इस कठिन परिस्थिति से उबरने का कोई नया तरीका तलाशना होगा, जो चुनौतीपूर्ण है।'

ऐसा होता है आयोजन : जीएसएमए वर्ष 2006 से बार्सिलोना में लगातार एमडब्ल्यूसी का आयोजन करता रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के मंत्री, नीति निर्माता, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां एवं उनके अधिकारी इस सेक्टर की टेक्नोलॉजी में आए बदलावों समेत अतीत, वर्तमान और भविष्य पर मंथन करते हैं। इस मौके पर दुनियाभर की टेलीकॉम कंपनियां भविष्य की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की झलक भी दिखाती रही हैं।

पीछे हट गई थीं कई बड़ी कंपनियां : चीन में फैले कोरोना वायरस के चलते कई दिग्गज कंपनियों ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से किनारा कर लिया था। इनमें वोडाफोन, सिस्को, एलजी, नोकिया, वीवो, एनटीटी डोकोमो, सोनी, अमेजन, फेसबुक, मीडियाटेक और इंटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

कोरोना वायरस के संकट से ग्लोबल टेक सेक्टर हलकान

नई दिल्ली, प्रेट्र : चीन में फैले कोरोना वायरस ने दुनियाभर की आर्थिक सेहत को बीमार कर दिया है। इस आफत से हलकान सेक्टरों में टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे अहम है। इसकी बड़ी वजह है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा टेक मैन्यूफैक्चरिंग हब है। वहां छाया संकट पूरी दुनिया के टेक सेक्टर को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने इस बारे में चिंता जताई है।

चीन में कोरोना के कारण हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50,000 लोग इसकी चपेट में बताए जा रहे हैं। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स का कहना है कि वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए दूसरी तिमाही का आधा हिस्सा भी मुश्किल भरा रह सकता है। फिलहाल हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर और सेमीकंडक्टर कंपनियों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। अगर वायरस का खतरा नहीं थमा तो स्थिति और जटिल हो सकती है।

बाजार को नहीं रास आए महंगाई के आंकड़े, सेंसेक्स लुढ़का

वजह

चीन में कोरोना के नए मामले सामने आने से निवेशकों में चिंता, प्रमुख एशियाई व यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट का रुख

मुंबई, प्रेट्र : औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, खुदरा महंगाई की ऊंची दर और चीन में कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने से निवेशकों की धारणा कमजोर हुई है। इससे गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 106.11 अंक गिरकर 41,459.79 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 26.55 अंक गंवाकर 12,174.65 पर बंद हुआ।

चीन में कोरोना वायरस का संकट कम होता नहीं दिख रहा है। वायरस के नए मामले सामने आने और एक ही दिन में 200 से ज्यादा लोगों की मौत ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसका असर दुनियाभर के बाजारों पर पड़ रहा है। इसके अलावा घरेलू मोर्चे पर कुछ निराशाजनक वृहद आर्थिक आंकड़ों ने भी भारत में निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। बुधवार को आए आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन 0.3 फीसद सिकुड़ गया। वहीं खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमत के कारण जनवरी, 2020 में खुदरा महंगाई 7.59 फीसद पर पहुंच गई। यह 68 महीने का उच्चस्तर है। महंगाई बढ़ने के कारण रिजर्व बैंक की ओर से मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद कमजोर पड़ी है। इससे ब्याज आधारित सेक्टर जैसे बैंकिंग, फाइनेंस और ऑटो में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 3.68 फीसद की गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयरों में आई। एनटीपीसी, टाटा स्टील, आइसीआइसीआइ बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी में भी गिरावट आई। इस दौरान टाइटन, एसबीआइ, इन्फोसिस, सन फार्मा और टेक महिंद्रा के शेयर बढ़त में रहे। सेंसेक्स की 16 कंपनियों के शेयर गिरावट में रहे, जबकि 14 में बढ़त दर्ज की गई।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के लक्ष्य से बहुत ऊपर पहुंच गई है। इससे ब्याज दरों पर आधारित शेयरों में गिरावट आई। बीएसई में स्मालकैप और मिडकैप शेयरों का प्रदर्शन शानदार रहा।

कोरोना की चिंता में प्रमुख एशियाई बाजारों में गिरावट आई। यूरोपीय बाजार भी शुरुआती कारोबार में गिरावट में रहे। इस बीच, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि कोरोना के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़े दुष्प्रभाव ने तेल की मांग गिरा दी है। दशक में पहली बार तिमाही आधार पर तेल की मांग में कमी आती दिख रही है। इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है।

प्रतीकात्मक

यस बैंक के शेयरों में उछाल

गुरुवार को निजी क्षेत्र के यस बैंक के शेयरों में छह फीसद से ज्यादा का उछाल देखा गया। बीएसई में कंपनी के शेयर 5.68 फीसद चढ़कर 37.20 रुपये और एनएसई में 6.39 फीसद उछलकर 37.45 रुपये पर बंद हुए। कंपनी प्रबंधन की तरफ से फंड जुटाने की खबरों से शेयरों में तेजी देखी गई। प्रबंधन का कहना है कि इस समय बैंक के लिए फंड जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण से अक्टूबर-दिसंबर तिमाही का नतीजा भी अभी रोक दिया गया है।

21 लोगों को जिंदा जला दिया उत्तरी नाइजीरिया के एक गांव में सशस्त्र हमलावरों द्वारा। मरने वालों में 16 एक ही परिवार के हैं। सशस्त्र हमलावरों द्वारा लूट का विरोध करने पर इस घटना को अंजाम दिया गया।

हर बीमारी का नाम होता है 'खास'

1,350 से अधिक लोग आधिकारिक रूप से कोरोना वायरस के कारण जान गंवा चुके हैं

वैसे तो शेक्सपियर ने कहा था, 'नाम में क्या रखा है।', लेकिन नाम का बहुत महत्व है। इसी वजह से धरती पर तबाही लाने वाले तूफान और घातक बीमारियों के नाम तक दिए जाते हैं। समुद्री तूफानों के विचित्र नाम अक्सर हमारे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार एक नाम पूरी दुनिया के सामने आया है 'कोविड-19 (सीओवीआइडी)'। इस नाम से इस समय दुनिया खौफ में है। 1,350 से अधिक लोग आधिकारिक रूप से इस बीमारी से मारे जा चुके हैं, जबकि हजारों लोग संक्रमित हैं और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो गई है। आप सही सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं नोवल कोरोना वायरस की, जिसे कोविड-19 (सीओवीआइडी) लिखा जाएगा और संक्षेप में एनसीओवी-19।

इसलिए पड़ी जरूरत

संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पहले एक ही बीमारी को दुनिया में अलग-अलग नामों से जाना जाता था, जिसकी वजह से कई बार भ्रम की स्थिति हो जाती थी। इस समस्या का निदान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने निकाला। अब यह डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी है कि वह किसी नई बीमारी को एक नाम दे, ताकि सभी शोध संस्थानों और अस्पतालों को एक मानक मिले। इससे इलाज में काफी मदद भी मिलती है।

क्या है सीओवीआइडी-19

सीओवीआइडी-19 को डिकोड करें, तो सीओ का मतलब है कोरोना, वीआइ का अर्थ है वायरस और डी डिजीज के लिए इस्तेमाल किया गया है। 19 वर्ष 2019 के लिए उपयोग में लाया गया है। डॉक्टर एनसीओवी-19 भी लिख सकते हैं। यहां एन का मतलब नोवल, सीओ का अर्थ कोरोना और वी वायरस के लिए इस्तेमाल किया गया है।

यह है प्रक्रिया

डब्ल्यूएचओ अचानक किसी बीमारी को कोई भी नाम नहीं देता है। इसके पीछे बड़ी कवायद होती है। वैश्विक संगठन का एक विभाग है इंटरनेशनल क्लासीफिकेशन ऑफ डिजीज (आइसीडी)। इसका यह काम है कि वह किसी बीमारी को कोई नाम दे। इस काम के लिए वह सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) से अहम जानकारी हासिल करता है। दोनों संगठन आइसीडी को बताते हैं क्या जानवरों या पेड़-पौधों में उक्त बीमारी से मिलते-जुलते लक्षण वाली बीमारी तो नहीं मिलती है। पहले बीमारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो बीमारी को नया नाम मिलता है।

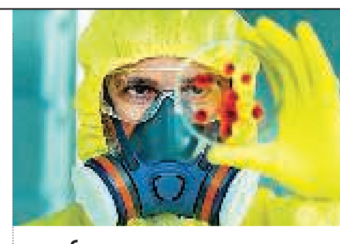

सतर्कता आवश्यक

आइसीडी किसी बीमारी का नाम रखने में बहुत सतर्क रहता है। डब्ल्यूएचओ के मानक के अनुसार किसी बीमारी के नाम से किसी धर्म, नस्ल, देश और इलाके की भावनाओं को आहत करने वाली न हो। साथ ही बीमारी के लिए किसी देश, नस्ल, इलाके को किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले नाम भी नहीं रखा जा सकता है।

'एन' बनाता है बीमारी को घातक

जब किसी बीमारी के नाम के आगे 'एन' शब्द लिख दिया जाता है तो समझ लें कि वह बीमारी घातक है और डॉक्टरों के लिए उसका इलाज करना कठिन है। नोवल शब्द के लिए एन लिखा जाता है। नोवल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी बीमारी का पैथोलॉजिकल रिकॉर्ड नहीं होता और शोधकर्ताओं को बिल्कुल शुरुआत से बीमारी को समझना पड़ता है।

न्यूज गैलरी

कैलिफोर्निया के गुरुद्वारे में कोबे ब्रायंट को दी गई श्रद्धांजलि

लास एंजिलिस : कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो स्थित गुरुद्वारा नानकसर में सैकड़ों लोगों ने दिवंगत बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट को श्रद्धांजलि दी। महान खिलाड़ी के असमय निधन पर पिछले हफ्ते भी गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं ने कोबे की बास्केटबॉल टीम लॉस एंजिलिस लेकर्स की जर्सी पहन रखी थी। पुरुष और बच्चे जहां लेकर्स की बैंगनी और पीली जर्सी में थे, वहीं महिलाओं ने इसी रंग की सलवार कमीज पहन रखी थी। गत 26 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 41 वर्षीय कोबे और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। श्रद्धांजलि सभा में कोबे की याद में कई बच्चे रोते दिखे। इन्हीं लोगों में शामिल अंगद संधू ने बताया कि उन्होंने कोबे को देखकर ही बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था। उनकी तरह अमेरिका में सिख समुदाय के लोग कोबे के प्रशंसक हैं। (आइएएनएस)

अमेरिकी सीनेटरों ने भारत में मानवाधिकार का मुद्दा उठाया

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले चार अमेरिकी सीनेटरों ने कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति और देश में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने की मांग की है। सीनेटरों ने कहा है कि सैकड़ों कश्मीरी हिरासत में हैं। चारों सीनेटरों ने खुद को भारत का पुराना मित्र करार दिया है। विदेश मंत्री माइक पोंपिओ को 12 फरवरी को लिखे गए अपने पत्र में सीनेटरों ने कहा है कि भारत ने अब लोकतंत्र के माध्यम से सबसे लंबा इंटरनेट प्रतिबंध लगाया है। 70 लाख लोगों के लिए चिकित्सा सुविधा, व्यापार और शिक्षा तक पहुंचना बाधित हो गया है। कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने एकतरफा तरीके से जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता समाप्त कर दी। सीनेटरों में क्रिस वैन हॉलेन, टोड यंग, रिचर्ड जे डरबिन, लिंडसे ओ ग्राहम शामिल हैं। (प्रेट्र)

चीन में कोरोना वायरस से एक दिन में 254 की मौत

आपदा ▸ संक्रमित लोगों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंची

242 मौतें अकेले हुबेई प्रांत में हुईं, जबकि 12 अन्य की मौत चीन के दूसरे प्रांतों में हुई

बीजिंग, एजेंसियां : चीन में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 254 मौतें हुईं। इस तरह इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1367 पहुंच गई है। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 60 हजार के करीब पहुंच गया है। चीन के वुहान शहर में 31 दिसंबर को कोरोना वायरस से पीड़ित पहला मरीज सामने आया था।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बुधवार को सबसे ज्यादा 242 मौतें अकेले हुबेई प्रांत में हुईं जबकि 12 अन्य की मौत चीन के दूसरे प्रांतों में हुई। करीब 15 हजार नए मामले भी सामने आए हैं। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 59,804 हो गई है। हुबेई की राजधानी वुहान से पूरे चीन समेत दुनिया के लगभग 30 देशों में यह वायरस फैला है। छह करोड़ की आबादी वाले हुबई में पिछले करीब तीन हफ्ते से आवाजाही ठप है।

भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों ने लगाई गुहार: वुहान में रह गए भारतीय और पाकिस्तानी छात्र सहमे हुए हैं। उन्होंने अपने-अपने देश की सरकारों से वुहान से निकाले जाने के लिए गुहार लगाई है। भारत वुहान से पहले ही अपने 647 नागरिकों को निकाल चुका है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि करीब 100 भारतीय अब भी बचे हो सकते हैं। जबकि हुबेई में करीब एक हजार पाकिस्तानी छात्र बताए जा रहे हैं। हालांकि अपने नागरिकों को नहीं निकालने के चलते पाकिस्तान सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

मच्छरों से बचने के लिए फागिंग : चीन से फैले कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे के सैन लोरेंजो शहर में स्थित एक स्कूल में स्वास्थ्य कर्मचारी मच्छरों से बचाव के लिए फागिंग कर रहा है। प्रशासन कोई भी ऐसा खतरा मोल लेना नहीं चाहता। रायटर

बुजुर्गों को क्रूज से निकलने की इजाजत जापान में कोरोना से हुई पहली मौत

टोक्यो, रायटर : जापान अपने तट पर दस दिनों से खड़े डायमंड प्रिंसेज क्रूज से उन बुजुर्गों को निकलने की इजाजत देगा, जिनके कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होने की पुष्टि हो चुकी है। क्रूज पर वायरस के 44 नए मामले सामने आने के साथ ही पीड़ितों की संख्या बढ़कर 218 हो गई है। पीड़ितों में चालक दल के दो भारतीय सदस्य भी शामिल हैं। हांगकांग से आया यह क्रूज तीन फरवरी से योकोहामा बंदरगाह पर खड़ा है। संक्रमण फैलने के डर से किसी को क्रूज से उतरने नहीं दिया गया। इस बीच जापान में वायरस से एक महिला की मौत भी खबर है।

जापान के स्वास्थ्य मंत्री कट्सुनोबु कातो ने कहा, 'कुछ बुजुर्ग यात्रियों को 14 दिन की अवधि पूरी होने से पहले ही यानी शुक्रवार से क्रूज से निकलने की इजाजत होगी। हम लोगों की सुरक्षा के लिए हर प्रयास करेंगे।' पहला मामला सामने आने के बाद क्रूज को 14 दिन के लिए अलग-थलग रखा गया है। यह अवधि 19 फरवरी को खत्म होगी।

80 फीसद यात्री बुजुर्ग: क्रूज के करीब 80 फीसद यात्रियों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। 215 यात्री 80 साल और 11 नब्बे साल के हैं। क्रूज पर करीब 3,700 लोग सवार हैं। इनमें करीब 132 भारतीयों समेत 1,100 तो चालक दल के सदस्य हैं। क्रूज पर छह भारतीय यात्री भी बताए जा रहे हैं। डायमंड प्रिंसेज ब्रिटिश क्रूज है। इसका संचालन प्रिंसेज क्रूज लाइंस करती है। 290 मीटर लंबा यह क्रूज 2004 से संचालित किया जा रहा है।

नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री

- प्रीति पटेल का गृह मंत्री पद बरकरार
- आगरा के आलोक शर्मा बने वाणिज्य मंत्री
- पाकिस्तानी साजिद जावीद की हुई छुट्टी

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक को नया वित्त मंत्री बना गया है। उन्हें पाकिस्तानी मूल के साजिद जावीद को हटाकर वित्त मंत्री बनाया गया है। यूरोपीय यूनियन से हटे ब्रिटेन में यह पद अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि आने वाले महीनों में ब्रिटेन को दुनिया के देशों से अपने व्यापार संबंधों का नया ढांचा खड़ा करना है। सुनक को लेकर एक खास बात और...वह सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं।

इस प्रकार से ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार में गृह मंत्री पद पर प्रीति पटेल बरकरार हैं और सुनक को वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। ब्रिटिश सरकार के दो अति महत्वपूर्ण पद भारतीयों के हिस्से में आए हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री जॉनसन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। भारतीय मूल के आलोक शर्मा और स्वेला ब्रेवरमैन को भी मंत्रिमंडल में प्रोन्नति मिलने की उम्मीद है। सुनक इससे पहले वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और उन्हें ब्रिटिश खजाने के मुख्य सचिव का दर्जा प्राप्त था। उन्हें ब्रिटिश सरकार के उभरते सितारे के रूप में देखा जा रहा है।

39 वर्षीय सुनक का कार्यालय प्रधानमंत्री के डाउनिंग स्ट्रीट आवास एवं कार्यालय के ठीक बगल में होगा। ब्रिटिश मीडिया मौजूदा परिप्रेक्ष्य में वित्त मंत्री सुनक को सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कहा है- महारानी ने ब्रिटिश खजाने के प्रमुख के तौर पर ऋषि सुनक की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी है।

मां की दुकान के तजुर्बे से होगा ब्रिटेन का निर्माण: यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजरवेटिव पार्टी के सांसद सुनक की शादी मूर्ति की बेटी अक्षता के साथ हुई है। वह सबसे पहले 2015 में चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। इसके बाद बहुत तेजी से कंजरवेटिव पार्टी के ढांचे में उन्होंने तरक्की की। वह प्रधानमंत्री की ब्रेक्जिट रणनीति को अंजाम दिलाने में विश्वसनीय व्यक्ति बनकर उभरे। ब्रिटेन में जन्मे सुनक ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है।

उनका मूल पेशा इन्वेस्टमेंट बैंकर का है। इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में उन्होंने राजनीति में आने से कुछ ही पहले एक अरब पाउंड (करीब नौ हजार करोड़ रुपये) की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म स्थापित की थी। सुनक की मां फार्मेसिस्ट थीं जबकि पिता ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य सेवा में जनरल प्रेक्टिशनर थे। सुनक बताते हैं कि मां की छोटी सी दवाओं की दुकान में बैठकर ही उन्हें बड़े स्तर पर कारोबार करने का तजुर्बा प्राप्त हुआ। अब उसी तजुर्बे का लाभ लेते हुए वह ब्रिटेन के शानदार भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे।

ब्रिटेन के नए वित्तमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट में। रायटर

शर्मा को संरा के वैश्विक सम्मेलन के आयोजन का जिम्मा

लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन में भारतीय मूल के वाणिज्य मंत्री आलोक शर्मा को नवंबर में पर्यावरण पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सम्मेलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें गुरुवार को ही प्रोन्नत कर ब्रिटेन का वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार देश में इस तरह के वैश्विक सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी अनुभवी और वरिष्ठ मंत्री को सौंपी जाती है।

सीओपी26 नाम के इस वैश्विक सम्मेलन में ब्रिटेन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ऊर्जा मंत्री क्लेयर पेरी ओनील पर थी लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सार्वजनिक आलोचना के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री पर्यावरण सुधार की योजनाओं को वास्तव में लागू नहीं करना चाहते। अब ब्रिटेन में पर्यावरण सुधारों की जिम्मेदारी शर्मा के कंधों पर है। उन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया के देशों को तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। इस सम्मेलन को लेकर ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच भी मतभेद चल रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि स्कॉटलैंड की सरकार को हमारे साथ मिलकर कार्य करना चाहिए जिससे संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन सफल हो सके।

मुंबई हमले के अपराधियों को मिले सजा : भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- हाफिज सईद को स्थानीय अदालत से मिली सजा से भारत बहुत संतुष्ट नहीं
- वित्तीय कार्यवाई कार्य बल की बैठक को ध्यान में रख कर दी गई है यह सजा

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की स्थानीय अदालत से मिली सजा को लेकर भारत बहुत संतुष्ट नहीं है। भारत मानता है कि यह सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस बात के संकेत नहीं दिए गए हैं कि वह आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए वाकई गंभीर है। पाकिस्तान जब तक अपने यहां आतंकी ढांचे को नष्ट नहीं करता है और मुंबई हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए कदम नहीं उठाता है, तब तक उसे गंभीर नहीं माना जा सकता। हाफिज सईद को सजा भी वित्तीय कार्यवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की बैठक को ध्यान में रख कर दी गई है।

पाकिस्तान की एक अदालत ने भारत में कई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता हाफिज सईद को सजा सुनाई है। सईद को दो मामलों में दोषी पाया गया है। इन दोनों मामलों में उसे 11 वर्षों की सजा सुनाई गई है। यह सजा उसे तब दी गई है जब तीन दिन बाद रविवार से पेरिस में एफएटीएफ की बैठक शुरू होने वाली है। एफएटीएफ पूरी दुनिया में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने व भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम करता है।

इसने वर्ष 2018 में ही पाकिस्तान को 20 कामों की सूची सौंपी थी। आतंकी गतिविधियों से जुड़े संगठनों की वित्तीय सहायता पर रोक लगाने के मामले में पाकिस्तान के बेहद खराब रिकार्ड को देखते हुए उसे उन कार्यों की सूची सौंपी गई थी। अभी पाकिस्तान इसकी निगरानी सूची में है। माना जाता है कि आगामी बैठक में प्रतिबंधित होने वाले देशों की सूची से बचने के लिए ही पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आतंकी सईद को सजा सुनाने का रास्ता निकाला है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि एफएटीएफ की बैठक से पहले इस तरह का फैसला करने की वजह से अभी यह साफ होना शेष है कि पाकिस्तान कितना गंभीर है? अभी यह भी देखना है कि वह दूसरे आतंकियों के खिलाफ गंभीरता दिखाता है या नहीं।

'सईद की सजा लश्कर की जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम कदम'

वाशिंगटन, प्रेट्र : मुंबई 2008 आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने का अमेरिका ने स्वागत किया। अमेरिका ने कहा कि लश्कर ए-तैयबा की जवाबदेही तय करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। पाकिस्तान की यह कार्रवाई विश्व समुदाय के प्रति आतंकवाद से निपटने में उसकी प्रतिबद्धता दर्शाती है।

अमेरिका के विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में हाफिज सईद को बुधवार को साढ़े पांच साल- साढ़े पांच साल कैद और दोनों मामलों में 15-15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों की कार्यवाहक सहायक विदेश मंत्री एलिस जी. वेल्स ने कहा, 'आज, हाफिज और उसके साथियों को दोषी ठहराया जाना, लश्कर ए-तैयबा की उसके अपराधों के लिए जवाबदेही तय करने और पाकिस्तान की आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने की उसकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' वेल्स ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि यह देश के भविष्य के हित में है कि वह अपनी सरजमीं का इस्तेमाल देश विरोधी तत्वों को नहीं करने दें। बता दें कि आतंकवाद निरोधक अदालत ने आतंकवाद को धन मुहैया कराने के मामलों की रोजाना सुनवाई करते हुए 11 दिसम्बर को सईद एवं उसके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था। अदालत ने बुधवार को दोनों मामलों में सईद को साढ़े पांच साल- साढ़े पांच साल कैद की सजा सुनाई और दोनों मामलों में 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

लाहौर के एसएसपी और पूर्व अटार्नी जनरल अगवा

लाहौर, एएनआइ : पाकिस्तान में लाहौर शहर के एसएसपी मुफखार अदील और पूर्व सहायक अटॉर्नी जनरल शाहबाज अहमद को अगवा कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन दोनों का अभी कोई सुराग नहीं लगा है।

न्यूज इंटरनेशनल अखबार में गुरुवार को छपी एक खबर के अनुसार, लाहौर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अदील और शाहबाज दोस्त हैं। पिछले हफ्ते संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ अज्ञात लोगों ने दोनों को अगवा कर लिया। पंजाब प्रांत के आइजी शोएब दस्तगीर ने मामले की जांच का आदेश दिया है। शहर के जोहर टाउन और नसीराबाद पुलिस स्टेशनों में अलग-अलग मामले दर्ज कराए गए हैं। नसीराबाद में दर्ज शिकायत में कहा गया है कि शाहबाज सात फरवरी को अपने दफ्तर से निकले थे, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आए। इसी दिन एसएसपी के भी लापता होने की खबर आई। अदील की सरकारी गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के बाहर से बरामद की गई है। दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अदील पिछले कुछ दिनों से किसी मामले की गोपनीय जांच कर रहे थे।

इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटा

इंडोनेशिया के मेरापी पर्वत पर ज्वालामुखी में विस्फोट होने से आकाश में दो किलोमीटर (करीब 6, 500 फीट) तक घना धुआं छा गया। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। विस्फोट के बाद प्रशासन ने एहतियातन दस किलोमीटर परिधि के इलाकों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। एएफपी

संकट बरकरार

जंगलो की आग से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया को बारिश से राहत तो मिली, लेकिन एक नया संकट खड़ा हो गया

ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश से बुझी आग, उफनाए बांध

सिडनी, एएफपी : जंगलों की आग से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में राहत की बारिश हुई है। इससे ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत के जंगलों में लगी आग पूरी तरह बुझ गई है, लेकिन कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण प्रांत के कई बांध उफना गए हैं।

न्यू साउथ वेल्स की ग्रामीण अग्निशमन सेवा के प्रवक्ता ने कहा, 'प्रांत के जंगलों में सभी जगह लगी आग बुझ गई है। बारिश से आग को नियंत्रित करने में मदद मिली।' पूर्वी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गत सितंबर से लगी आग में 33 लोगों की जान जा चुकी है।

इस आग के कारण लाखों जानवर मारे गए। ढाई हजार से ज्यादा घर खाक हो गए। करीब एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र के पेड़-पौधे आग की भेंट चढ़ गए। जंगलों में आग के कारण सिडनी समेत कई शहरों में गंभीर संकट खड़ा हो गया था। अग्निशमन सेवा के उपायुक्त रॉब रोजर्स ने कहा, 'राज्य के दक्षिणी इलाके में अब भी कुछ जगह आग सुलग रही है।' राजधानी कैनबरा के समीप के जंगलों में भी आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई है।

बांधों के ऊपर से बह रहा पानी : कई दिनों की बारिश के चलते न्यू साउथ वेल्स के कई बांध गुरुवार को लबालब भर गए। पानी अब बांधों के ऊपर से बह रहा है। प्रांत की राजधानी सिडनी के समीप स्थित नेपियन बांध में क्षमता से ज्यादा पानी भर गया है। तालोवा और ब्रोगो बांध का भी यही हाल है।

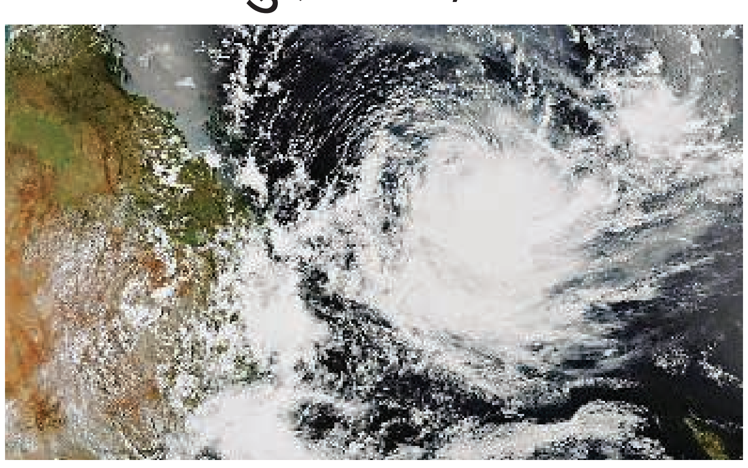

ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर में साइक्लोन उईसी भारी बारिश लेकर आया है। नासा द्वारा जारी एक सैटेलाइट इमेज में इसे देखा जा सकता है। एपी

अमेजन के संस्थापक बेजोस ने 1,176 करोड़ में खरीदा बंगला

सैन फ्रांसिस्को, एएफपी

- लॉस एंजिलिस इलाके में आवासीय परिसर की सबसे बड़ी कीमत

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने लॉस एंजिलिस में 1,176 करोड़ रुपये (16.5 करोड़ डॉलर) से ज्यादा कीमत वाला आलीशान बंगला खरीदा है। वाल स्ट्रीट जरनल में बुधवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक यह क्षेत्र में किसी आवासीय संपत्ति की कीमत का नया रिकॉर्ड है।

समाचार पत्र के अनुसार, बेजोस ने वॉर्नर एस्टेट नामक इस बंगले को मीडिया मुगल डेविड गेफेन से खरीदा है। इससे पहले वर्ष 2019 में मीडिया मुगल कहे जाने वाले रुपर्ट मर्डोक के बेटे लाशन मर्डोक ने बेल-एयर एस्टेट को करीब 15 करोड़ डॉलर में खरीदा था। बेवर्ली हिलबिलीज नामक इस बंगले को वर्ष 1960 के आसपास टीवी शो में दिखाया गया था।

नौ एकड़ में फैला है वार्नर एस्टेट : बेवर्ली हिल्स स्थित वार्नर एस्टेट बंगला नौ एकड़ (3.6 हेक्टेयर) में फैला है। जॉर्जियन स्टाइल में बने इस परिसर में गेस्ट हाउस के अलावा टेनिस कोर्ट और नौ होल वाले गोल्फ कोर्स भी है। इस बंगले का निर्माण मूल रूप से वर्ष 1930 के आसपास जैक वार्नर ने कराया था। वह वार्नर ब्रदर्स के प्रेसिडेंट रहे।

दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं बेजोस : बेजोस की कुल संपत्ति 110 बिलियन डॉलर (करीब 7,841 अरब रुपये) की आंकी गई है। वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते हैं। इनकी डिजिटल सहयोगी एलेक्सा हजारों उत्पादों से जुड़ी है और यह सबसे बड़ी वीडियो सेवा प्रदाता कंपनियों में से एक है। बेजोस अमेरिका के चर्चित समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं।

इराक में नाटो फिर बढ़ाएगा अपनी सैन्य गतिविधियां

ब्रसेल्स, आइएएनएस : उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने इराक में अपनी गतिविधियों को फिर बढ़ाने का निर्णय लिया है। नाटो के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बुधवार को यहां हुई बैठक के बाद संगठन के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि इराकी बलों को प्रशिक्षण देने का काम भी जारी रखा जाएगा।

29 देशों के इस सैन्य संगठन की बैठक में तय किया गया कि इराक में आतंकी संगठन आइएस के खिलाफ जंग लड़ रही अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना पर दबाव कम करने के लिए नाटो सेना अपने अभियानों में तेजी लाएगी। गत तीन जनवरी को अमेरिकी सेना के हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद नाटो सदस्यों ने सुरक्षा के मद्देनजर इराक में तैनात अपने ज्यादातर सैनिकों को वापस बुला लिया था। बगदाद में ड्रोन हमले के बाद अमेरिका का ईरान के अलावा इराक के साथ भी तनाव बढ़ गया था।

ये भी जानिए

मौजूदा भारतीय टीम में इशांत शर्मा को छोड़कर किसी को भी न्यूजीलैंड में ज्यादा टेस्ट खेलने का अनुभव नहीं है। इशांत ने यहां सबसे ज्यादा पांच टेस्ट खेले हैं जबकि विराट कोहली ने यहां मात्र दो टेस्ट खेले हैं।

पृथ्वी और गिल के बीच टीम में जगह बनाने की होड़

दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले आज से भारतीय टीम खेलेगी अभ्यास मैच न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ मुकाबले में नजरें सलामी जोड़ी पर

हैमिल्टन, प्रेट्र: भारतीय टीम शुक्रवार को जब न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच में उतरेगी तो सभी की नजरें सलामी जोड़ी और स्पिनरों पर टिकी होंगी। विराट कोहली की टीम के लिए अगले हफ्ते शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले यह अभ्यास मैच काफी महत्वपूर्ण है। भारत इससे बेहतर अभ्यास मैच की उम्मीद नहीं कर सकता था क्योंकि विरोधी टीम में न्यूजीलैंड के कई सीनियर और ए टीम के खिलाड़ियों को जगह मिली है जिसमें लेग स्पिनर ईश सोढ़ी, आलराउंडर जिम्मी नीशाम और विकेटकीपर टिम सेफर्ट भी शामिल हैं।

न्यूजीलैंड एकादश की टीम में हाल में सीमित ओवरों की सीरीज खेलने वाले स्कॉट कुगलेइनज और ब्लेयर टिकनर भी शामिल हैं जिससे पृथ्वी और शुभमन गिल दोनों को अभ्यास का अच्छा मौका मिलेगा। ये दोनों ही 21 फरवरी से वेलिंगटन में शुरू हो रहे पहले टेस्ट की अंतिम एकादश में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रहे हैं क्योंकि एक ओपनिंग स्पॉट मयंक अग्रवाल के लिए फिक्स है। शुभमन कप्तान को दिखाना चाहेंगे कि वह टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के लिए तैयार हैं। सपाट पिच पर टीम में शामिल दो शीर्ष स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की परीक्षा होगी जिन्हें डेरिल मिशेल, टॉम ब्रूस और सेफर्ट जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ खुद को परखने का मौका मिलेगा। अभ्यास मैच में अच्छा प्रदर्शन करके अश्विन पहले टेस्ट की अंतिम एकादश में जगह बनाने की दौड़ में जडेजा को पछाड़ सकते हैं जो अपनी ऑलराउंड क्षमता के दम पर अभी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। न्यूजीलैंड एकादश में डेन क्लीवर भी शामिल हैं जिन्होंने भारत ए के खिलाफ दो 'टेस्ट' में 196 और 53 रन की पारी खेली। उनके पास चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का एक और मौका होगा। इस मैच को प्रथम श्रेणी का दर्जा हासिल नहीं है जिसका मकसद टीम के प्रत्येक सदस्य को 50 से 100 गेंद खेलने का मौका देना और साथ ही गेंदबाजों को लय हासिल करने में मदद करना है। मेजबान टीम भी आम तौर पर अभ्यास मैच के लिए कमजोर टीम उतारती है जिससे कि मेहमान टीम को अच्छे खिलाड़ियों के खिलाफ खुद को परखने का मौका नहीं मिले लेकिन अच्छे खिलाड़ियों की मौजूदगी में इस अभ्यास मैच के काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 21 फरवरी वेलिंगटन में खेला जाएगा।

मुहम्मद शमी ने नवदीप, अनुष्का और विराट संग यह तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की ● इंस्टाग्राम

भारत: विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), हनुमा विहारी, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मुहम्मद शमी, उमेश यादव, रविचंद्रन अश्विन, रिषभ पंत, नवदीप सैनी और शुभमन गिल।

न्यूजीलैंड एकादश: डेरिल मिशेल (कप्तान), फिन एलन, टॉम ब्रूस, डेन क्लीवर, हेनरी कूपर, स्कॉट कुगलेइनज, जिम्मी नीशाम, रचिन रवींद्र, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनर और विल यंग।

बुमराह को आक्रामक होने और अधिक जोखिम उठाने की जरूरत: जहीर

नई दिल्ली: भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान को लगता है कि जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अधिक आक्रामक होने के अलावा अतिरिक्त जोखिम उठाने की जरूरत है। हाल में वनडे सीरीज में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। पिछले साल स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण चार महीने क्रिकेट से दूर रहने वाले बुमराह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी तीन वनडे खेले, उन्होंने 30 ओवरों में 167 रन दिए लेकिन कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। जहीर ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी बल्लेबाजों को अब बुमराह के खिलाफ खेलने में ज्यादा सतर्क होना होगा जबकि इस तेज गेंदबाज को फॉर्म में वापसी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। जहीर ने कहा कि जब आप ऐसी ख्याति हासिल कर लेते हो जैसे कि जसप्रीत बुमराह ने इतने वर्षों में हासिल की है तो आपको इससे जूझना होता है। उन्होंने कहा कि बुमराह को इसे समझना होगा कि उसे विकेट हासिल करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त आक्रामक होना होगा।

जहीर खान ● फाइल फोटो, प्रेट्र

अनुष्का संग ब्लू स्प्रिंग घूमने गए भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली: अभ्यास मैच से पहले गुरुवार को टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी हैमिल्टन स्थित पुतरू के ब्लू स्प्रिंग घूमने गए। वहां इन खिलाड़ियों ने खूब लुत्फ लिया। बीसीसीआइ ने गुरुवार को इन खिलाड़ियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में टीम के कई खिलाड़ी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में रिद्धिमान साहा, चेतेश्वर पुजारा, रविचंद्रन अश्विन और उमेश यादव नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रिषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ भी यहां घूमने पहुंचे। कप्तान विराट कोहली की पत्नी और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी न्यूजीलैंड पहुंच गईं हैं। वह भी टीम के खिलाड़ियों के साथ पुतरू घूमने पहुंचीं। तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी ने इंस्टग्राम पर तस्वीर शेयर की। इसमें वह टीम के खिलाड़ी नवदीप सैनी और अनुष्का व विराट के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि भारत ने पहले पांच मैचों की टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ किया। वहीं वन-डे सीरीज में टीम इंडिया को 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

पृथ्वी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं: गिल

हैमिल्टन: भारत के प्रतिभावान बल्लेबाज शुभमन गिल ने गुरुवार को जोर देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में सलामी बल्लेबाज के स्थान के लिए उनकी साथी युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है लेकिन अगर उन्हें मौका मिला तो वह इसे बर्बाद नहीं होने देंगे।

यहां न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दोहरा शतक और शतक जड़ने वाले गिल ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। हालांकि 21 फरवरी से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पृथ्वी का दावा भी मजबूत है। भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान के साथ प्रतिस्पर्धा के बारे में पूछे जाने पर गिल ने कहा कि बेशक, हमारे करियर एक ही समय पर शुरू हुए लेकिन कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है।

गिल और शॉ दोनों 20 बरस के हैं और आयु वर्ग के क्रिकेट में ढेरों रन बनाने के बाद उन्हें भविष्य का स्टार माना जा रहा है। न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ शुक्रवार से यहां शुरू हो रहे अभ्यास मैच से पूर्व 20 साल के गिल ने कहा कि हम दोनों ने अपने स्थान पर अच्छा प्रदर्शन किया है। यह टीम प्रबंधन पर निर्भर करता है कि वे किसे खिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच कोई संघर्ष है। जिसे भी मौका मिलता है वह उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा और उसे बर्बाद नहीं होने देगा। गिल पिछले छह हफ्ते से भारतीय-ए टीम के साथ न्यूजीलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेजबान गेंदबाज छोटी गेंद के साथ काफी विकेट लेते हैं विशेषकर नील वैगनर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी पिछली सीरीज देखें, जब विकेट से कोई मदद नहीं मिल रही थी तो वह छोटी गेंदों पर काफी निर्भर थे।

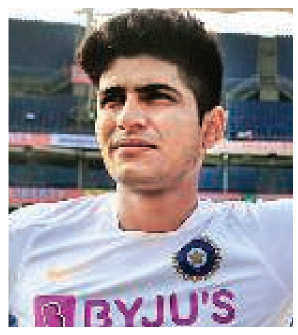

शुभमन गिल ● फाइल फोटो, ट्विटर

गिल ने कहा कि एक बलेबाज के रूप में अगर हम इसे तस्वीर से हटा देते हैं और उन्हें छोटी गेंद पर विकेट नहीं देते हैं तो यह हमारे लिए काफी मददगार होगा। उन्होंने कहा कि यहां हवा काफी महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर जब आप बल्लेबाजी कर रहे हो। गेंदबाज हवा को लेकर काफी योजना बनाएंगे। न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ सीरीज के दौरान हवा के बीच गेंद को लगातार हुक और पुल करना आसान नहीं था। न्यूजीलैंड में अच्छा प्रदर्शन कर चुके गिल को इंग्लैंड में लाल ड्यूक गेंद का सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण लगता है क्योंकि उसमें अधिक स्विंग मिल रही होती है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में गेंद अधिक स्विंग होती है और न्यूजीलैंड की तुलना में विकेट से भी अधिक मूवमेंट मिलती है। न्यूजीलैंड में गेंद भी थोड़ी अलग होती है लेकिन मुझे लगता है कि जहां तक तेज गेंदबाजों का सामना करने का सवाल है तो इंग्लैंड में खेलना चुनौतीपूर्ण है।

सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज में सचिन के सामने होंगे लारा

मुंबई: विश्व क्रिकेट के दो दिग्गज भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा एक नेक काम के लिए एक बार फिर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी टी-20 टूर्नामेंट सड़क सुरक्षा विश्व सीरीज के पहले मैच में आमने सामने होंगे। हाल ही में लारा और सचिन ने ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए हुए चैरिटी मैच में भी भाग लिया था। हालांकि उस मैच में सचिन तेंदुलकर कोच की भूमिका में थे जबकि लारा ने बल्लेबाजी की थी।

यह मैच सात मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया लीजेंड्स और वेस्टइंडीज लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा। गुरुवार को जारी सीरीज के कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट में कुल 11 मैच खेले जाएंगे। इस सीरीज में भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के कुछ बड़े क्रिकेटर हिस्सा लेंगे, जिसमें तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, जहीर खान, ब्रायन लारा, शिवनारायण चंद्रपाल, ब्रेट ली, ब्रेट हॉज, जोंटी रोड्स, मुथैया मुरलीधरन, तिलकरत्ने दिलशान और अजंता मेंडिस शामिल हैं।

आयोजकों के अनुसार इस सीरीज का लक्ष्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस सीरीज के दो मैच वानखेड़े स्टेडियम, चार मैच पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम और चार मैच नवी मुंबई के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 22 मार्च को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में होगा।

मनप्रीत साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

सम्मान

- यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं मनप्रीत
- भारतीय हॉकी टीम के कप्तान को मिले 35.2 प्रतिशत मत

लुसाने, प्रेट्र: राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) का साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इस तरह उनके लिए 2019 का साल यादगार रहा, जहां उनकी अगुआई में भारतीय टीम ने ओलंपिक में भी जगह बनाई। 27 साल के मिडफील्डर मनप्रीत इस तरह 1999 में पुरस्कार शुरू होने के बाद इसे जीतने वाले पहले भारतीय बने। मनप्रीत ने इस पुरस्कार की दौड़ में बेल्जियम के आर्थर वान डोरेन और अर्जेंटीना के लुकास विला को पछाड़ा जो क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

राष्ट्रीय संघों, मीडिया, प्रशंसकों और खिलाड़ियों के संयुक्त मतों में मनप्रीत को 35.2 प्रतिशत मत मिले। वान डोरेन ने कुल 19.7 प्रतिशत मत रहे, जबकि विला ने 16.5 प्रतिशत मत हासिल किए। इस पुरस्कार के लिए बेल्जियम के विक्टर वेगनेज, ऑस्ट्रेलिया के एरन जालेवस्की और एडी ओकेनडेन को भी नामित किया गया था। मनप्रीत ने कहा, 'यह पुरस्कार जीतकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मैं इसे अपनी टीम को समर्पित करना चाहता हूं। मैं अपने शुभचिंतकों और दुनियाभर के हॉकी प्रशंसकों को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पक्ष में मतदान किया। भारतीय हॉकी के लिए इतना अधिक समर्थन शानदार है।' लंदन ओलंपिक 2012 और रियो ओलंपिक 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले मनप्रीत ने 2011 में सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। वह अब तक भारत की ओर से 260 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। मनप्रीत ने कहा, 'अगर आप साल में हमारे प्रदर्शन को देखें तो हमने जिस भी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया उसमें अच्छा किया। जून में एफआइएच सीरीज फाइनल हो या बेल्जियम में टेस्ट सीरीज, जहां हम मेजबान और स्पेन के खिलाफ खेले और उन्हें हराया। 2019 में हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक में जगह बनाना था।' मनप्रीत की अगुआई में भारत ने ओलंपिक क्वालीफायर में रूस को 4-2 और 7-2 से हराकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था।

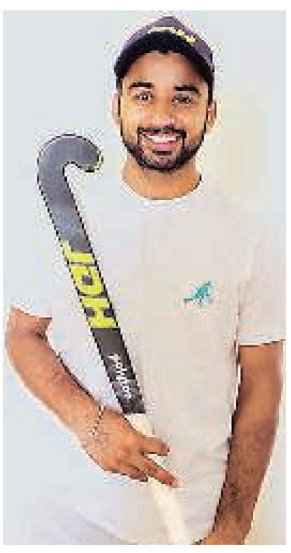

मनप्रीत सिंह ● फाइल फोटो, ट्विटर

विश्व कप फाइनल के बाद जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण: कार्तिक

बोले, अंडर-19 विश्व कप फाइनल में हमारा दिन अच्छा नहीं था

शुभम गोयल ● हापुड़

पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका में हुए अंडर-19 विश्व कप टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने कहा कि विश्व कप का अनुभव अच्छा रहा है। मुझे जब भी मौका मिलेगा, अच्छा करके दिखाऊंगा। फाइनल मैच में बांग्लादेश की टीम के साथ हुए विवाद पर उन्होंने अधिक नहीं बोलते हुए कहा कि अंत में जो भी हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण था।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम शायद टूर्नामेंट में श्रेष्ठ थी। फाइनल मैच में भारत की हार पर कहा कि वह हमारा दिन नहीं था। गांव धनौरा निवासी तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने कहा कि विश्व कप के दौरान नई-नई चीजें सीखी हैं। आगे की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया अब तक मैचों के दौरान अपनाता आया हूं, उसे अपनाऊंगा। आइपीएल की शुरुआत पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही कैंप की शुरुआत होगी। मुझे जब भी मौका मिलेगा, अपना सबसे बेहतर करके दिखाता रहूंगा।

विश्व कप में पाकिस्तान की टीम को हराने पर उन्होंने कहा कि उनके साथ मैच को हमने आम मुकाबले की तरह ही लिया। हम प्रत्येक मैच विश्व कप जीतने के लिए खेल रहे थे। हर मैच को जीतने के बाद हमारा मनोबल भी बढ़ रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले रात में दबाव तो महसूस कर रहा था, लेकिन जीत के बाद वह दूर हो गया। उन्होंने कहा कि विश्व-कप जीतने के लिए हम पिछले दो साल से रात-दिन तैयारी कर रहे थे। अंडर-19 स्तर पर भारत की टीम सबसे कठिन टीम है। हम पसंदीदा टीम भी थे, लेकिन अंतिम दिन कोई भी फैसला हमारे हक में नहीं गया। परिस्थितियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, पर उससे पहले सबकुछ अच्छा रहा था।

क्लार्क का तलाक, पत्नी को देंगे 285 करोड़

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने शादी के सात साल बाद पत्नी काइली से तलाक लेने की घोषणा की है। दोनों ने मई 2012 में शादी की थी और इनकी चार साल की बेटी केल्सी है। ऐसा माना जा रहा है कि क्लार्क ने तलाक के लिए मुआवजे के तौर पर पत्नी को 285 करोड़ रुपये दिए हैं। तलाक के बाद दोनों की तरफ से बयान जारी करके कहा कि कुछ वक्त तक अलग रहने के बाद हमने यह मुश्किल फैसला लिया है। हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है और तय किया है कि अब अलग रहेंगे। हम एक-दूसरे के प्रति काफी सम्मान रखते हैं और आपसी सहमति के साथ ही अलग होने के नतीजे पर पहुंचे हैं। हमने अपनी बेटी का एक-दूसरे के सहयोग से देखभाल करने का फैसला लिया है।

बांग्लादेशी टीम का नायकों जैसा स्वागत: बांग्लादेशी की टीम का आइसीसी अंडर-19 विश्वकप जीतकर स्वदेश लौटने पर बुधवार को नायकों जैसा स्वागत किया और इस दौरान हजारों प्रशंसक सड़कों और स्टेडियम में हम चैंपियन हैं के नारे लगाते दिखे। बांग्लादेश ने रविवार को हुए फाइनल में चार बार के चैंपियन भारत को तीन विकेट से हराकर खिताब जीता था।

बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर आई उड़ान स्थानीय समयानुसार शाम चार बजकर 55 मिनट पर ढाका के मुख्य हवाई अडडे पर उतरी। इस दौरान अधिकारियों, टीम की जर्सी पहने हजारों प्रशंसकों ने स्वागत किया। देश के खेल मंत्री जाहिर अहसन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

दक्षिण अफ्रीका की एक रन की जीत में लुंगी चमके

ईस्ट लंदन (द. अफ्रीका), एएफपी: तेज गेंदबाज लुंगी नगिदी ने अपने अंतिम दो ओवर में तीन विकेट चटकाए जिससे दक्षिण अफ्रीका ने तीन टी-20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ एक रन की रोमांचक जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका के 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय (70) और कप्तान इयोन मोर्गन (52) के अर्धशतकों की बदौलत इंग्लैंड की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अंतिम तीन ओवरों में नगिदी (तीन विकेट) की अगुआई में गेंदबाजों ने पासा पलट दिया। इंग्लैंड ने छह विकेट 24 रन पर गंवाए और टीम नौ विकेट पर 176 रन ही बना सकी। आंदिले फेलुकवायो (दो विकेट) और ब्यूरन हेंड्रिक्स (दो विकेट) ने भी दो-दो विकेट चटकाए। इंग्लैंड को अंतिम ओवर में जीत के लिए सात रन की दरकार थी लेकिन नगिदी ने टॉम कुर्रन और मोइन अली को पवेलियन भेजा। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ पांच रन देकर अपनी टीम को जीत दिला दी। आदिल रशीद अंतिम गेंद पर दो रन लेने की कोशिश में रन आउट हुए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका को कप्तान क्विंटन डिकॉक (31) और तेंबा बावुमा (43) ने पहले विकेट के लिए 26 गेंद में 48 रन जोड़कर तेज शुरुआत दिलाई। बावुमा ने वॉन डेर डुसेन (31) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े।

क्षितिज शर्मा ने खुद को साबित किया

राजस्थान के खिलाफ क्षितिज और कुंवर ने ठोंके शतक नॉकआउट में पहुंचने के लिए दिल्ली की आस कायम

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अधिकतर समय बेंच पर बैठने को मजबूर हुए क्षितिज शर्मा ने इस सत्र के अपने दूसरे रणजी मुकाबले की पहली ही पारी में शतक ठोंककर अपनी प्रतिभा का परिचय तो करवाया ही साथ ही दिल्ली की नॉकआउट दौर में खेलने की उम्मीद को जिंदा रखा।

यहां अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी ग्रुप-ए मुकाबले में क्षितिज (103) और कुंवर बिधूड़ी (111) की पारियों की बदौलत दिल्ली ने राजस्थान के खिलाफ पहली पारी में 623 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। यह दिल्ली का इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इसके जवाब में दूसरे दिन गुरुवार का खेल खत्म होने तक राजस्थान ने अपने चार विकेट 115 रनों पर खो दिए हैं। कप्तान अशोक मनेरिया 38 और राजेश बिश्नोई 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।

दिल्ली ने दिन की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 389 रनों के साथ की थी। पहले दिन नाबाद लौटने वाले क्षितिज शर्मा और कुंवर बिधूड़ी ने अपने-अपने शतक पूरे किए। बिधूड़ी ने 135 गेंदों पर 12 चौके और दो छक्कों की मदद से 111 रन बनाए जबकि क्षितिज ने 212 गेंदों पर 12 चौके और एक छक्के की मदद से 103 रन बनाए। यह क्षितिज का दूसरा प्रथम श्रेणी शतक है। क्षितिज ने दिल्ली की ओर से मौका नहीं मिलने के बाद पिछले सत्र में अरुणाचल प्रदेश के लिए रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। वह इस वर्ष दिल्ली की टीम से खेलने के लिए वापस लौटे। हालांकि अधिकतर समय वह इस सत्र में सिर्फ दो मैचों में ही एकादश का हिस्सा बन सके। इसके बावजूद उन्होंने शानदार प्रतिभा का परिचय दिया। वह अब तक अपने करियर के नौ रणजी मुकाबलों में दो शतक समेत कुल 610 रन बना चुके हैं। वह पिछले सत्र में डीडीसीए की प्रीमियर डिवीजन लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। बिधूड़ी और क्षितिज के बीच सातवें विकेट के लिए 196 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों से पहले हितेन दलाल ने पहले ही दिन 102 रन बना दिल्ली के मजबूत स्कोर की नींव रख दी थी। जोंटी सिद्धू ने 92 रन बनाए।

शतक लगाने वाले दिल्ली के बल्लेबाज क्षितिज शर्मा और कुंवर बिधूड़ी ● सौ. डीडीसीए

जम्मू कश्मीर ने बढ़त बनाई

जम्मू: पदार्पण कर रहे गेंदबाज मुज्तबा यूसुफ के छह विकेट की बदौलत जम्मू कश्मीर ने गुरुवार को यहां रणजी ट्राफी ग्रुप सी मैच के दूसरे दिन हरियाणा के खिलाफ पहली पारी की बढ़त हासिल की। जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में 340 रन बनाए थे। इसके जवाब में हरियाणा की टीम प्रमोद चंदीला के शतक के बावजूद 89.1 ओवर में 291 रन पर सिमट गई जिससे जम्मू कश्मीर ने 49 रन की बढ़त बनाई। हरियाणा ने एक विकेट पर दो रन से आगे खेलना शुरू किया और उसने 66 रन तक चार विकेट गंवा दिए।

हिमाचल के सामने उत्तर प्रदेश के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो

लखनऊ: ऋषि धवन (पांच विकेट) और वैभव अरोड़ा (तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत हिमाचल प्रदेश ने यहां अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के अहम मुकाबले में उत्तर प्रदेश की पहली पारी महज 119 रनों पर समेटकर 101 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद दूसरी पारी में ठोस शुरुआत करते हुए मेजबान टीम के नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक हिमाचल ने तीन विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। आकाश वशिष्ठ 51 और अंकित 16 रन बनाकर नाबाद हैं। मेहमान टीम ने पहली पारी में 220 रन बनाए थे। इस तरह से उत्तर प्रदेश के खिलाफ उसकी कुल बढ़त 283 रनों की हो चुकी है जबकि अभी उसके सात विकेट शेष हैं। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरे हिमाचल के खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास का परिचय दिया और किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई।

मैच फिक्सिंग | **क्रिकेट की छवि को सुधारने में करनी पड़ी जी-तोड़ मेहनत**

फिक्सिंग बम से हिल गया था क्रिकेट जगत

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

क्रिकेट जगत को हिलाकर रख देने वाले मैच फिक्सिंग कांड के मुख्य आरोपी संजीव चावला के ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली पुलिस में ही नहीं क्रिकेट जगत में भी सरगर्मियां बढ़ गईं हैं। 20 साल पहले संजीव चावला द्वारा फोड़े गए फिक्सिंग बम से क्रिकेट जगत हिल गया था।

साल 2000 के मैच फिक्सिंग कांड में तत्कालीन दक्षिण अफ्रीकी कप्तान हैंसी क्रोनिए की संलिप्तता ने दुनियाभर के क्रिकेटरों और इस खेल प्रशंसकों को हिलाकर रख दिया था। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के अलावा इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय क्रिकेट पर पड़ा था। इस मामले के खुलासे के बाद क्रोनिए ने तत्कालीन भारतीय कप्तान मुहम्मद अजहरुद्दीन का नाम लिया था जिसके बाद बीसीसीआइ ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। फिलहाल वह अदालत से बरी हो चुके हैं और इस समय हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। क्रोनिए ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सलीम मलिक, भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा और अजय शर्मा का नाम भी लिया था। जडेजा पर पांच साल और शर्मा पर आजीवन प्रतिबंध लगा था। बीसीसीआइ ने शर्मा पर 2014 में और जडेजा पर 2003 में प्रतिबंध हटा लिया था। इस दौरान मनोज प्रभाकर का भी नाम सामने आया। प्रभाकर पर भी पांच साल का प्रतिबंध लगा था। उन्होंने इस दौरान कपिल देव का नाम बीच में घसीटा लेकिन आरोप झूठे साबित हुआ। कपिल देव इसके बाद फफक-फफक कर रोए थे।

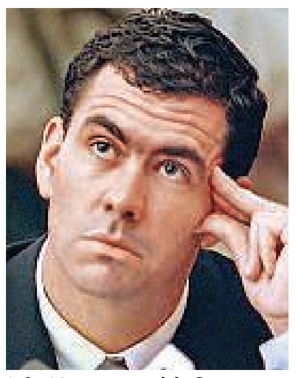

हैंसी क्रोनिए ● फाइल फोटो, ट्विटर

भारतीय क्रिकेट इस कांड से हिल गया था लेकिन सौरव गांगुली ने कप्तान बनने के बाद टीम को अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने फिक्सिंग के जंजाल से तो टीम को निकाला ही साथ ही भारतीय टीम को विदेशों में जीतना सिखाया।

क्रोनिए के फंसने से सब थे स्तब्ध: दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में शुमार हैंसी क्रोनिए को बेहद सभ्य और सीधा कप्तान माना जाता था। जब दिल्ली पुलिस ने संजीव चावला और क्रोनिए के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को इंटरसेप्ट किया तो सब हिल गए। किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हैंसी ऐसा कर सकते हैं। इस बातचीत में दोनों मैच फिक्स करने को लेकर बात कर रहे थे। दोनों के बीच ये बातचीत फरीदाबाद में हुए वनडे मुकाबले से ठीक एक दिन पहले हुई थी। वनडे मुकाबले में क्या होना है इस बात को दोनों पहले ही फिक्स कर चुके थे जिसमें टॉस से लेकर दोनों के बीच हर बात पर चर्चा हो चुकी थी। 2002 में प्लेन क्रैश में हैंसी का निधन हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच को रोक दिया गया। अप्रैल 2000 में दिल्ली पुलिस ने आइपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत संजीव चावला के खिलाफ एफआइआर दर्ज की। इस एफआइआर में क्रोनिए की टीम के साथी खिलाड़ी हर्शल गिब्स, पीटर स्ट्राइडम और निकी बोए का नाम भी शामिल था। इस प्रकरण के बाद बीसीसीआइ और आइसीसी ने फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग रोकने के लिए कई कदम उठाए लेकिन इसकी पूर्ण रोकथाम अब तक नहीं हो पाई है। 2013 में आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग का जिन्न सबके सामने आया जिसमें एस. श्रीसंत सहित कई खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि अदालत में श्रीसंत भी बरी हो गए। हाल ही में कर्नाटक प्रीमियर लीग और तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी कई फिक्सिंग के मामले सामने आए हैं।

मुक्केबाजी कार्यबल की रैंकिंग में शीर्ष पर पंघाल

नई दिल्ली, प्रेट्र: विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल (52 किग्रा) को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आइओसी) के मुक्केबाजी कार्यबल ने अगले महीने होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर से पहले नंबर एक रैंकिंग दी है। अब पंघाल एक दशक से भी अधिक समय में इस श्रेणी में शीर्ष वैश्विक रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं।

ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंदर सिंह 2009 में शीर्ष रैंकिंग हासिल करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे जब उन्होंने विश्व चैंपियनशिप के 75 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक के साथ भारत का खाता खोला था। मुक्केबाजी कार्यबल द्वारा जारी सूची के अनुसार, 24 साल के पंघाल 420 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। यह कार्यबल फिलहाल ओलंपिक खेलों के लिए मुक्केबाजी का संचालन कर रहा है। एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर अगले महीने जॉर्डन के अम्मान में होने हैं।

आइओसी कार्यबल इस साल ओलंपिक क्वालीफायर और फिर टोक्यो में मुख्य स्पर्धा का संचालन करेगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (एआइबीए) निलंबित है। पंघाल 2017 से फॉर्म में हैं। उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में स्वर्ण जीते। पिछले साल वह एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।

नेतृत्व में कमी के कारण सैंडपेपर मसला हुआ : पोंटिंग

सिडनी, आइएएनएस : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का मानना है कि स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली टीम में ना कहने की हिम्मत नहीं थी और इसलिए वह 2018 में केपटाउन में गेंद से छेड़खानी वाले विवाद में फंस गए। पोंटिंग के मुताबिक, न्यूलैंड्स में जो हुआ उसकी जमीन एक साल पहले से तैयार हो गई थी जब उन्हें राष्ट्रीय टीम में सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव की कमी खली थी।

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड में अगर विवाद नहीं होता तो मेरा करियर आगे बढ़ सकता था।
– वर्नोन फिलेंडर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज

फ्रेंच कप के सेमीफाइनल में पहुंचा पीएसजी क्लब

फुटबॉल डायरी ▶ क्वार्टर फाइनल में मेजबान डिजोन को 6–1 से दी शिकस्त, पाब्लो ने दागे दो गोल

डिजोन (फ्रांस), रायटर : पाब्लो सराबिया (56वें और 90+1वें मिनट) के दो गोलों की बदौलत पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने बुधवार को डिजोन को 6-1 से हराकर फ्रेंच कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं, एक अन्य क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक लियोनेस ने मार्सिले को 1-0 से हराया।

मेजबान डिजोन मैच की शुरुआती से ही मुश्किल में नजर आई, जब पहले ही मिनट में वेस्ले लौटोआ आत्मघाती गोल कर बैठे। हालांकि, 12 मिनट बाद मौनिर चौइअर ने गोल दागकर पीएसजी की 1-1 से बराबरी कराई। लीग तालिका में शीर्ष पर काबिज पीएसजी के कायलियन एमबापे ने पहले हाफ के अंत में गोल दागकर हाफटाइम से पहले अपनी टीम को 2-1 से आगे कर दिया।

दूसरे हाफ के पांचवें मिनट में डिफेंडर थिआगो सिल्वा ने पीएसजी की बढ़त को 3-1 कर दिया। स्पेन के सराबिया ने 56वें मिनट में पीएसजी की बढ़त को 4-1 का करते हुए मेजबान टीम की मुश्किलें और बढ़ा दीं। डिजोन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही थीं, क्योंकि 86वें मिनट में उसकी ओर से एक और आत्मघाती गोल हुआ, जो उसके डिफेंडर सेनोउ चौलिबले ने किया। इसके बाद सराबिया ने अतिरिक्त समय में एक और गोल दागकर पीएसजी की 6-1 से जीत सुनिश्चित की। पीएसजी की टीम इतने बड़े गोल के अंतर से मैच जीतने के बाद उत्साहित है।

इंटर मिलान को चौंकाकर नापोली फाइनल के करीब

मिलान : फैबियन रुइज के एकमात्र गोल की बदौलत नापोली ने सैन सिरो में बुधवार को इटालियन कप के सेमीफाइनल के पहले चरण के मुकाबले में इंटर मिलान को चौंकाते हुए 1–0 से जीत दर्ज की। स्पेनिश मिडफील्डर फैबियन ने 57वें मिनट में गोल दागकर गेन्नारो गट्टूसो की टीम नापोली को जीत की राह पर लौटाया, जिसे पिछले सप्ताह के अंत में घरेलू मैदान पर खेले गए लीग मुकाबले में लेचे के हाथों 2–3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। फैबियन ने जियोवन्नी डि लॉरेंजो से मिले पास को रोका और फिर इंटर मिलान के तीन डिफेंडरों को छकाते हुए गोल दागा, जिस पर मिलान के गोलकीपर डेनियल पेडेली भी असहाय नजर आए।

वहीं, एंटोनियो कोंटे की टीम इंटर मिलान ने एसी मिलान को रोमांचक डर्बी मुकाबले में 4–2 से हराकर सीरी ए की तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था, लेकिन नापोली के खिलाफ मुकाबले में कोंटे की टीम सुस्त नजर आई। करीब 60,000 दर्शकों की मौजूदगी में दोनों टीमों के पास पहले हाफ में गोल करने का मौका था, लेकिन दोनों ही टीमें इन्हें भुना नहीं सकीं। इंटर मिलान के लौतारो मार्टिनेज गोल करने से चूक गए।

इकेर के गोल से जीता एटलेटिको बिल्बाओ

बिल्बाओ : कप्तान इकेर मुनिआइन के एकमात्र गोल की बदौलत एटलेटिको बिल्बाओ ने कोपा डेल रे के पहले चरण के सेमीफाइनल में ग्रेनाडा को 1–0 से पराजित किया। दूसरे चरण का सेमीफाइनल मुकाबला पांच मार्च को खेला जाएगा।

27 साल के इकेर को सप्ताह के अंत में ला लीगा में रीयल सोसियाद के खिलाफ 1–2 से मिली अपनी टीम की हार के दौरान रेड कार्ड दिखाया गया था। हालांकि, वह बुधवार को अपनी टीम की जीत के हीरो रहे और हाफटाइम से तीन मिनट पहले इनाकी विलियम्स से मिले पास को उन्होंने गोल में बदलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। गाइज्का गारिटानो की टीम एटलेटिको बिल्बाओ ने पिछले सप्ताह क्वार्टर फाइनल में बार्सिलोना को हराया था और अब वे अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे होंगे, क्योंकि बुधवार को यदि दो गोल ऑफसाइड नहीं होते तो उनकी जीत का अंतर और बड़ा हो सकता था। एटलेटिको बिल्बाओ ने 1930 में रीयल मैड्रिड को 3–2 से हराकर पहली बार कोपा डेल रे का खिताब जीता था। कुल 23 खिताब के साथ वह बार्सिलोना के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

एमबापे के साथ जश्न मनाते पीएसजी के पाब्लो सराबिया। रायटर

नेमार के डोर्टमंड के खिलाफ खेलने पर संशय

डजोन (फ्रांस) : फिटनेस समस्या का सामना कर रहे पीएसजी के नेमार का बोरुसिया डोर्टमंड के खिलाफ अगले सप्ताह चैंपियंस लीग के अंतिम–16 के पहले चरण के मुकाबले के लिए टीम में जगह बनाने को लेकर संशय बना हुआ है। यह जानकारी कोच थॉमस टुशेल ने दी।

दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी नेमार को दो फरवरी को मोंटपिलर के खिलाफ जीत के बाद से पसली की चोट की वजह से तीन मैचों में बाहर बैठना पड़ा था। टुशेल ने फ्रेंच कप के क्वार्टर फाइनल में डिजोन को 6–1 से हराने के बाद कहा, 'मैं नहीं कह सकता कि वह बोरुसिया डोर्टमंड के खिलाफ खेलने के लिए 100 प्रतिशत फिट होंगे।'

1983 का कारनामा दोहरा सकती है महिला टीम : रमन

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

महिला विश्व कप

डब्ल्यूवी रमन। फाइल फोटो

भारतीय महिला टीम के कोच डब्ल्यूवी रमन को लगता है कि उनकी टीम 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप में कपिल देव की अगुआई वाली विश्व कप विजेता टीम का कारनामा दोहराने की क्षमता रखती है। भारतीय महिला टीम 21 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 विश्व कप में अपना अभियान शुरू करेगी। रमन ने कहा कि हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी खिताब जीतने की प्रबल दावेदारों में एक होगी। भारतीय महिला टीम ने कभी भी आइसीसी ट्रॉफी हासिल नहीं की है।

रमन ने कहा कि निश्चित रूप से टीम प्रबल दावेदारों में से एक होगी। उन्होंने 2017 विश्व कप में (उप विजेता रहकर) और 2018 टी-20 विश्व कप (सेमीफाइनल में पहुंचकर) में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद से टीम में फिटनेस, मैदान पर चपलता और बल्लेबाजी रवैये में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले छह महीनों में टीम अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। जब मैं टीम से जुड़ा था, तब को देखते हुए टीम थोड़ी बेहतर और संतुलित हुई है। इन खिलाड़ियों के पास इस विश्व कप में काफी बढ़िया मौका है। रमन ने कहा कि अगर भारत खिताब जीत लेता है तो इससे देश में महिला क्रिकेट को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा कर लेती हैं तो वे शायद वही कर लेंगी जो कपिल देव की विश्व कप विजेता टीम ने 1983 में भारतीय क्रिकेट के लिए किया था। अगर वे इस खिताब को जीत लेती हैं तो सुपरस्टार बन जाएंगी। भारतीय बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए रमन ने कहा कि बल्लेबाजी निश्चित रूप से अच्छी है। वे तकनीकी रूप से अच्छी होने के साथ निडरता से बल्लेबाजी करती हैं। वे तेज गेंदबाजों और स्पिनरों को अच्छी तरह से खेलती हैं और काफी आत्मविश्वास से भरी हैं।

ऑस्ट्रेलिया से विश्व कप का शुरुआती मैच अहम : रोड्रिगेज

सिडनी : भारतीय शीर्ष क्रम की बल्लेबाज जेमिमाह रोड्रिगज 21 फरवरी से यहां शुरू होने वाले टी–20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को बेकरार है और उन्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती मुकाबला उनके करियर के सबसे अहम मैचों में से एक होगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें बुधवार को त्रिकोणीय टी–20 सीरीज का फाइनल खेलने के बाद विश्व कप में खेलेंगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 11 रन से जीत हासिल की थी। राउंड रॉबिन चरण के अपने मुकाबलों में दोनों टीमों ने एक एक जीत हासिल की थी और वेस्टइंडीज में हुए विश्व कप के पिछले चरण में भारत ने ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया था। रोड्रिगज ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मेरे करियर के सबसे अहम मैचों में से एक होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में और वो भी विश्व कप में खेलना मेरे लिए अहम होगा।

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में उससे भिड़ने से रोमांचक कुछ और नहीं हो सकता, इसलिए हम इस मैच को लेकर काफी उत्साहित होंगे। दोनों टीमों में कुछ बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। भारतीय टीम में जहां स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर हैं तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में एलिसे पैरी, मेग लैनिंग और एलिसा हीली जैसी खिलाड़ी हैं जो पिछले साल शानदार फॉर्म में थीं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मेगान स्कट ने भारतीय सलामी बल्लेबाज मंधाना की तारीफों के पुल बांधे जो त्रिकोणीय सीरीज में 43 .20 के औसत से 216 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।

ओडिशा का मजबूत स्कोर

कटक : झारखंड के खिलाफ ओडिशा की टीम ने यहां चार विकेट पर 205 रन से आगे खेलते हुए अपनी पारी 436 रन पर समाप्त की। उसके लिए देबाशीष समंत्र ने 156 रन की पारी खेली जबकि बिप्लब संमत्रे 67 रन में सात रन और जोड़ सके। दिन का खेल खत्म होने तक झारखंड ने दो विकेट पर 71 रन बना लिए थे और कुमार सूरज 42 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे।

उत्तराखंड ने बनाई मैच में बढ़त

बारामती : महाराष्ट्र की टीम यहां पहली पारी के आधार पर उत्तराखंड से पिछड़ गई और दिन का खेल खत्म होने तक महाराष्ट्र ने दूसरी पारी में दो विकेट पर 140 रन बना लिए। उत्तराखंड ने कमल सिंह (101 रन) के शतक से 251 रन बनाए थे। पहली पारी में 207 रन पर सिमटने वाले महाराष्ट्र के लिए अंकित बावने 50 और स्वप्निल फुलपागर 40 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।

बंगाल को 186 रन की बढ़त

पटियाला : शाहबाज अहमद के सात विकेटों की बदौलत बंगाल ने यहां जारी रणजी ट्रॉफी मैच के दूसरे दिन गुरुवार को पंजाब को 151 रन पर ऑलआउट कर दिया। बंगाल ने इसके जवाब में अपनी दूसरी पारी में नौ विकेट पर 199 रन का स्कोर बना लिया है और उसे अब तक 186 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है। बंगाल की टीम के लिए उसकी दूसरी पारी में मनोज तिवारी ने 65, अर्नब नंदी ने 51, आशुतोष मजुमदार ने 26 और श्रीवत्स गोस्वामी ने 24 रनों का योगदान दिया। स्टंप के समय ऋतिक चटर्जी तीन और रमेश प्रसाद छह रन बनाकर नाबाद लौटे। पंजाब की ओर से कृष्ण अलांग ने पांच और सिद्धार्थ कौल तथा विनय चौधरी ने दो-दो विकेट लिए। इससे पहले, पंजाब की टीम अपनी पहली पारी में 151 रन पर ऑलआउट हो गई। पंजाब की टीम के लिए युवा बल्लेबाज रोहन मारवा ने 48, अनमोल मल्होत्रा ने 44 और कप्तान मंदीप सिंह ने 29 रनों का योगदान दिया। बंगाल की टीम के लिए तेज गेंदबाज शाहबाज अहमद ने सात और आकाशदीप सिंह ने तीन विकेट लिए।

एमएस धौनी भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान : सुरेश रैना

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

अनुभवी बल्लेबाज सुरेश रैना का मानना है कि महेंद्र सिंह धौनी भारत के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं। रैना और धौनी आइपीएल में एक ही फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपरकिंग्स के लिए खेलते हैं। धौनी इस टीम के कप्तान भी हैं।

'द सुपर किंग्स शो' के दौरान रैना ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कप्तान था जिसने भारतीय टीम को बदलकर रख दिया। अब यही हमारे ड्रेसिंग रूम में भी है।' धौनी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं लेकिन इस 38 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज के सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। दो बार विश्व खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान रहे धौनी इंग्लैंड में 2019 विश्व कप से भारत के बाहर होने के बाद से ब्रेक पर हैं। धौनी के 23 मार्च से शुरू हो रहे आइपीएल में वापसी करने की उम्मीद है जहां वह सीएसके की कप्तानी का जिम्मा संभालेंगे। सीएसके की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा, 'इस साल हमारी टीम में पीयूष हैं। जोश हेजलवुड, सैम कुर्रन और तमिलनाडु के साई किशोर हैं। हमारे पास युवाओं और सीनियर खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है।'

विविध

जाली आधार व पैन कार्ड बनाने वाले गिरोह का बदमाश दबोचा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ 35 जाली आधार कार्ड और 27 पैन कार्ड हुए बरामद

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाली आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपित कपूर सिंह दहिया रोहिणी सेक्टर-15 के रहने वाला है और पहले भी अपहरण, लूट, हत्या के प्रयास और रंगदारी के करीब डेढ़ दर्जन मामलों में वांछित है। उसके पास से 35 जाली आधार कार्ड, 27 जाली पैन कार्ड, पांच मतदाता पहचान पत्र, 20 मोबाइल, 17 चैक बुक, 31 सिमकार्ड, 13 डेबिट कार्ड, कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

डीसीपी संजीव कुमार यादव ने बताया कि टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के वांछित बदमाशों की धरपकड़ के लिए स्पेशल सेल की एक टीम काम कर रही थी। जांच के दौरान यह पता चला था कि गिरोह का एक बदमाश कपूर सिंह दहिया रोहिणी इलाके में छिपा हुआ था। मामले में आगे यह भी पता लगा कि वह भगोड़ा घोषित है। टिल्लू गिरोह का यह बदमाश कई तरह से अपराधियों की मदद करने के साथ विभिन्न बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने में भी शामिल था। वह हमेशा अवैध हथियार से लैस रहता है। 12 फरवरी को टीम को सूचना मिली कि कपूर सिंह दहिया कार से एक सहयोगी से मिलने के लिए दिल्ली के द्वारका, धूलसिरस चौक इलाके में आने वाला है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने कपूर सिंह दहिया को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा एक कारतूस बरामद किया गया। उनकी कार की तलाशी लेने पर बड़ी संख्या में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए।

पूछताछ में उसने बताया कि हरियाणा में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद वह 1995 में दिल्ली आ गया। उसने कुछ केबल कंपनियों की दुकान पर काम किया और बाद में दिल्ली के धीरपुर गांव में अपना केबल टीवी नेटवर्क बनाया। इस दौरान वह टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के एक बदमाश काला उर्फ मीता के संपर्क में आया। उसके जरिये वह गिरोह के अन्य सदस्यों के संपर्क में आया। उसने गिरोह को रुपयों से भी मदद करना शुरू किया। 2018 में वह रोहिणी के मुकेश जुनेजा के संपर्क में आया जो जाली दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों व फाइनेंस कंपनियों से लोन लेता था। केबल का काम ठीक न चलने के कारण वह मुकेश के साथ जाली आधार कार्ड व पैन कार्ड बनाने लगा। असली कार्ड में किसी और की फोटो लगाकर ऐसे जाली दस्तावेजों से नए सिम कार्ड खरीदता था। इन जाली आईडी का प्रयोग करके कई बैंकों में खाते खोले।

तीस हजार के लिए खत्म कर दिया ममेरे भाई का परिवार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली में दंपती और तीन बच्चों की हत्या का आरोपित गिरफ्तार

▶ फुफेरे भाई ने दिया वारदात को अंजाम, रॉड से किया वार

दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिल दहला देने वाले हत्याकांड को महज तीस हजार रुपये की देनदारी से बचने के लिए अंजाम दिया गया। पुलिस ने मृतक शंभूनाथ के फुफेरे भाई प्रभुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बेरहमी से रॉड मारकर महज चार घंटे में महिला समेत तीन बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद घर के मुखिया को शराब के नशे में धुत किया और उसकी भी निर्मम हत्या कर दी। आरोपित ने बताया कि वह उधार के 30 हजार रुपये लौटा नहीं पा रहा था। इसलिए, उसने पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल रॉड को बरामद कर लिया है। शुक्रवार को जीटीबी अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम होगा।

पूर्वी जिले के जिला पुलिस आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि 12 फरवरी को दोपहर में पुलिस को सूचना मिली कि सी ब्लॉक गली नंबर-11 के एक घर से बदबू आ रही है। पुलिस पहुंची तो घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पुलिस ताला तोड़कर अंदर गई। वहां दो कमरों में एक ही परिवार के पांच शव पड़े हुए थे। शवों की पहचान शंभूनाथ, उनकी पत्नी सुनीता, दो बेटों सचिन और शिवम और एक बेटी कोमल के रूप में हुई। परिवार मूल रूप से बिहार के सुपौल जिले के मलहनी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी और कॉल डिटेल से प्रभु के बारे में पता चला। आरोपित शंभूनाथ के घर से थोड़ी दूरी पर ही किराये पर रहता है। पुख्ता सुबूत मिलने पर पुलिस ने उसे गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया।

आलोक कुमार ने बताया कि लग रहा था कि कई लोगों ने वारदात को अंजाम दिया होगा, लेकिन आरोपित ने अकेले ही एक-एक करके पांचों की हत्या की थी। शव 10 दिन से कमरे में पड़े हुए थे।

ऐसे पकड़ा गया आरोपित

पुलिस ने शंभूनाथ के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें आखिरी कॉल प्रभुनाथ की थी। गली में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में प्रभुनाथ घर पर ताला लगाकर जाते हुए दिखा। पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और गुनाह कबूल कर लिया।

महिला से कहासुनी के बाद की हत्याएं : पुलिस पूछताछ में प्रभुनाथ ने बताया कि तीन फरवरी को दोपहर में उसने शंभूनाथ को फोन कर पैसों के लेनदेन के मामले में लक्ष्मी नगर में बुलाया और खुद साढ़े तीन बजे उसके घर जा पहुंचा। उस वक्त शंभूनाथ की पत्नी सुनीता घर पर अकेली थी। सुनीता ने उससे उधार के रुपये मांगे और मना करने पर खरी खोटी सुनाई। इससे नाराज प्रभुनाथ ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने घर में पड़ी रॉड उठाई और सुनीता के सिर पर मारता रहा। इसके बाद वह घर में ही बैठा रहा। कुछ देर बाद सुनीता की बेटी कोमल ट्यूशन से घर पहुंची। प्रभुनाथ ने उसकी भी रॉड से हत्या कर दी। इसके बाद बड़ा बेटा शिवम् ट्यूशन से घर पहुंचा। आरोपित उसे भी मार डाला। कुछ देर बाद दूसरा बेटा सचिन पहुंचा। आरोपित ने उसकी भी रॉड मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वह घर का मुख्य दरवाजा बंद कर बाहर चला गया। शंभूनाथ को फोन कर गामड़ी गांव में बुलाया और दोनों ने बैठकर खूब शराब पी। शाम साढ़े सात बजे उसे उसके घर लेकर गया और अंदर जाते ही उसका गला दबा दिया। शंभूनाथ पर भी उसने कई बार रॉड मारा। नृशंस हत्याकांड के बाद वह मुख्य द्वार पर बाहर से ताला लगाकर अपने घर पर चला गया।

एक हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआइ जांच पर रोक

नईदुनिया, बिलासपुर

▶ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सभी पक्षों को नोटिस

छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में कागजी संस्था के नाम पर समाज कल्याण विभाग में हुए करीब एक हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले की सीबीआइ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानूमति, जस्टिस एस अब्दुल नजीर व जस्टिस एएस बोपन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सभी पक्षों को नोटिस भी जारी किए हैं। इस मामले में सात आइएएस सहित करीब 12 अधिकारी आरोपित हैं। हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआइ को जांच के आदेश दिए थे।

प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें घपले की सीबीआइ जांच के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सात आइएएस व पांच राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों पर आरोप लगाया था। हालांकि, सीबीआइ ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग के संविदा कर्मचारी कुंदन सिंह ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर समाज कल्याण विभाग में फर्जी एनजीओ बनाकर एक हजार करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया था। इसमें उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम से हासिल दस्तावेज भी दिए थे। राज्य निःशक्तजन स्रोत संस्थान के नाम पर प्रदेश के सात आइएएस व पांच राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों की सूची पेश कर फर्जीवाड़ा में संलिप्तता होने की बात कही थी। हाई कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद 30 जनवरी को आरोपित अधिकारियों के खिलाफ सात दिन के भीतर एफआइआर दर्ज करने और समाज कल्याण विभाग से समस्त दस्तावेज जब्त करने के निर्देश सीबीआइ को दिए थे।

चीफ जस्टिस ने गठित की थी स्पेशल बेंच

डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ पूर्व आइएएस बीएल अग्रवाल व राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारी सतीश पांडेय ने चीफ जस्टिस के कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन ने स्पेशल बेंच का गठन करते हुए जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू को सुनवाई के निर्देश दिए थे। दोनों पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद स्पेशल बेंच ने खारिज कर दिया था । यही नहीं शासन की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी।

पूर्वजों का नाम बनेगा सिंधी समाज की पहचान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर

▶ बंटवारे के बाद भारत आए पूर्वजों को सम्मान देने का अभियान

भारतीय सिंधु सभा ने पूर्वजों को सम्मान देने की नायाब पहल की है। सभा भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद यहां आए सिंधी समाज को प्रेरित करेगी कि वे अपने नाम के आगे पूर्वजों का नाम जोड़ें। ऐसा करने का मकसद पूर्वजों को सम्मान देने के साथ समाज की भी पहचान बनाना है।

सभा का मानना है कि बंटवारे ने सिंधी समाज को जो दर्द दिया, वह उनकी ताकत बन चुका है। उस दर्द को ताजा रखने और बंटवारे के बाद भारत आए पूर्वजों को सम्मान देने के लिए कदम बढ़ाया गया है। दरअसल समाज के लोग अभी तक अपने नाम के आगे जो टाइटिल लगाते हैं, वह पूर्वजों के नाम पर तो जरूर है, लेकिन पूरी पहचान वाला नहीं मानते। साथ ही टाइटिल बंटवारे के बाद आए पूर्वजों की स्मृतियों से भी जुड़ी नहीं है।

गिरमिटिया कर चुके हैं यह प्रयोग

भारत से गिरमिटिया मजदूरों के रूप में मारीशस गए लोग यह प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाकर पूर्वजों का नाम जोड़ा और आज वही नाम उनकी पहचान है।

समाज के तमाम लोग आज भूल गए हैं कि बंटवारे के बाद उनके जो पूर्वज यहां आए थे, उनका नाम क्या था। सभा यह पहल इसीलिए कर रही है कि लोगों को उनके पूर्वजों के बारे में पता चले और वह उनको पूरा सम्मान दें, जिनके संघर्ष से वह भारत में स्थापित हुए। जैसे किसी का नाम राजेश सावलानी है और दादा–परदादा जो बंटवारे के बाद भारत आए थे, उनका नाम पूरन था, अब राजेश पूरन नाम होगा।
– राजेश नेभानी, अध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा

नोएडा में रेलवे के अवैध तत्काल ई–टिकट बेचने वाले दो लोग दबोचे

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

सॉफ्टवेयर से आइआरसीटीसी की वेबसाइट को हैक कर रेलवे के तत्काल ई-टिकट बेचने वाले दो लोगों को गाजियाबाद आरपीएफ ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। आरोपित फर्जी आइडी से चार हजार से ज्यादा ई-टिकट बेच चुके हैं। आरपीएफ ने आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

आरपीएफ को सूचना मिली थी कि नोएडा में बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से ई-टिकट बेच रहे हैं। आरपीएफ ने बुधवार को नोएडा सेक्टर-17 मेट्रो स्टेशन के पास भूम नेट जोन नामक दुकान पर छापेमारी की। यहां से आरपीएफ ने अवैध रूप से ई-टिकट बेच रहे सुरेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने टिकट बुक करने के लिए आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर 12 फर्जी आइडी बना रखी थीं। इसके पास से सात ई-टिकट बरामद हुए हैं। इसके बाद आरपीएफ ने नोएडा के सेक्टर-27 अट्टा मार्केट में निखिल टेलीकॉम नामक दुकान पर छापा मारा। यहां से आरपीएफ ने गुड्डू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया।

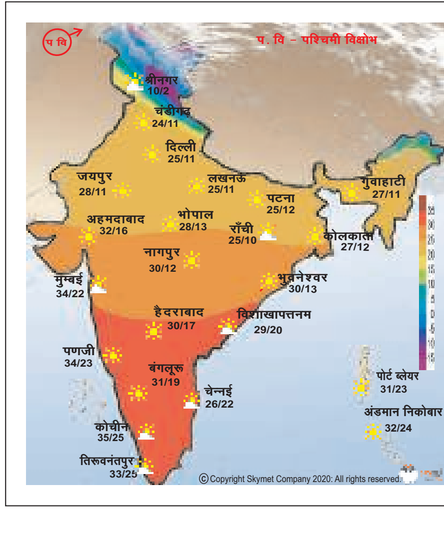

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बादल छाये रहेंगे तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा व बर्फबारी होगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुष्क मौसम जारी रहेगा। दिन के समय मध्यम गति की हवाएं प्रभावित करेंगी। सुबह ठंडी व शीतल बनी रहेगी।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/23/आंबा	अहमदाबाद	29/09/सा
कोलकाता	27/12/सा	बड़ौदा	31/11/सा
चेन्नई	33/25/सा	नागपुर	30/13/सा
हैदराबाद	30/18/सा	इन्दौर	30/15/सा
बंगलूरू	31/20/सा	राँची	26/11/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/24/सा	पटना	24/12/सा
गुवाहाटी	22/13/सा	जमशेदपुर	28/11/सा
गंगटोक	14/05/सा	पुणे	31/16/सा

अस्तित्व में आई वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट यूट्यूब

ऑनलाइन भुगतान कंपनी पे-पल के तीन पूर्व कर्मी चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने वीडियो शेयरिंग के लिए आज ही 2005 में यूट्यूब को तैयार किया। 23 अप्रैल 2005 को इस पर पहला वीडियो डाला गया। 2006 में गूगल ने 1.65 अरब डॉलर में इसका अधिग्रहण किया।

जीपीएस के पहले सेटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया

अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए तैयार किए गए प्रथम सेटेलाइट को आज ही 1989 में भेजा गया था। विभाग ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के 24 सेटेलाइट तैयार किए थे। 1990 तक ये सुविधा आम लोगों के लिए भी उपलब्ध थी।

अभिनय और सौंदर्य का अप्रतिम मिश्रण थीं मधुबाला

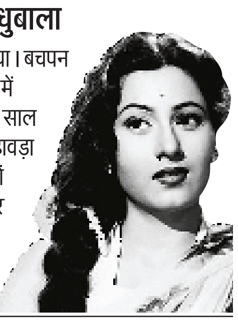

मधुबाला का जन्म 1933 में आज ही दिल्ली में हुआ था। बचपन का नाम मुमताज जहां देहलवी था। छह साल की उम्र में परिवार के साथ मुंबई आईं। बतौर बाल कलाकार नौ साल की उम्र में पहली फिल्म बसंत की थी। मिस्टर एंड मिसेज 55, हावड़ा ब्रिज, काला पानी और मुगल ए आजम जैसी ऐतिहासिक फिल्मों समेत करीब 21 फिल्मों में काम किया। अपनी मौत तक परिवार की अकेले कमाने वाली सदस्य रहीं। 23 फरवरी 1969 को भारतीय सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ गईं।

वायु प्रदूषण से दुनिया को प्रतिवर्ष 2.9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान

पेरिस, एएफपी : जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले वायु प्रदूषण से दुनिया को प्रतिदिन करीब आठ अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। यह लागत वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.3 प्रतिशत है। एक पर्यावरणीय अनुसंधान समूह ने अध्ययन में यह दावा किया है।

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) और ग्रीनपीस साउथ ईस्ट एशिया की रिपोर्ट में तेल, गैस और कोयले से होने वाले वायु प्रदूषण के नुकसान का आकलन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण से चीन में प्रतिवर्ष होने वाले नुकसान की लागत 900 अरब डॉलर, अमेरिका में 600 अरब डॉलर और भारत में 150 अरब डॉलर है।

वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 45 लाख मौतें: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) ने बताया है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की चपेट में प्रतिवर्ष दुनियाभर में 45 लाख लोगों की मौत होती है। चीन में जहां 18 लाख तो भारत में 10 मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। अधिकतर मौतें हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और तीव्र श्वसन संक्रमण से होती हैं। हाल ही के अध्ययनों में यह सामने आया था कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहने का मतलब 10 सिगरेट के बराबर धुंआ ग्रहण करना है।

उचित कदम उठाकर कम कर सकते हैं नुकसान : ग्रीनपीस ईस्ट एशिया में क्लीन एयर के कैंपेनर मिनवू सोन ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से होने वाला वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के साथ आर्थिक तंत्र के लिए भी खतरा है। इससे लाखों लोगों की जान जाती है, लेकिन यह ऐसी समस्या नहीं है जिससे निजात नहीं पाया जा सकता है। ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन को छोड़कर नवीकरणीय स्रोतों को शामिल करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को नाइट्रोजन डाईऑक्साइड से 350 अरब डॉलर का नुकसान होता है। नाइट्रोजन डाईऑक्साइड भी जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाली प्रमुख गैस है।

पीएम 2.5 की स्थिति सबसे खतरनाक : शोधकर्ताओं ने बताया कि पीएम 2.5 की स्थिति सबसे खतरनाक है। इसकी वजह से प्रतिवर्ष दुनिया में दो ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है।

पीएम 2.5 की वजह से पांच साल से कम उम्र वाले 40,000 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। करीब बीस लाख बच्चों का जन्म समय से पहले होता है। पीएम 2.5 कण फेफड़ों में गहराई से प्रवेश करते हैं और रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे हृदय और स्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। डब्ल्यूएचओ ने इन्हें कैंसर के कारक के रूप में पाया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.3 प्रतिशत है नुकसान की यह लागत। प्रतीकात्मक

विकसित से लेकर विकासशील देशों में स्थिति भयावह

वायु प्रदूषण का प्रभाव विकसित से लेकर विकासशील देशों में एक जैसा ही है। इसकी वजह से सालाना जहां यूरोपीय यूनियन के देशों में 3,98,000 लोगों की मौत तो अमेरिका में 2,30,000 लोगों की मौत होती है। वहीं बांग्लादेश में 96,000 तो इंडोनेशिया में 44,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

2070 तक पौधे व जंतुओं की तिहाई प्रजातियां खत्म हो जाने का खतरा

स्पेक्ट्रम

वाशिंगटन, प्रेट्र: जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनियाभर में 2070 तक जंतुओं और पौधों की एक तिहाई प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगी। एक अध्ययन में इस बात का दावा किया गया है। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ एरीजोना के शोधकर्ताओं ने आने वाले 50 सालों में जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का आकलन किया है। शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन से वर्तमान में पड़ रहे प्रभाव, भविष्य को लेकर किए गए विभिन्न अनुमानों के आधार पर यह आकलन किया है।

'पीएनएएस' नामक पत्रिका में प्रकाशित उनके परिणाम दुनियाभर में सैकड़ों प्रजातियों के पौधों और जंतुओं पर सर्वेक्षण पर आधारित है। शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में दुनियाभर की 581 साइटों पर 538 प्रजातियों के डाटा का विश्लेषण किया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि एक से ज्यादा साइटों पर 44 प्रतिशत प्रजातियां पहले से ही विलुप्ति की कगार पर हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा तापमान भी पौधों और जंतुओं के विलुप्ति के लिए जिम्मेदार है। शोधकर्ताओं ने बताया कि अगर अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो 50 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना है। वहीं, अगर अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो 95 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर आ जाएंगी।

इधर-उधर की

एक महिला और 130 पालतू बिल्लियां

मॉस्को, एजेंसी : मॉस्को में एक कॉलोनी के लोग पास के अपार्टमेंट से आ रही अजीब दुर्गंध से इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने कारण का पता लगाने के हर संभव प्रयास कर डाले। पता चला कि फ्लैट में महिला ने 130 बिल्लियां पाल रखी थीं। ये सिलसिला चार साल पहले शुरू हुआ था। जानवरों का रखरखाव करने वाली एनास्तसिया सोलोविएवा ने कहा, अभी तक पचास बिल्लियों को दूसरा घर उपलब्ध कराया जा चुका है। करीब 130 अभी फ्लैट में मौजूद हैं। एक दिन रास्ते में इनको एक बिल्ली मिली, जिससे ही ये कुनबा बढ़ा। हालांकि महिला अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उन बिल्लियों के भोजन का प्रबंध करती थीं लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। सोशल मीडिया के जरिए इन बिल्लियों के लिए धन जोड़ा जा रहा है ताकि उनके भोजन और आवास की व्यवस्था हो सके।

प्रत्येक वर्ष मंगल में बनता है खारा पानी

शोध ▸ अमेरिका के वैज्ञानिकों का दावा, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में ही पिघल जाती है बर्फ

इस ग्रह पर प्रत्येक साल होती है यह घटना, कुछ समय के लिए ही बनता है पानी

▸ मंगल पर माइनस 128 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तापमान, कार्बन डाईऑक्साइड भी जाती है जम

▸ लाल ग्रह पर पानी की खोज के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं वैज्ञानिक, लगाए जा रहे आकलन

वाशिंगटन, प्रेट्र: मंगल ग्रह की सतह पर वर्ष में एक बार कुछ दिनों के लिए खारे पानी का निर्माण होता है। एक अध्ययन में यह दावा किया गया है। अमेरिका में प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने बाताया कि हालांकि, इस लाल ग्रह पर तरल पानी का आना मुश्किल है। क्योंकि, बर्फ अपने पिघलने के बिंदु तक पहुंचने से बहुत पहले वातावरण में फैलकर विलुप्त हो जाती है।

वरिष्ठ वैज्ञाकि नॉबर्ट शॉर्गोफर ने बताया कि मंगल ग्रह में बर्फ से भरपूर ठंडे क्षेत्र भी मौजूद हैं और बिना बर्फ वाले गर्म क्षेत्र भी। ठंडे और बर्फ से भरपूर क्षेत्रों में तापमान कभी भी स्वीट पॉइंट पर नहीं होता। जिससे की बर्फ पिघल सके। स्वीट पॉइंट उस तापमान के उस बिंदु को कहते हैं, जिसमें बर्फ पिघलने लगती है और तरल दृव्य बनता है। शोधकर्ताओं ने बताया कि मंगल के बर्फीले क्षेत्रों में तापमान के स्वीट पॉइंट तक पहुंचना असंभव है।

एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि मंगल की सतह पर मध्य अक्षांश में एक बोल्डर (ऊंची पहाड़ी) स्थित है। इस वजह से इस पहाड़ी की छांव वाला हिस्सा अधिकतम ठंडा होता है। इसके पीछे हमेशा बर्फ जमी रहती है।

जब सूर्य वसंत के मौसम में मंगल पर फिर से उगता है तो यहां की बर्फ गर्म होती है। विस्तृत माडल गणना में शोधकर्ताओं ने पाया कि तापमान माइनस 128 डिग्री सेल्सियस से दोपहर के समय माइनस 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। एक चौथाई दिन में ही इतना बड़ा बदलाव हो जाता है। माइनस दस डिग्री भी वह तापमान नहीं होता जहां पर पानी (एचटूओ) तरल अवस्था में मिल सके, लेकिन शोधकर्ताओं ने बताया कि नमक युक्त सतह पर बर्फ के तरल अवस्था में बदलने का तापमान बिंदु घट जाता है। इसलिए माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में खारा दृव्य बनता है, लेकिन यह स्थिति कुछ समय के लिए होती है। मंगल पर हर साल यही प्रक्रिया होती है। बोल्डर की छांव वाली जगह इनती ठंडी होती है कि न केवल पानी बल्कि कॉर्बन डाईऑक्साइड भी जम जाती है।

एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किया गया अध्ययन। प्रतीकात्मक

पानी के त्रिगुण बिंदु के बराबर है मंगल का दाब

मंगल ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पानी के अणुओं (एचटूओ) के त्रिगुण बिंदु के करीब ही होगा। त्रिगुण बिंदु उस स्थिति को कहा जाता है, जिस पर कोई पदार्थ तरल, ठोस और गैसीय अवस्था में संतुलित मात्रा में मौजूद होता है। शुद्ध पानी का त्रिगुण बिंदु 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है।

पहले भी हो चुके लाल ग्रह में पानी मिलने के दावे

शोधकर्ता इससे पहले भी मंगल पर तरल दृव्य के अस्तित्व का पता लगाने का दावा किया है। इस ग्रह के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अमेरिका और रूस ने लैंडर और ऑर्बिटर भेजे हैं। इसके साथ ही जापान, भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ऑर्बिटर भेजे हैं। भारत का पहला मंगल मिशन 'मंगलयान' पहली बार में मंगल पर जाने में सफल रहा था। अभी तक मंगल पर पानी मौजूद होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है।

कहानियों में माफी से ज्यादा आनंद देता है बदला

वाशिंगटन, प्रेट्र: बदलते वक्त के साथ सोच भी बदली है। मौजूदा समय में कहानियों में बुरे लोगों को सजा मिलने पर लोगों को आनंद आता है। अमेरिका के द ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक बुरे लोगों को माफी मिलने पर लोग खुश नहीं होते हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक और सहायक प्रोफेसर मैथ्यू ग्रिजार्ड ने बताया कि अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश लोग बुरे लोगों को माफी देने वाली कहानियों का आनंद नहीं लेते हैं, लेकिन वे इसे दंड की तुलना में अधिक सार्थक और प्रेरक पाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे बुराई का मार्ग छोड़ने का रास्ता निकलता है। मैथ्यू का यह भी कहना है कि जब गलत काम करने वाले को तय सजा से अधिक सजा मिलती है तो और भी मजा आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत काम करने पर माफी देने वाली कहानियों की लोग सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं, लेकिन इसे आनंददायक नहीं मानते। जर्नल कम्यूनिकेशन में इस अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। कुल 184 छात्रों पर किए गए इस अध्ययन में उन्हें छोटी कहानियां दी गई थीं और कहा गया था कि इसका इस्तेमाल टीवी सीरियल में किया जाएगा।

लंबे पुरुषों को डिमेंशिया का खतरा होता है कम

लंदन, प्रेट्र : याददाश्त और निर्णय लेने जैसी दिमागी क्षमता खोने की बीमारी डिमेंशिया का खतरा लंबे कद के पुरुषों में कम होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगेन के शोधकर्ताओं द्वारा यह नतीजा डेनमार्क के छह लाख से अधिक लोगों के डाटा का अध्ययन के बाद निकाला गया है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने डेनमार्क में 1939 से 1959 के बीच जन्मे लोगों के बीच आगे चलकर सामने आए डिमेंशिया के लक्षणों से संबंधित डाटा का अध्ययन किया। शोध को ईलाइफ जर्नल में प्रकाशित किया गया है।

डिमेंशिया से पीड़ित पुरुषों को ध्यान में रखकर किए गए इस अध्ययन से पता चला कि औसत लंबाई के ऊपर हर एक छह सेंटीमीटर का कद बढ़ने के साथ आगे चलकर डिमेंशिया होने का खतरा करीब दस फीसद घट गया। बीमारी पर कद की लंबाई का असर सगे भाईयों के बीच भी देखा गया। शोध में शामिल प्रोफेसर मेरेटे ओस्लर ने बताया कि डिमेंशिया के खतरे से बचने में लंबाई के अलावा शिक्षा व बुद्धिमता को भी प्रभावी कारक के रूप में देखा गया है। हालांकि इससे बचने वाले लोगों में कद काठी के लंबे होने का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया गया।

फोटो न्यूज

स्पाइडर मैन दे रहा सफाई की सीख

स्पाइडरमैन की पोशाक में साफ-सफाई का संदेश देने वाले रूडी हार्टोनो नामक शख्स अपनी अनोखी पहल से लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इंडोनेशिया के एक कैफे में कर्मचारी रूडी दक्षिणी सुलावेसी प्रांत के पारे-पारे में तटीय इलाकों से कचरा हटाते हैं। उनका कहना है कि पहले बिना पोशाक के यह काम किया तो लोगों ने खास तवज्जो नही दी, लेकिन स्पाइडर की पोशाक में सफाई करते देख लोग मदद के लिए जुट जाते हैं। कचरे से निपटने के खास इंतजाम नहीं होने से यह देश की विकट समस्या विकट हो चुकी है। रायटर

मस्तिष्क का विकास तेज करता है स्तनपान

शोध अनुसंधान

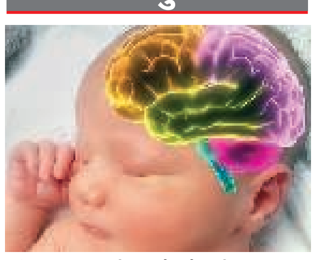

मां का दूध शिशुओं के लिए अमृत माना जाता है। इससे ना सिर्फ उनका सही विकास बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी होता है। अब शोधकर्ताओं का कहना है कि स्तनपान का शिशुओं के मस्तिष्क के विकास पर भी असर पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, मां के दूध में ऑलिगोसैकराइड 2 एफएल नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यह ज्ञान संबंधी क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देता है। यह निष्कर्ष 50 माताओं और उनके शिशुओं पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। एक से छह माह की अवधि के दौरान स्तनपान करने वाले शिशुओं के दो साल का होने पर मस्तिष्क के विकास का आकलन किया गया था। अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता पेगी बर्जर ने कहा, 'यह कार्बोहाइड्रेट पहले दो साल के दौरान मस्तिष्क के ज्ञान संबंधी हिस्से के विकास के लिए अहम होता है।' -आइएएनएस

हर हफ्ते हरियाली वाली जगह पर जाने से स्वस्थ रहेगा आपका तन और मन

स्वस्थ तन और मन में प्रकृति की भी अहम भूमिका होती है। लेकिन तेजी से बढ़ते इमारतों के जंगल के कारण पेड़-पौधे कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से सेहत संबंधी कई दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। एक अध्ययन में पाया गया है कि हफ्ते में एक दिन हरियाली वाली जगह पर जाने वाले लोग खुद को प्रकृति से जुड़ा महसूस करते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। ब्रिटेन की प्लेमाउथ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार, यह भी पाया गया है कि प्रकृति के बीच जाने वाले लोग पर्यावरण की सेहत को बेहतर करने वाला बर्ताव भी कर सकते हैं। अपनी तरह के इस पहले अध्ययन में प्रकृति से जुड़ाव और मानव स्वास्थ्य के बीच जुड़ाव पर गौर किया गया। शोधकर्ताओं ने उन लोगों पर अध्ययन किया, जो हरियाली वाली जगहों का दौरा करते हैं। -प्रेट्र

स्क्रीन शॉट

मेरा हर गाना दिल से निकलता है : इरशाद कामिल

सात सवाल

गीतकार इरशाद कामिल द्वारा लिखे हालिया रिलीज फिल्म 'शिकारा' व 'कबीर सिंह' के 'बेखयाली' सहित कई गाने लोकप्रिय हुए हैं। आज रिलीज हुई फिल्म 'लव आज कल' में उनके लिखे हां मैं गलत... और शायद... जैसे कई गानों को पसंद किया जा रहा है। लफ्जों के जरिए दिल का पैगाम लिखने वाले इरशाद कामिल से बातचीत :

● गाना लिखते हुए आपके दिमाग में क्या चलता है?

- गीतकार और कवि अपने आप में ही बहुत रोमांटिक होते हैं। मैं जब किसी फिल्म के लिए गाना लिखता हूं तो थोड़ी देर के लिए उसके किरदार के साथ रोमांटिक जोन में चला जाता हूं। इससे मेरे लिए उस परिस्थिति के गाने लिखना थोड़ा आसान हो जाता है।

● फिल्म 'कबीर सिंह' का गाना 'बेखयाली' पिछले साल के बेहतरीन रोमांटिक गानों में से एक था। उसे कैसे लिखा?

- कबीर सिंह के निर्देशक संदीप वांगा बहुत खुले विचारों के व्यक्ति हैं। इस फिल्म के ज्यादातर गाने मैं ही लिख रहा था। उन्होंने मुझसे इस फिल्म में ब्रेकअप के सीन पर चर्चा की। उन्होंने मुझसे कहा कि दो प्यार करने वाले एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। गाने में रोमांस के साथ कबीर सिंह के किरदार को ऊपर उठाने की ऊर्जा भी हो। गाने की पंक्तियां 'ये जो लोगबाग हैं, जंगल की आग हैं' आज के युवा के गुस्से और भड़ास को दिखाती हैं। इस गाने को भले ही अभिनेता के नजरिए से दिखाया गया हो, लेकिन गाना समाज की वजह से अलग हुए दोनों प्रेमियों के दिलों में लगी आग को दर्शाता है।

● 2014 के वेलेंटाइन डे पर रिलीज हुई फिल्म 'गुंडे' का गाना 'तूने मारी एंट्रियां' भी काफी लोकप्रिय हुआ था, इसके पीछे की क्या कहानी है?

- इस फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर के साथ मैंने 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'टाइगर जिंदा है' और 'भारत' जैसी कई फिल्मों में काम किया है। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल है। इस फिल्म में दो दोस्त एक ही लड़की के दीवाने होते हैं। यह गाना बनाते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि गाने में लड़की के लिए दोनों लड़कों का रोमांस खुलकर दिखना चाहिए। उनकी मांग थी कि भाषा अच्छी होने के साथ गाने में किरदारों की गुंडई भी दिखनी चाहिए। ये बातें ध्यान में रखकर मैंने यह गाना लिखा।

● कोई गाना लिखने में आपको कितना वक्त लगता है?

- कोई तय समय सीमा नहीं है। कितना समय और कितनी मेहनत लगेगी, यह गाने के जज्बात पर निर्भर करता है। कभी-कभी एक गाना दो दिन में ही पूरा हो जाता है तो कभी-कभी पूरा सप्ताह भी लग जाता है। मैं किसी गाने को तब तक वक्त देता हूं, जब तक गाने में मनचाहे जज्बात नहीं आ जाते हैं।

● गाना लिखते हुए निजी भावनाओं का कितना इस्तेमाल करते हैं?

- मेरे सभी गानों में थोड़ा-बहुत नहीं, बल्कि पूरी भावनाएं निजी होती हैं। हर गाना मेरे दिल से निकलता है और दिलों तक पहुंचता है। मेरे और सुनने वालों के बीच में कान नहीं आता हैं। यह दिल का रिश्ता है और दिल से ही समझा जा सकता है।

● वैलेंटाइन डे को लेकर आपकी कैसी यादें रही हैं?

- अपनी भावनाएं लोगों तक पहुंचाने का यह अच्छा दिन है। लेकिन भावनाओं का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि किसी वैलेंटाइन डे पर मुझे भी सौ-दो सौ चाहने वालों की तरफ से गुलाब का फूल मिले। मैं किसी को अपने गाने और कविताओं से इंप्रेस करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि मैं व्यक्तित्व को जानना ज्यादा बेहतर समझता हूं। दीपेश पांडेय

राजकुमार ने पत्रलेखा के लिए लिखा प्रेम-पत्र

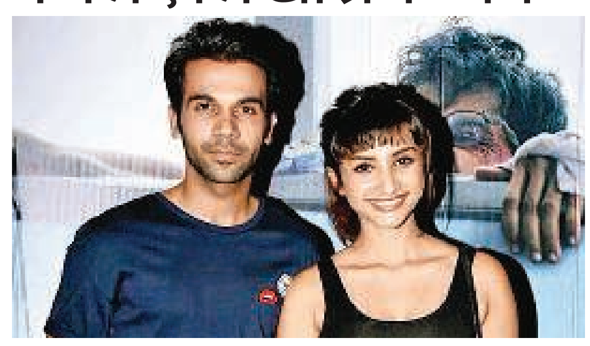

वैलेंटाइंस डे के मौके पर अभिनेता राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के लिए प्रेम-पत्र लिखा और अपने दिली जज्बात साझा किए। पिछले नौ साल से दोनों रिलेशन में हैं। राजकुमार ने लिखा, 'प्रिय पत्रलेखा, यह मुहब्बत का महीना है और मैं प्यार तथा इसे जाहिर करने वाले शब्दों और संकेतों के बारे में सोच रहा था। कई रोमांटिक किरदार निभाने के बावजूद मेरे जेहन में प्यार के कई 'स्वीकृत' भावों और इशारों पर सवाल उठता है कि हम इसे कैसे महसूस करते हैं और वास्तव में यह कैसा होता है। इसे लेकर लोगों में बहुत नासमझी है, इसे बहुत बुरा-भला भी कहा गया है। मुझे इसकी फिक्र है। हम अक्सर 'प्यार में पागल' और 'प्यार में अंधा' जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है। क्योंकि तुममें मुझे जो प्यार दिखा है, वह मेरे लिए कहीं ज्यादा है। इससे मुझे विश्वास मिलता है कि हम दोनों का साथ जबर्दस्त ताकत हैं।' राजकुमार ने यह भी बताया कि वे दोनों जीवन में बिना किसी फैंसी डेट और महंगे तोहफों के एक साथ रहे।

माधुरी के चेहरे पर खुशी की वजह हैं डॉ. नेने

वैंलेटाइन्स डे प्यार का जश्न मनाने का दिन है। हर कोई अपने तरीके से इस दिन को मना रहा है। बात की जाए अगर माधुरी दीक्षित नेने की तो उनका मानना है कि उनके और उनके पति श्रीराम नेने के लिए हर दिन वैंलेटाइन्स डे होता है। माधुरी ने बताया कि दोनों प्रत्येक दिन एक-दूसरे की खुशी के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। माधुरी के मुताबिक, उनके पति डॉ. नेने बेहद रोमांटिक हैं। उनके चेहरे पर जो खुशी नजर आती है, वह उन्हीं की वजह है। माधुरी दीक्षित नेने के मुताबिक, यह दिन हर तरह के प्यार को मनाने का दिन है। प्यार माता-पिता के लिए भी होता है। माधुरी के अनुसार, वह खुद अपने बच्चों से कहती हैं कि हर दिन मदर्स और फादर्स डे होता है। उन्होंने बताया कि उनके मन में उनके माता-पिता और सास-ससुर के लिए प्यार एक जैसा है। ये सारी बातें माधुरी दीक्षित ने गुरुवार को मुंबई में फिल्म 'गन्स ऑफ बनारस' के ट्रेलर लॉन्च पर कहीं। यह पहली बार था, जब माधुरी किसी फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंची थीं। इसकी वजह थे उनके मैनजर रह चुके राकेश नाथ और उनकी हिट फिल्मों 'साजन', 'याराना', 'सैलाब' की लेखिका रह चुकी रीमा राकेश नाथ, जिनके बेटे करण नाथ इस फिल्म में लंबे अरसे बाद नजर आएंगे। यह फिल्म धनुष अभिनीत तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक होगी।

68 हाथियों में चुना गया 'हाथी मेरे साथी' का 'उन्नी'

राणा डग्गुबाती अभिनीत तमिल फिल्मकार प्रभु सोलोमन की हिंदी फिल्म 'हाथी मेरे साथी' का टीजर बुधवार को रिलीज किया गया। इंसान और हाथियों के रिश्ते तथा हाथी दांत की तस्करी पर आधारित इस फिल्म में काम कर रहे मुख्य हाथी का नाम उन्नी है। उन्नी के चुनाव के बारे में निर्देशक प्रभु बताते हैं कि आंध्र प्रदेश में लगभग 68 हाथी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सरकारी मान्यताप्राप्त प्रशिक्षित हाथियों के साथ काम करने की अनुमति थी। उनके पास सिर्फ तीन हाथियों का विकल्प बचा था। अंततः उन्नी का चयन किया गया। फिल्म में 'बाहुबली' फेम अभिनेता राणा डग्गुबाती महावत की भूमिका में हैं।

उनके मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्होंने 30 किग्रा वजन घटाया है। फिल्म को हिंदी, तेलुगु और तमिल में बनाया जा रहा है। राणा का कहना है कि वह हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु और तमिल चारों भाषाएं बोल लेते हैं, पर सोचते सिर्फ तमिल व अंग्रेजी में हैं। 'हाथी मेरे साथी' में पुलकित सम्राट, श्रेया पिलगांवकर व जोया हुसैन भी हैं। फिल्म 2 अप्रैल को रिलीज होगी।